हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 2000

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

वीरवार, 15 मार्च, 2000

	पृष्ठ संख्या
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
पंचायत चुनावों के लिए अध्यापकों को प्रतिनियुक्त करने संबंधी	(7)1
वक्तव्य--	
शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी	(7)1
उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी घोषणा	(7)4
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(7)4
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/गैर-सरकारी संकल्प की सूचनाएं	(7)5
वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7)6
वाक-आउट	(7)36
वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)36
वैयक्तिक स्पष्टीकरण--	
श्री बलबीर पाल शाह द्वारा	(7)46

मूल्य :

97 C

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)47
शोक प्रस्ताव	(7)73
वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)74
वाक-आउट्स	(7)81
वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)81
उपाध्यक्ष का चुनाव	(7)89
वर्ष 2000-2001 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(7)92

© Pu by

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

बीरवार, 15 मार्च, 2000

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

पंचायत चुनावों के लिए अध्यापकों को प्रतिनियुक्त करने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention notice given of by Shri Karan Singh Dalal regarding deputing the teachers for Panchayat Elections. I admit it. Shri Karan Singh Dalal may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पंचायत चुनावों में शिक्षण अमले की चुनाव में ड्यूटी लगाने के कारण हरियाणा राज्य के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है तथा बच्चों की परीक्षाएं भी प्रभावित होने की संभावना है।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

वक्तव्य—

शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Education may make a statement.

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बहादुर सिंह) : इस बारे में निवेदन है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-12-1999 एवं आदेश दिनांक 21-2-2000 को प्रकाश में आई 2000 की विशेष राहत याचिका क्रमांक 1598-1599 एवं 2000 की विशेष राहत याचिका क्रमांक 1629-30, 1717-18 एवं 1705-1706 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि राज्य सरकार तथा राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों, जिला परिषदों एवं नगर पालिकाओं आदि के चुनाव फरवरी, 2000 के अन्त तक करवायें। राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में 2000 की 772-73 एवं 2000 की 774-779 सिविल अपील दायर करते हुये इस उद्देश्य से प्रार्थना की थी कि विधानसभा भंग होने के कारण जो चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी और जिसके लिये चुनाव की तिथि 22 फरवरी 2000 निश्चित की जा चुकी थी, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फरवरी, 2000 तक पंचायत समितियां आदि के चुनाव करवाये जाने संभव नहीं थे इसलिये इस उद्देश्य के लिये और अधिक समय दिये जाने की आवश्यकता थी। संबंधित पक्षों को

[श्री बहादुर सिंह]

सुनने के पश्चात माननीय उच्चत् न्यायालय ने यह निर्देश दिये कि राज्य सरकार तथा राज्य चुनाव आयोग द्वारा जहां-जहां भी चुनाव करवाये जाने हों वहां पर ग्राम पंचायत आदि के चुनाव 31 मार्च, 2000 को या इससे पूर्व करबाये जायें। उक्त आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिये थे कि राज्य एवं चुनाव आयोग नगर परिषद आदि के चुनाव भी करवायें और जहां-जहां चुनाव करवाये जाने आवश्यक हों, वहां पर चुनाव प्रक्रिया 07 अप्रैल, 2000 तक पूर्ण कर ली जाये। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 161 के तहत ऐसे चुनाव कराये जाने का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की उपरोक्त व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां नोटिस आदि जारी करना और तदानुसार चुनाव करवाना आवश्यक था ताकि दिनांक 31-3-2000 तक पंचायत समितियों आदि के चुनाव सम्पन्न करवाये जा सकें तथा दिनांक 07-04-2000 तक नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न करवाये जा सकें।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 169 में निम्नलिखित प्रावधान है :—

धारा 169 : राज्य सरकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग को आवश्यकतानुसार मतदान सूची तैयार करने एवं चुनाव संबंधी अन्य कार्यों के लिये कर्मचारी उपलब्ध करबायेगी।

इसी अधिनियम की धारा 179 के अनुसार राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध करवायेगी जितने आयोग को चुनाव संबंधी कार्यों के लिये चाहियें। हर कर्मचारी उन निर्देशों का पालन करेगा जो उससे आयोग या आयोग द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिये जायेंगे।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्य चुनाव आयोग को इसकी आवश्यकतानुसार सभी सहायता दे। राज्य सरकार को 12 मार्च तथा 16 मार्च को करबाये जाने वाले पंचायत चुनावों के लिये कर्मचारी लगाने हेतु सभी तरह की आवश्यकतायें पूरी करनी थीं।

विधानसभा एवं लोक सभा चुनावों में अध्यापकों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी हमेशा लगाई जाती है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 185 के अन्तर्गत प्रावधान है कि इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारी को बिना उचित कारण के अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को निभाने का दोषी पाया गया तो उसे इस दोष के लिये सजा के रूप में जुर्माना लगाया जायेगा जो कि 2000 रुपये तक हो सकता है। जिला चुनाव अधिकारियों/राज्य चुनाव आयोग की आवश्यकतानुसार राज्य शिक्षा विभाग को चुनाव ड्यूटी करने के लिये विद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों के नाम भेजने पड़ते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि विद्यालय की आंतरिक परीक्षायें तथा बोर्ड की परीक्षायें पहले ही शुरू हो चुकी हैं और अध्यापन कार्य नहीं हो रहा है। महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आरम्भ होंगी और वहां तीन सप्ताह की परीक्षा तैयारी की छुट्टियां चल रही हैं और कक्षा अध्यापन का

कार्य नहीं है। इस प्रकार पंचायत चुनावों के कारण विधार्थियों की पढ़ाई पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है। पंचायत चुनाव 12 तथा 16 मार्च को निश्चित होने के कारण बोर्ड की परीक्षायें जो पहले 11 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च को निर्धारित थीं उन्हें पुनः निर्धारित किया गया है। आंतरिक परीक्षायें भी इसी के अनुसार पुनः निर्धारित की गई हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप इस बारे में दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : ठीक है सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसे इसलिए संतोषजनक नहीं माना जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार को पहले से ही इस बारे में मालूम था। पंचायतों के चुनाव पहले भी करवाए जा सकते थे लेकिन इसके पीछे इनका यह ध्येय था कि कहीं इन चुनावों को पहले करवाने से विधान सभा के चुनाव पर असर न पड़े। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से गलत दलीलें दी गई, इसके लिए सरकार को सख्त फटकार लगी।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरा आपके माध्यम से इनको कहना है कि ये विषय तक सीमित रहें। इन्होंने अध्यापकों की पंचायत इलैक्शन में ड्यूटी के बारे में कॉल टैंशन मोशन दी थी। इसमें फलाने को फटकार लगी। यह नहीं था। कोर्ट अन्तिम निर्णय दे चुका है। कोर्ट में अपनी बात को लेकर हर आदमी जा सकता है। हाई-कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गवर्नमैंट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दे दिया, उसको हमने माना है। अब ये अपने प्रश्न से बाहर जाकर बात कहें यह ठीक नहीं है। इन्होंने जो कॉल अटैंशन मोशन दी है, उससे सम्बन्धित प्रश्न ही पूछें।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, किसको फटकार लगी किसको नहीं लगी इस बात को छोड़ कर आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने यह माना है कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव करवाए जाने जरूरी थे। हरियाणा में हमारे और भी कर्मचारी हैं क्या अध्यापकों को उनसे अलग नहीं रखा जा सकता था ? वे दूसरे अधिकारियों को बुला सकते थे। मेरा अभिप्राय है कि हरियाणा में जो स्टूडैंट्स हैं, अध्यापकों की ड्यूटी लगने की वजह से उनको बहुत नुक्सान हुआ है। हरियाणा में शिक्षा की स्थिति पहले ही खराब है। हरियाणा में परीक्षाएं चली हुई हैं और अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाकर चुनावों की ड्यूटी में लगे हुए हैं। मैं इनसे इस बारे में जानना चाहता हूं ?

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन चुनावों में अध्यापकों की ही नहीं बल्कि हर डिपार्टमैंट के कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि आन्तरिक परीक्षाएं और बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी थीं इसलिए अब अध्यापन कार्य नहीं हो रहा था। अतः परीक्षाओं की तैयारियों में अध्यापकों की ड्यूटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भये हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं। (विघ्न) मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि यह मेरी बात का ठीक से जबाब क्यों नहीं दे सके ? राज्य में बहुत से अधिकारी हैं इसलिए क्या यह जरूरी था कि शिक्षकों की ही इन चुनावों में ड्यूटी लगायी जाती ? अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस बात की कोई चिन्ता ही नहीं की। जबकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे बच्चे नौवीं या दसवीं एवं उससे आगे की पढ़ाई के लिए स्कूलों में और कॉलेजों में जाते हैं उन्हें परीक्षाओं के दौरान शिक्षकों की विशेष जरूरत होती है। क्योंकि उन्होंने

[श्री कर्ण सिंह दलाल]
उनसे इस बारे में विचार-विमर्श करना होता है, पूछताछ करनी होती है। सरकार ने उनकी ड्यूटी चुनावों में लगाकर बहुत बड़ी कोताही की है। इनको इन चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए थी। अगर इन्होंने इस बारे में सही तरीके से विचार किया होता तो राज्य के दूसरे अधिकारियों की इन चुनावों में ड्यूटी लगायी जा सकती थी ? अध्यक्ष महोदय, जब परीक्षाफल आएगा तब आप इसका नुक्सान देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जब इम्तहानों के बाद हरियाणा में परीक्षाफल आता है वह वैसे ही कम होता है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। पहले जो इनकी सरकार थी उसने ही स्टेट चुनाव आयोग का गठन किया था। ये चुनाव करवाने का काम उसी स्टेट चुनाव आयोग का है। अध्यक्ष महोदय, पहले जो चुनाव की तिथि निर्धारित हुई थी वह 12 और 19 तारीख की हुई थी। चूंकि 19 तारीख को होली थी इसलिए त्यौहार के दिन को देखते हुए ये चुनाव पहले करवाए गए। स्टेट गवर्नमैंट का काम तो सिर्फ यह है कि चुनाव आयोग को जिन-जिन चीजों की जरूरत होती है, उसकी वह पूरा करती है। चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए जितने कर्मचारी चाहिएं, उतने स्टेट गवर्नमैंट उनको प्रोवाइड करवाती है इसलिए इस विषय को इतना लम्बा चौड़ा बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। आखिर चुनाव तो होंगे ही। इनमें कौन-कौन से कर्मचारी हों, इसका फैसला करना चुनाव आयोग का काम है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो अभी रह ही गया है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपके दोनों क्वैश्चंज हो गये हैं। आप सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। आपका मोशन मान लिया गया था और आपने अपने क्वैश्चंज भी पूछ लिए हैं इसलिए अब आप बैठें। (विघ्न)

उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी घोषणा

Mr. Speaker : Under Rule 10(i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly, I fix today, the 15th March, 2000, as the date for the election of Deputy Speaker. This item will be taken up today later on.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 30.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 16th March, 2000.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 16th March, 2000.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से उस दिन संपत सिंह जी से निवेदन किया था कि आप नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि नये-नये सदस्य चुनकर आए हैं कोई अपना बिल रखना चाहता है कोई अपना प्रस्ताव रखना चाहता है। हरियाणा प्रदेश की कई समस्याओं पर चर्चा होनी है उस दिन भी चौधरी संपत सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो उस पर जरूर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक प्रस्ताव दिया था कि हरियाणा में लड़कियों को मां-बाप की संपत्ति में से जो हिस्सा मिलता है वह शादी के बाद नहीं मिलना चाहिए, इससे हमारे गांवों का भाई-चारा बिगड़ता है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपको कोई सजैशन देना हो तो दें, आप तो भाषण देने लगते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट न करें और जो प्रस्ताव मैंने दिया हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कल कोई विशेष बिजनेस नहीं है और आज भी आपको बजट पर अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

Question is—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 16th March, 2000.

The motion was carried.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएं

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी सेवा में हमारे एक सीनियर मैम्बर कैप्टन अजय सिंह ने कॉल अटैंशन मोशन दी हुई हैं आज आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा कि उन्हें रद्द कर दिया या उस पर कोई बात होगी या नहीं ?

Mr. Speaker : The Calling Attention notice No. 4 regarding suspension of disbursement of loan from World Bank has been sent to Government for comments. The Calling Attention notice No. 3 regarding abolishing of 29 Municipal Committees has been disallowed. The Calling Attention notice No. 7 regarding the pollution in Dharuhera Industrial Complex is under consideration.

श्री अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आप तो ऐसे विहेव करते हैं जैसे मैं क्रॉस चुनकर आया हूं। आप हमारे कस्टोडियन हैं।

श्री अध्यक्ष : यह पौल्यूशन आपको कई दिन से नजर आता होगा या आज ही नजर आया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संपत सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव सदन की समीक्षा के लिए मैंने रखा है कि लड़कियों को उनकी शादी के बाद बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलना चाहिए उसके बारे में भारत सरकार से आप निवेदन करें कि कानूनों में तबदीली हो।

Mr. Speaker : Your Calling Attentiion Notice No. 2 regarding mixing of sewerage water into the drinking water in Palwal City has been admitted for tomorrow, the 16th March, 2000. लड़कियों के जायदाद के हिस्से के बारे में जो नान-आफिशियल रैज़ोलूशन है उसे हम पहले ही डिसअलाऊ कर चुके हैं उसे आप अगले सैशन में दें, फिर उस पर विचार होगा। इसके अलावा मैं हाउस को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हरियाणा विधान सभा के इतिहास में यह पहला अवसर है जब सदस्यों को सबसे ज्यादा बोलने का मौका दिया गया। इससे पहले आज तक गवर्नरज़ ऐड्रस पर अधिकतम 33 सदस्य बोले थे और अब की बार 45 सदस्य बोले हैं। जनवरी 1998 में गवर्नरज़ ऐड्रस पर उस समय का सबसे ज्यादा समय 13 घंटे 32 मिनट चर्चा के लिए दिया गया था। इस सत्र में 13 घंटे 53 मिनट का समय दिया गया है जोकि सर्वाधिक है। जिसमें से अपोजीशन बैंचेज को 432 मिनट का समय दिया गया और ट्रेजरी बैंचेज को 401 मिनट का समय दिया गया। इसके अतिरिक्त बजट पर भी बोलने का मौका दिया जाएगा।

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the general discussion on Budget for the year 2000-2001 will take place.

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बजट पर हो रही बहस पर बोलने का समय दिया है। कल माननीय वित्त मंत्री जी ने चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की नई सरकार का नया बजट पेश किया। जब वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो उस समय वे बहुत निराश थे और उनके साथ-साथ ट्रेजरी बैंचिज के सदस्य भी निराश थे। हमेशा यह प्रथा रही है कि जब वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करते हैं तो उनकी पार्टी के सदस्य और सहयोगी पार्टी के सदस्य उनका स्वागत करने के लिए अपनी मेजें थपथपाते हैं। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। जब माननीय चौधरी भजन लाल जी ने याद दिलाया तब जाकर इन्होंने मेजें थपथपाई थी, वरना बिल्कुल चुपचाप बैठे थे।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मांगे राम गुप्ता जी ने कहा कि सरकारी पक्ष के सदस्य निराश बैठे थे। इसमें निराशा की कौन सी बात थी क्योंकि जब बजट पेश होना होता है उससे पहले किसी सदस्य को यह मालूम नहीं होता कि बजट में क्या है। क्योंकि यह तो सिक्रेट डोक्यूमेंट होता है उसके लिए पहले से थंपिंग कैसे कर सकते हैं Even every announcement was appreciated and welcomed by you people also. जब पार्टी की कंट्रीब्यूशन की कोई बात होगी तो उस वक्त जरूर थंपिंग करेंगे। पढ़ते वक्त जब माननीय सदस्यों को पता लगा कि यह तो बढ़िया बजट है तभी इन्होंने बजट का वैलकम करना शुरू कर दिया था। इसके लिए हर पार्टी की तरफ से स्वागत किया गया। चौधरी भजन लाल जी ने भी चलते समय यह कहा था कि बहुत बढ़िया बजट पेश किया गया है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी भी कहता हूं कि सरकार ऐसे जितने अच्छे काम करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे ताकि हमें जल्दी मौका मिल सके। अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी काफी पुराने और सीनियर सदस्य हैं और काबिल भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब वित्त मंत्री जी बजट पढ़ने के लिए सदन में खड़े होते हैं तो सभी सदस्य तीन मिनट तक मेजें थपथपाते रहते हैं चाहे पार्लियामेंट हो या राज्य की विधान सभा हो। लेकिन कल वित्त मंत्री जी इस सदन में बजट ऐसे पढ़ रहे थे जैसे किसी गांव के चौक पर खड़े होकर भाषण दे रहे हों।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। इन्होंने थम्पिंग इसलिए नहीं की क्योंकि यह बजट ओपन बजट नहीं था बल्कि सीक्रेट बजट था और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने ठीक फरमाया था कि यह बजट सिक्रेट बजट था और लोगों को इसके बारे में पहले पता नहीं था। लेकिन पिछले कई सालों से इस सदन की ऐसी प्रथा हो गई थी कि जिस दिन वित्त मंत्री महोदय का बजट पेश होता था उस दिन इस हाउस में हरियाणा के लोगों को यह बजट दिखाने के लिए टी०वी० सैट लगाए जाते थे। परन्तु कल मुख्य मंत्री महोदय ने इसका इंतजाम नहीं करवाया क्योंकि इस बजट में हरियाणा के लोगों के लिए कुछ रखा ही नहीं गया और हरियाणा के लोग यदि इस बजट को देखते तो सरकार को गालियां देते। वित्त मंत्री महोदय ने दिल से यह बात कह डाली कि हमने पहली बार बजट को वैब साइट पर दिखाने के लिए 3 सी०डी० तैयार की हैं जिसमें से एक सी०डी० मुख्य मंत्री महोदय को दी जाएगी और एक स्पीकर महोदय को दी जाएगी और तीसरी सी०डी० विरोधी पक्ष के नेता को दी जाएगी। ये कम्प्यूटर पर उस सी०डी० को देख लें उसमें आम जनता के लिए कुछ बजट नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चुनावों की बात तो नहीं करता लेकिन चुनावों से पहले व्यापारी वर्ग को इस सरकार से बड़ी उम्मीदें थी कि यह सरकार उनको कुछ रियायतें देगी गवर्नरज़ ऐड्रैस पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए इन्होंने हरिजनों की कन्याओं को दी जाने वाली सुविधाओं की बात की लेकिन हरियाणा का किसान बड़ा निराश था, उन किसानों को मुख्य मंत्री महोदय ने एक बात कह रखी थी कि जो बी०जे०पी० वाले मेरे साथ काम कर रहे हैं वे मुझे अच्छी तरह से काम नहीं करने देते इसलिए मैंने चुनाव करवाए हैं और अब की वार मैं ये कांटा निकाल दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप ये बातें पहले भी बोल चुके हैं, आप कृपया बजट पर बोलें।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुप्ता जी गलत बात कह रहे हैं ।मुख्य मंत्री महोदय ने कभी इस प्रकार की बात नहीं की। ये अपनी बात छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। विधान सभा में गलत बात कहना ठीक नहीं है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब कोई सदस्य बजट पर बोल रहा हो तो वह बजट के पैसे की बात कर सकता है, कानून और व्यवस्था की बात कर सकता है और विकास की बात कर सकता है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये विकास की बात करें इनको कौन रोकता है ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो तीन सी०डी० दी हैं, एक मुझे भी दी है और एक आपको भी दी है क्या इससे बजट की सीक्रेसी लीक नहीं हो जाएगी।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ऐसे तो यह बजट टाइप भी हुआ है और प्रिंट भी हुआ है (शोर)। अध्यक्ष महोदय, 9.30 बजे से पहले कहीं पर भी इस बजट की कोई भनक लगी हो, इसका एक शब्द, एक लाइन या एक भी आंकड़ा लीक हुआ तो हम उसके लिए जिम्मेवार हैं (इस समय मेजें थपथपाई गई) (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय की बात से सहमत होता हूं कि इस बजट की कोई सीकरेसी लीक नहीं हुई। जो बात मानने वाली है मैं उसको मानता हूं लेकिन ये जो तीन सी०डी० दी गई हैं इनका क्या महत्व है। यह जो ओपन बजट पेश हुआ है। यह बजट हमारे हाथ में भी आ गया है, सी०डी० में देख लें, किताब में पढ़ लें इसमें आम जनता को विशेष कर हरियाणा के किसान को जिनको उम्मीद थी कि यह जो ओम प्रकाश चौटाला जी सरकार बनी है अपने बजट अधिवेशन में उनको कोई विशेष पेकेज देगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया है और इसी कारण से इस बजट को टी०वी० 10.00 बजे पर दिखाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। क्योंकि बजट में दिखाने को कुछ है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा छोटी सी स्टेट है और मौजूदा सरकार ने 294.56 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया है तथा आने वाले साल में 97.79 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है और वित्तमंत्री जी कहते हैं कि हमने कोई कर नहीं लगाया। अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी ओर कितना कर लगायेंगे ये तो लक्की हैं कि इंटर स्टेट्स में एक समान कर प्रणाली भी इन्हीं की सरकार के समय में लागू हो गई। कांग्रेस की सरकार के वक्त में जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय हमने यह प्रपोजल रखा था और इस बारे में हमारी एक नहीं 10 मीटिंग हुई थी। लेकिन मौजूदा सरकार इस बात के लिए लक्की है कि यह स्कीम इनकी सरकार के समय में लागू हो गई और एक समान कर प्रणाली लागू होने से सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा के अंदर 75 करोड़ रुपये के टैक्स लगे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रणाली के लागू होने से 75 करोड़ के नहीं बल्कि 150 करोड़ रुपये के टैक्स लगे हैं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक समान कर प्रणाली के अंदर हमने तीन चीजों को नहीं लिया। फर्टीलाईजर, डीजल, पैस्टीसाईड और इनसैक्टीसाईड के ऊपर हमारी सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाये। क्योंकि ये तीनों ही चीजें किसानों से संबंधित हैं। अगर हम इन पर भी एक समान कर प्रणाली के तहत टैक्स बढ़ा देते तो जरूर हमें 150 करोड़ रुपये का फायदा होता। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों की तरफ देखते हुए, इनके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया। (विघ्न एवं शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी यह तो मान रहे हैं कि 75 करोड़ रुपये का फायदा इनको हुआ है लेकिन 75 करोड़ रुपये के जो ये टैक्स इनको लगे हुए मिल गये इनको ये नये टैक्स के रूप में बताना नहीं चाहते।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये टैक्स तो एक्सपैक्टिड थे। ये तो गैप को मीट-आऊट करने के लिए किये गये हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपैक्टिड नहीं है, जिन वस्तुओं पर 0% टैक्स था उन पर 4% हो गया है। जिन पर 2% था उन पर 6% हो गया है और मौजूदा सरकार ने 1 जनवरी से ये लागू कर दिये।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : स्पीकर सर, ये टैक्स तो जरूरत पड़ने पर घटाये या बढ़ाये भी जा सकते हैं। अभी तो सभी स्टेट्स के हिसाब से हमने भी कर दिया।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन्होंने वे टैक्स कम तो नहीं किये। इनसे इनको 75 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है और उसे दर्शाना भी नहीं चाहते। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वह यह है कि चौधरी बंसी लाल जी ने शराब बंदी के नाम पर अपनी सरकार बनाई थी और हरियाणा में शराब बंदी भी कर दी थी। शराब बंदी के नाम पर हरियाणा की जनता पर इन्होंने 800 करोड़ के नये टैक्स लगाये थे और शराब बंदी करने से एक वर्ष में 800 करोड़ रुपये का स्टेट का राजस्व घाटा होता रहा। चौधरी बंसी लाल जी ने 2 साल तक हरियाणा में शराब बंदी रखी। जिसके कारण दो साल में हरियाणा स्टेट का राजस्व घाटा 1600 करोड़ रुपये हो गया। हरियाणा स्टेट की हद पिट गई। विकास कार्य बंद हो गये और मजबूर होकर बंसी लाल जी ने दो साल बाद शराब खोल दी और शराब खोलने के बाद जो टैक्स शराब बंदी के समय 800 करोड़ के लगाये थे वे वापिस भी नहीं लिये। चौधरी संपत सिंह जी तो 800 करोड़ रुपये के टैक्स ही बताते थे लेकिन चौधरी बंसी लाल जी ने 300 करोड़ माना था। उस समय संपत सिंह जी यह कहते थे कि जो टैक्स जनता पर शराब बंदी के समय लगाये थे ये अब वापिस लिये जायें। लेकिन अब इनकी सरकार है, फिर भी इन्होंने वे टैक्स बिदड़ा नहीं किए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्स बंसी लाल जी ने शराब बंदी के नाम पर लगाये थे चाहे वे 300 करोड़ के थे या 800 करोड़ के थे, उन्हें ये विदड्रा करें। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चौधरी बंसी लाल जी ने अपनी सरकार के समय में हुडा के प्लॉटस बंद करके उनकी रजिस्ट्री-कंवेंस डीड लागू कर दी थी। जिससे हुडा का 200 करोड़ रुपये का रैवेन्यू बढ़ गया था। लेकिन हुडा के प्लाट्स बिकने बंद हो गये और उन्होंने दोबारा से ट्रांसफर करने शुरू कर दिये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चौटाला साहब की सरकार ने भी फिर से हुडा के प्लाट्स की रजिस्ट्री कंवेंस डीड 8 तारीख से शुरू कर दी। जिससे हुडा का 200 करोड़ रुपये का रैवेन्यू सालाना बढ़ेगा और ये भाई कह रहे हैं कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाये। टैक्स रहित बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा ख्याल है चौधरी सम्पत सिंह जी ने तो पहली बार ही बजट पेश किया है लेकिन हरियाणा की सरकार के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट मैंने पेश किये हैं। लगातार पांच बजट बल्कि छठा बजट भी मैंने ही पेश किया था। 1996 में जब हम सरकार छोड़कर गये थे तो 1996-97 का बजट भी हमने पेश किया था। अध्यक्ष महोदय यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि हमने जो बजट पेश किए उन में कोई टैक्स लगाये नहीं बल्कि कई टैक्सों को खत्म किया या कम किया। हां, चुंगी समाप्त हम नहीं कर सके, इन्होंने समाप्त की है उसके लिये तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं लेकिन बैरियर हमने खत्म किये जो कि बहुत बड़ी लानत थी। ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों को बड़ी दिक्कत आती थी। बैरियर खत्म करने के बावजूद भी हमने सरकार को घाटे में नहीं रहने दिया। 1996-97 के बजट में हम कोई घाटा छोड़ कर नहीं गये थे। जहां तक मेरा अन्दाजा है हम 31 मार्च तक 500 करोड़ रुपया छोड़कर गये थे जो कि नई सरकार के काम में आना था। यह पैसा रिजर्व बैंक तथा कुछ दूसरे बैंकों में हम जमा कर के गये थे। अध्यक्ष महोदय बड़े ही दुःख की बात है कि इस छोटी सी हरियाणा स्टेट के ऊपर 14418 करोड़ रुपये का ऋण हो जाएगा जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कैलकुलेट करके अपनी स्पीच में भी कहा है। इस तरह से हरियाणा के बजट का 30% या 31% हिस्सा तो ब्याज के रूप में इस कर्ज के ऊपर चला जाया करेगा। अध्यक्ष महोदय, 1966 में हरियाणा बना था और जहां तक मुझे याद है कि जब 1991 से 1996 तक हमारी सरकार रही तब तक यानि 30 साल में वर्ल्ड बैंक या दूसरी स्टेटों अथवा संस्थाओं से केवल 6000 करोड़ रुपये के ऋण हरियाणा सरकार ने लिये थे लेकिन 1996 से 2000 तक की सरकारों की नाकामयाबी की वजह से ये कर्जे 14418 करोड़ रुपये तक पहुंच गये। अध्यक्ष महोदय, हमारी समझ में नहीं आता कि ये इतने बड़े कर्जे की किश्तें कहां से देंगे क्योंकि

[श्री मांगे राम गुप्ता]

नये टैक्स लगा नहीं सकते और अनावश्यक आमदनी के जो सोर्सिज़ थे, वे सब ये लगा चुके हैं। सड़कें पक्की करानी हों तो ये वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे, बिजली के सुधारीकरण के लिये भी लोन लेते हैं। सरकार लोन लेकर ही काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार अपने साधनों से क्या काम कर रही है। सोचने का विषय यही है कि आपने इस विषय पर विचार किया ही नहीं है। जब आप बजट भाषण पढ़ रहे थे तो उस वक्त जब चुंगी को खत्म करने वाला प्वायंट आया था तो आपने मुझे टोका था कि गुप्ता जी आप सो तो नहीं रहे। मैंने कहा था कि मैं सो नहीं रहा बल्कि आपके बजट को गहराई से देख रहा हूं। (विघ्न) आपने अपने बजट में मण्डी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2000 से 21 वस्तुओं पर मार्किट शुल्क दो प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत कर दिया। इस का उल्लेख तो आपने अपने बजट भाषण में किया है लेकिन रूरल डिवैल्पमैंट फण्ड का जो एच०आर०डी०एफ० का पैसा माफ किया था, उसकी चर्चा आपने इस बजट में नहीं की। उस पैसे को आप कहां पर खा गए, या उसका उल्लेख करना भूल गए, यह तो आप जानें। लोगों को दिखाने के नाम पर तो आपने 21 चीजों पर सैस 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत कर दिया हमारे हरियाणा में किसान दो मेन फसल पैदा करते हैं उन पर सैस को कम नहीं किया गया। ये दो चीजें हैं गेहूं और चावल। छोटी-मोटी जो पैदावार किसी इलाके में कहीं कहीं पर होती है उन्हीं पर सैस कम किया गया है। सरकार को चाहिए कि गेहूं और चावल की पैदावार पर भी सैस कम करे। सरकार कह रही है कि पिछले साल सैस कम करने के कारण इस मद के तहत 100 करोड़ रुपये की इन्कम हुई जबकि दूसरी तरफ कह रही है कि अगले साल इस मद के तहत 130 करोड़ रुपये आने की संभावना है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने सैस कम कर दिया तो फिर आपकी आमदनी इस मद के तहत कैसे बढ़ेगी ? (विघ्न) जो बात मैंने कही है उस हिसाब से आप देख लें कि आपने सैस खत्म किया है या नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री जी का चुंगी समाप्त करने के लिए धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नोटिस में लाना चाहूंगा कि इन्होंने चुंगी क्या समाप्त की कि साथ ही साथ कई कमेटीज भी समाप्त कर दी। अब जो हमारी 54 कमेटीज रही हैं उनके लिए सरकार ने 23.84 करोड़ रुपये की ऐड देने की बात कही है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इतनी कम राशि से कमेटीज का क्या भला होगा और क्या वे जनकल्याण के कार्य कर पाएंगी ? कमेटीज के जो कर्मचारी हैं उनको पिछले तकरीबन 3-3 महीनों से पे भी नहीं मिल पाई है। चौधरी बंसी लाल जी ने अपने समय में एक बहुत अच्छा काम किया कि इनके वक्त में जब सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो इन्होंने उन सब को ठिकाने लगा दिया था। उस वक्त वे कर्मचारी ऐसे ठिकाने लगाये गए कि अब वे आपके समय में हड़ताल करने लायक रहे ही नहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : गुप्ता जी, हमने तो जो कर्मचारी बंसी लाल जी के वक्त में हटाए गए थे उन सब को दुबारा वापस नौकरी में ले लिया है और इनके अलावा नये कर्मचारी भी लगाये हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : आपकी बात हम मान लेते हैं लेकिन जो कर्मचारी कमेटीज़ में काम कर रहे हैं उनको आप पे भी दिलवाने का प्रबन्ध करें। आज उनको 3-3 महीने से पे नहीं मिल पा रही है। अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में व्यापारियों को राहत देते हुए फार्म 14-15 जो खत्म किया गया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस बारे में मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि ये फार्म तो जब हमारी सरकार थी उस वक्त खत्म कर दिए थे। बाद में जब बंसी लाल जी मुख्य मंत्री बने तो इन्होंने फिर से उनको लगा दिया था। अब आपने उनको दुबारा से हटा दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को समझता हूं कि सरकार के पास जितने रिसोर्सिज़ होंगे उतना ही बजट अलॉट करेगी उससे ज्यादा बजट कहां से अलॉट करेगी बजट स्पीच के पेज नं०-6 पर देखिए कि ग्रामीण विकास की मद में कितना पैसा रखा गया है ? अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा प्रदेश की 80% जनता गांवों में रहती है इसलिए उसका विकास सबसे ज्यादा होना चाहिए। हमारे गांव बहुत पिछड़े हुए हैं लेकिन उनके लिए वित्त मन्त्री जी ने 35.10 करोड़ रुपये की राशि की अलॉटमैंट का प्रावधान रखा है। मैं वित्त मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि क्या इतनी राशि से गांवों का विकास हो पाएगा ? (विघ्न) वित्त मन्त्री जी से मेरा सुझाव है कि गांवों के विकास के लिए और अधिक राशि का प्रावधान करना चाहिए। इसी प्रकार से आपने हरियाणा के हरिजन कल्याण निगम के लिए भी बहुत थोड़ी राशि का प्रावधान किया है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मांगे राम गुप्ता जी से यह कहना चाहूंगा कि एच०आर०डी०एफ० का पैसा कहां जाएगा वह पैसा भी उपलब्ध है जो कि गांवों के लिए विकास कार्यों पर खर्च किया जाना है। इसी तरह से सड़कों के विकास के लिए जो पैसा रखा है उसमें रूरल डिवैल्पमैंट पर भी खर्च होना है। गांवों के लिए अगर सड़कें ही नहीं बनाएंगे तो वहां पर विकास कार्य कैसे होंगे बिना सड़कों के गांवों की तरक्की कैसे होगी। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में हरिजनों के करीब 12 हज़ार परिवार हैं और उनके लिए 37.23 करोड़ रुपये अलॉट करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग कल्याण निगम हैं और अल्पसंख्यक वर्ग भी इसमें है हरिजन और कमजोर वर्ग के लोग तथा माईनोरिटीज़ के लोग भी इसमें शामिल हैं उन सबके लिए आपने 6.50 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा है जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है।

श्री सम्पत सिंह : मांगे राम जी, आप तो खुद सयाने आदमी हो और वित्त मन्त्री रहे हुए हो फिर भी इस किस्म की बावली बात क्यों करते हैं। आपको तो इस बारे में खुद ही पता है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कि सरकार गांवों के विकास के लिए पैसा दे रही है लेकिन हमारे समय में हमने हर एम०एल०ए० को चाहे वह रूलिंग पार्टी से हो, या ओपोज़ीशन पार्टी से हो, विशेष ग्रान्ट विकास कार्यों के लिए दी थी। वह ग्रान्ट इसलिए दी थी क्योंकि हर एम०एल०ए० का अपने क्षेत्र से बड़ा भारी लिंक रहता है क्योंकि वह गांव में जाता था और गांव की गलियों में घूमता था। चुनाव के समय आपने खुद भी गांवों में जा कर देख लिया होगा कि वहां पर कितनी बुरी हालत है। गोडे-गोडे तक गांवों में कीचड़ होता है जिसके कारण गांव की गलियों में घुसना मुश्किल हो जाता है। (विघ्न)

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांगे राम जी एक गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं (विघ्न एवं शोर) चौधरी भजन लाल जी अगर आपके टाईम में ऐसी बात न हुई हो तो आप बताएं। मैं तो आपके टाईम का भी भुक्तभोगी हूं। (विघ्न एवं शोर)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चौधरी भजन लाल जी को याद दिलाना चाहूंगा कि इनके समय में भी हम लोगों के खिलाफ 3-3 प्रिविलैज मोशन्ज़ थे। मेरे खिलाफ तीन-तीन प्रिविलैज कमेटी में मामले ठोक रखे थे। इनको याद होगा कि जब मैं बोलता था तो चौधरी भजन लाल जी मुख्य मन्त्री होते हुए खुद 100 से ज्यादा बार इन्टरवीन किया करते थे। इनको भी याद होगा, प्रैस के लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं और दूसरे लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं, मिनिस्टर की बात तो छोड़िये ये खुद मुझे इन्टरवीन किया करते थे। (विघ्न एवं शोर)

श्री धीरपाल सिंह : चौधरी भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे और उस वक्त प्रो० सम्पत सिंह जी किसी बहस पर चर्चा करते हुए बोल रहे थे। उस दिन चौधरी देवी लाल की 13वीं थी, मैं मुंडाल से आया था। यहां पर आया तो मैंने देखा कि सम्पत सिंह जी को सस्पैंड कर दिया गया तो मैंने कहा कि इनको किस बात के लिए सस्पैंड किया गया है तो मुझे यह कहा गया कि आपको भी मेम किया जाता है। यह रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने बोलते हुए कहा कि हुडा के द्वारा रजिस्ट्री में हमारी वर्तमान सरकार को दो सौ करोड़ रुपए का इजाफा होगा। प्लाट होल्डर को चार ट्रांस्फर फ्री हैं। सर, सरकारी दस्तावेज में दर्शाया गया है कि 1998-99 में रहन के द्वारा, नगरपालिका के द्वारा और एग्रीकल्चर लैण्ड से 294 करोड़ रुपए की इन्कम प्राप्त हुई है। 1999-2000 में एस्टीमेट 408 का था और प्राप्ति 360 करोड़ रुपए हुई थी। 2001 के लिए 405 करोड़ का एस्टीमेट है। इन्होंने 200 करोड़ इसलिए कह हैं क्योंकि यह फर्जी बात है। मैंने यह बात सरकारी दस्तावेज से हाउस के सामने रखी है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, धीरपाल जी बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं। आप स्पीकर के पद पर नए आए हैं वैसे आपको सदन का बहुत ऐक्सपीरियंस है। मैं आपके माध्यम से इनको यह कहना चाहता हूं कि जब कोई मैम्बर बोल रहा हो तो मंत्री महोदय, को प्वायंट नोट कर लेने चाहिएं और जब जवाब दें तो उसके बारे में बोल लें।

श्री धीरपाल सिंह : चौधरी साहब, इन्होंने एक बात कही थी मैंने उसका सरकारी दस्तावेज से जवाब दिया है बाकी के प्वायंट हम नोट कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्लाट के बारे में ट्रांसफर की बात कही है। बाद में आपने कह दिया कि ट्रांसफर नहीं होगी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इमीजिएट इफैक्ट से तो आप कर सकते हो लेकिन रिट्रोसपैक्टिव इफैक्ट से नहीं कर सकते। आप इस बारे में विचार कर लें। लोगों में बहुत रोष है। उन्होंने मुझे लिखकर दिया है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि यहां पर जो गवर्नर एड्रैस पढ़ा गया है वह सरकार की अथैंटिक स्पीच होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए बजट बनाना चाहिए। कृषि में आपने गन्ने की बिजाई पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि यह लाभदायक फसल है। यह भी कहा है कि फलों और सब्जियों की खेती ज्यादा करें उससे किसान को ज्यादा लाभ मिलेगा। यह नीति आपने दर्शाई है। आप गवर्नरज़ एड्रैस पेज नम्बर 14 पर देखें। उचानी गांव करनाल के पास है। उसमें एक बागवानी प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा जो बेमौसमी सब्जियों और फूलों की पैदावार के लिए ग्रीन हाउस प्रोद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह संस्थान 12.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है लेकिन बजट में इस बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अमाउंट सरकार उसके लिए खर्च करने जा रही है इसलिए इसका किसी न किसी हैड में वित्त मंत्री जी को अपनी बजट स्पीच में शो करना चाहिए था लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। यह 12.50 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है जब इसका ही बजट में जिक्र नहीं होगा तो फिर इस बजट को बनाने का लाभ क्या है ? इसी तरह से मछली उत्पादन के बारे में गवर्नर ऐड्रैस में तो चर्चा की गयी है कि उसका रिकार्ड उत्पादन हुआ है लेकिन बजट में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। बजट में वित्त मंत्री जी ने इस चीज को कहीं पर भी टच ही नहीं किया है। इस बारे में कोई फंड अलौट ही नहीं किए हैं। इसी तरह से ऐनीमल हसबैन्ड्री की बात है। हरियाणा के किसान के लिए पशुपालन आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नर ऐड्रस में तो कहा गया लेकिन बजट में इस बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं टाईम का ध्यान रखते हुए ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। साथ ही

मुझे अपनी बीमारी के हिसाब से भी कम ही बोलना पड़ता है। जब सरकार ने अग्रोहा मेडीकल कालेज की ग्रांट बहाल की थी तो मैंने मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद किया था। वित्त मंत्री जी का या शायद मुख्यमंत्री जी का कहीं पर भाषण था कि हमने इस कालेज की ग्रांट जो चौधरी बंसी लाल जी के समय में बंद रही थी, को खोला है। चौधरी बंसी लाल जी ने तो लोगों की कचहरी में खड़े होकर देख लिया लेकिन इनको केवल दो ही सीट मिली हैं। खुद तो ये पता नहीं कैसे लोगों की खुशामद करके एम०एल०ए० बन गये हैं। (विघ्न) जब हम 60 एम०एल०ए० थे तो भी हमारे समाज के दो एम०एल०ए० होते थे और अब जब हम 21 हैं तब भी हमारे समाज के दो एम०एल०ए० हैं। इनका दूसरा एम०एल०ए० तो * * ही बनकर आया है।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह फौजी अफसर है और अपनी मेहनत से चुनाव जीतकर आया है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल पार्टी है उसके तो केवल 21 ही एम०एल०ए० हैं जबकि हमारी रीजनल पार्टी होते हुए भी दो एम०एल०ए० हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : जो उस कालेज को 7 करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई थी वह तो चौधरी बंसी लाल जी के समय के ड्यू बनते थे क्योंकि हमने तो उस कालेज की कोई ग्रांट बंद नहीं की थी। मुख्यमंत्री जी ने कल इस बारे में एक चिट्ठी भी यहां पर पढ़कर सुनायी थी। वह रिकार्ड है जोकि आज भी मौजूद है। उस समय युनानीमसली बोर्ड की तब्बजो पर एक रास्ता निकाला गया था, सरकार के खर्च घटाने का और उस मेडीकल कालेज को लाभ पहुंचाने का, परन्तु ग्रांट हमारे समय में बंद नहीं हुई है। हम तो 2 करोड़ रुपये चौधरी बंसी लाल जी के समय के लिए अपने बजट में रखकर गए थे। आपने जिस ग्रांट की घोषणा की वह तो चौधरी बंसी लाल जी के समय की बनती थी। (विघ्न) चौधरी बंसी लाल जी के इन कारनामों की वजह से ही लोगों ने वह सरकार बना दी नहीं तो इनकी सरकार कौन बनाता था।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांगे राम जी से जानना चाहता हूं कि मेरी सरकार किसके कारनामों से बनी थी ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारे कारनामों से नहीं बनी थी बल्कि आपने जनता के साथ धोखा करके झूठे वायदे करके वह सरकार बनायी थी।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, 24 जुलाई 1999 को जो चौटाला साहब के नेतृत्व में सरकार बनी थी वह कांग्रेस और हरियाणा विकास पार्टी दोनों के कारनामों से बनी थी और अब जो हमारी सरकार बनी है वह हमने जो अपने पिछले सात महीनों में काम किए हैं, उनके पोजिटिव अचिवमैन्ट से बनी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इनकी सरकार क्यों बनी ? अंग्रेजों के समय की बात सुना रहा हूं ध्यान से सुनो। सांपला में एक जिलेदार था उसकी जिलेदारी तुड़वा दी। सांपला के सेठ का उसके साथ झगड़ा हो गया तो सेठों ने मुकदमा कर दिया और जिलेदार ने भी कोर्ट केस कर दिया। जिलेदार कोर्ट में जीत गया और जीतने के बाद सेठ के घर डांग खड़का दी कि मैं कोर्ट से जीतकर आ गया हूं तो सेठ ने कहा कि तू अपने कर्मों से जीतकर नहीं आया बल्कि हमारे

** चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री भूपेन्द्र सिंह]

कुछ कर्म माड़े थे जिनकी वजह से जीतकर आया है सो आपका वही हाल है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के कुछ माड़े कर्म बाकी थे जिनकी वजह से आप जीतकर आ गए।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को मेरा सुझाव है। इनकी पार्टी की तरफ से जितने माननीय सदस्य बोले सभी ने अग्रोहा मेडीकल कालेज के बारे में खूब दबदबा मचाया। मैं भी इनका धन्यवाद करता यदि इन्होंने जो सात करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी, उस राशि को रिलीज कर देते। सात करोड़ में से आपने एक करोड़ रुपया रिलीज किया है यह उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है आप इस 31 मार्च तक उनका बकाया 6 करोड़ रुपया रिलीज करें। अगर आप समाज की वाहवाही लेना चाहते हैं तो यह राशि शीघ्र रिलीज कर दें।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मांगे राम जी तो वित्त मंत्री थे इसके अलावा इनकी पार्टी के सारे सदस्यगण जो उधर बैठे हैं, सारे जानते हैं कि जो सात करोड़ रुपया आप झूठ बता रहे हैं इसमें रैकरिंग और नॉन रैकरिंग दोनों चीजें मिलाकर शामिल होती हैं जहां तक तनख्वाहों का सवाल है तो उसका तो 50 लाख रुपया बकाया था और वह 50 का 50 लाख तुरंत रिलीज कर दिया था ताकि तनख्वाहें बकाया न रह जाएं। दूसरे जो निर्माण कार्यों पर पैसा खर्च होता है उसके लिए कोई एक मुश्त रकम कभी नहीं कराई जाती। आज जैसे बजट में प्रोविजन रखे हैं हर मद में रखे हैं क्या यह सारा का सारा पैसा एक साथ रिलीज कर दिया जाएगा ? वह तो जैसे-तैसे निर्माण का कार्य गति पर आएगा। पी०डब्लू०डी० (बी० एण्ड आर०) और सोसायटी मिलकर काम कर रही है। किसी वर्क को हम पेंडिंग नहीं रहने देंगे और काम होने के साथ-साथ पैसा मिलेगा। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश शर्मा जी, मोबाइल फोन हाउस में लाने की अनुमति नहीं है आप मोबाइल फोन यहां लेकर न आया करें।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो पैसा है ग्रान्ट जो मिलनी थी उसके न मिलने के कारण सोसायटी जिसके अंदर मैं भी पैट्रन हूं, जिंदल साहब भी हैं चीफ मिनिस्टर साहब और चौधरी देवी लाल जी भी पैट्रन हैं। स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले बताया कि सोसायटी तो पैसा इकट्ठा करके खर्च करती रही। गवर्नमैंट ने खर्च किया नहीं, हम भी शामिल थे। बाकायदा मीटिंग करते रहे और यहां तक कि विरोध करते रहे। विरोध के लिए सोसायटी ने चौटाला साहब को बुलाया था उसके लिए एक महीना पहले से ही टाइम निश्चित किया था और 25 जुलाई का टाइम निश्चित किया हुआ था। यह बात अलग है कि पहले उनको विपक्ष के नेता के रूप में बुलाया हुआ था लेकिन परमात्मा की करनी थी कि वे वहां विपक्ष के नेता के रूप में नहीं बल्कि मुख्य मंत्री के रूप में गए और मुख्य मंत्री जी ने जाते ही कह दिया कि पिछले दो साल से जो काम बंद पड़ा है उसे चालू करवाइए। उस जमीन पर जाने से पहले ही चौटाला साहब को मुख्य मंत्री का पद दिला दिया और 25 तारीख को जाते ही उन्होंने अग्रोहा मेडीकल कालेज की ग्रान्ट को बहाल करने के आदेश दे दिए और जितना पैसा बनता था रिलीज हो गया है और ज्यों-ज्यों एल०ओ०सी० की डिमाण्ड आती जायेगी पैसा रिलीज होता रहेगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी को बहुत इंटेलीजेंट समझता था। ये कह रहे हैं कि सरकार अग्रोहा मेडीकल कालेज का एक पैसा भी बाकी नहीं रखेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस सरकार ने पहले यह कहा था कि हम अग्रोहा मेडीकल कालेज को सात करोड़ रुपया देंगे। मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है क्या उस बजट में इन सात करोड़ रुपयों को रिलीज करने का कोई प्रावधान है ?

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री मांगे राम गुप्ता जी ने बजट को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है वरना ये इस बात को नहीं कहते।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कहने को तो हर कोई कह सकता है कि हम यह देंगे और वह देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री महोदय यह जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन के आशीर्वाद से यह सरकार बनी है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का इलाका भी वहां पर पड़ता है, चौधरी सम्पत सिंह का इलाका भी वहीं पड़ता है और चौधरी देवी लाल जी ने ही उस कालेज के लिए जमीन दी थी। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अग्रोहा मेडीकल कालेज की 6 करोड़ रुपये की ग्रान्ट को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों का सवाल है। सड़कें तो यह सरकार बना ही देगी क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लोन जो ले रखा है। बिजली की सुविधा देने के लिए भी यह सरकार जरूर कुछ करेगी क्योंकि वर्ल्ड बैंक का लोन ले रखा है। बजट में ऐसा कहा गया कि स्कूलों को ज्यादा खोला जायेगा जिससे शिक्षा में सुधार हो, अस्पताल ज्यादा बनवाये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी अपनी सुरक्षा, अपनी इज्जत को ठीक ढंग से बचा सके। जब आदमी का घर से बाहर निकलना ही दूभर हो जाये। घर से बाहर निकलने पर यह डर रहे कि कहीं लूट न लिया जाये, सड़क पर जाते हुए यह लगे कि कहीं कोई किडनैप न कर ले तो इस हालात में आदमी अपने आपको सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है ? ऐसी हालत में सरकार की नाकामी समझी जाती है और सरकार की बदनामी भी होती है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने शराब बन्दी के समय एक बड़े माफिया गिरोह का जिक्र किया जिसने इस प्रदेश में बड़ेबड़े क्राइम किए हैं। इस बात के लिए सभी सदस्य सहमत हैं। अध्यक्ष महोदय, जब क्राइम प्रदेश में बढ़ जाता है तो कहीं पर लूट-खसोट हो रही है, कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर किडनैपिंग हो रही है कहीं पर मर्डर हो रहा है तो सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनको ऐसी सजा दे ताकि दूसरे लोगों को उनकी सजा से सबक मिल जाये और फिर उस क्राइम को करने की किसी दूसरे आदमी में हिम्मत न रहे। क्योंकि हर वक्त तो सरकार किसी भी आदमी की पैरवी नहीं कर सकती कि 24 घण्टे उसके घर पर पुलिस का पहरा दिया जाये। ऐसे पता भी नहीं चलता कि अपराधी किस आदमी को किस समय अपना निशाना बनायेंगे। इस बात के लिए मैं सदन के सामने एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे हल्के के गांव बड़ा खुर्द जो कि जीन्द से 6 किलोमीटर दूर है दिसम्बर, 1999 को उस गांव के ही किसी अपराधी आदमी ने एक छः साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। उस बच्चे के घर वाले सारी रात इधर-उधर ढूंढते रहे लेकिन दूसरे दिन उस गांव के स्कूल के पास उस बच्चे की लाश मिली और जिस हालत में उस बच्चे को मारा गया था उससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि कोई अपराधी जगत का ही आदमी ऐसी मौत मार सकता है। उस छोटे से बच्चे की किस के साथ दुश्मनी हो सकती है। क्या उस बच्चे का मर्डर जाति दुश्मनी के कारण हुआ। जो मर्डर जाति दुश्मनी की वजह से होते हैं उनकी डिक्लयेरेशन हो जाती है कि फलां आदमी को मैंने मार दिया। उस गांव के लोग देश के प्रधानमंत्री से मिले और यहां के मुख्य मंत्री से मिले। लेकिन 3 महीने होने जा रहे हैं आज तक यह सरकार उस 6 महीने के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जब तक ऐसी हालत रहेगी तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, लड़कियां कालेज कैसे जाएंगी, व्यापारियों का काम कैसे चलेगा ? दुकानों के कब्जे होना, किडनैपिंग जैसे इन्सीडैंट हो जाते हैं लेकिन ऐसे काम करने वालों को सजा देना इस सरकार की ड्यूटी बनती है। यह सरकार जनता की बनाई हुई है, आपकी सरकार प्रजातंत्र की सरकार है मैं आपका विरोधी नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि आपकी सरकार पूरे 5 साल चले। दल बदल-बदल कर सरकार तोड़ना ठीक बात नहीं है। हमारे लिए आपस में एक दूसरी सरकार की बुराई

[श्री मांगे राम गुप्ता]

करना ठीक बात नहीं है। प्रजातंत्र की जो सरकार बनी है हमें उससे खुशी है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों के हित की बात करती है। मैं बिल मंत्री महोदय को एक बात कहूंगा कि वे मुख्यमंत्री महोदय से एक काम करवाएं कि किसानों की तरफ जो बिजली के बिल बकाया हैं उनको माफ कराएं क्योंकि उसमें हरियाणा के किसानों का कोई कसूर नहीं है। इनकी पार्टी के नेताओं ने किसानों को कहा था कि आप लोग बिजली के बिल मत भरो और बिल न भरने की वजह से उन किसानों पर कई केस बन गए थे, कुछ को जेल में डाल दिया गया था। ये बातें आज किसानों के गले की हड्डी बन गई हैं। वे बकाया बिल आज हजारों और लाखों में हो गए हैं। इसलिए इन बिलों को माफ किया जाए।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। सम्मानित साथी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने नारा दिया था कि बिजली के बिल न भरो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये एक बार न्यूज पेपर उठाकर देखें कि सबसे पहले किस की पार्टी के नेता ने यह नारा दिया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की यह स्टेटमैंट आई थी कि हम फ्री बिजली-पानी देंगे। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : वह अलग चीज है मैं तो बिलों की बात कर रहा हूं।

श्री सम्पत सिंह : हम इस बात को मानते हैं कि वह अलग चीज है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी का यह ऐलान नहीं था कि बिजली के बिल न भरो। यह गलत बात है। जिस समय किसान इसके लिए आन्दोलित थे, ये भाई मंत्री बनकर उनकी लाशों के ऊपर से निकलते थे। उस समय किसकी सरकार थी कौन वजीर थे, ये इस बारे में बताएं ? जब निर्सिंग में, कादमा में, टोहाना, नारनौल, नारनौंद में और मण्डियाली में दर्जनों किसान मारे गए थे ये कांग्रेस के भाई झंडी वाली गाड़ियों में घूमते थे और अब ये किसानों के हमदर्द बनते हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार बीच में जवाब देने खड़े हो जाते हैं, यह ठीक बात नहीं है। इन्होंने किसानों को गुमराह करके बिजली के बिल नहीं भरने दिए और कहा कि जब हमारी सरकार आएगी हम इन बिलों को माफ कर देंगे।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब ये इन्टरवीन कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि लीडर ऑफ अपोजीशन और मुख्यमंत्री महोदय कहीं भी इन्टरवीन कर सकते हैं। माननीय साथी गलत बात कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। उस वक्त इन्होंने वोट लेने के लिए हर तरह से किसानों को गुमराह करने का काम किया। अब इनकी सरकार बन गई है इसलिए इनका यह धर्म और फर्ज बनता है कि ये किसानों के बिजली के बिल माफ करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज वे बकाया बिल जो लाखों में हो गए हैं उनको किसान देने की स्थिति में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चाहे मौजूदा सरकार उन किसानों के बिजली के कनैक्शन काट दे, चाहे उन्हें उठाकर जेलों में बंद कर दे। लेकिन वे किसान अब बिजली का बिल भरने की हालत में नहीं हैं। अब वे बिजली के पुराने बिल नहीं भर सकते। अध्यक्ष महोदय, जनता ने बड़े विश्वास के साथ चौटाला साहब की सरकार बनाई है और ये अपने आपको किसान हितैषी बताते हैं। जब ये दूसरे हैड में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो क्या ये किसानों

के पुराने बिजली के बिल नहीं माफ कर सकते ? अध्यक्ष महोदय, ये मुफ्त बिजली-पानी किसानों को दें, मैं इसके हक में नहीं हूं क्योंकि जब पैसे देने से ही बिजली नहीं मिलती तो मुफ्त में कहां से मिल जायेगी ? पंजाब ने अपने किसानों को मुफ्त बिजली दी है, वहां पर लेने के देने पड़ गये हैं। एक घंटे मुफ्त में बिजली देने से काम नहीं चलता। किसानों को तो 16 घंटे बिजली की जरूरत होती है। अध्यक्ष महोदय, किसानों को मुफ्त बिजली देने से न तो किसानों की भलाई होगी और न ही स्टेट की भलाई होगी। किसी वजह से किसान यूनियन द्वारा गुमराह किये जाने पर किसान बहक गये और उन्होंने उस समय अपने बिजली के बिल नहीं भरे। अब किसान वह बिल भर नहीं सकता और सरकार उसे माफ नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में तो किसानों के गले में हड्डी अटक गई है। अध्यक्ष महोदय, इसका तो एक ही हल है कि मुख्य मंत्री महोदय को किसानों के वे बिल माफ कर देने चाहिएं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मांगे राम जी बहुत ही समझदार आदमी हैं। ये जानते हैं कि किसान यूनियन अब भी है और चौधरी बंसी लाल जी के समय में भी थी और कांग्रेस की सरकार के समय में जब चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे, तब भी थी। अब भी किसान यूनियन ने यह नारा दे दिया है कि वे बिल नहीं भरेंगे। हमारी सरकार को बने 8 महीने हो गये हैं और सभी माननीय सदस्य भी देख रहे हैं कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। उन किसानों को कैसे नैगोशिएट कर रही है। उनसे बात-चीत कर रही है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसी लाल जी की सरकार ऐसे समय में किसानों को लाठियों और गोलियों से जवाब देती थी। स्पीकर सर, लाठियां और गोलियां चलाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान बात-चीत करने से होता है और हमारी सरकार भी किसानों के साथ बात-चीत कर रही है। पहले की सरकारों की तरह उन पर लाठियां या गोलियां नहीं चलवा रही। स्पीकर सर, डिक्टेटरशिप से काम नहीं चलता। चौधरी बंसी लाल जी तो इस मामले में भजन लाल जी से भी आगे निकल गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, प्लीज आप बैठिये।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये लोग किसानों पर गोलियां चलाते रहें और हम जो किसानों से संबंधित हैं हम अपने घर में बैठे रहें, यह कैसे हो सकता था। स्पीकर सर, उस समय हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, इनका विरोध किया ताकि और लाठियां व गोलियां न चलें। स्पीकर सर, यह कैसे हो सकता था कि हम घर बैठे रहते और किसानों का खून सड़कों पर बहता रहता और ये दोनों भाई अपने घर में बैठकर मौज करते रहते। हमने उस समय किसानों का पूरा-पूरा साथ दिया।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने किसानों की मदद की लेकिन अब तो इनकी सरकार आ गई है। जैसे चौधरी देवी लाल जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ। आज उसी तरह होना चाहिए कि चौटाला साहब कहें कि किसानों के वे बिल माफ। इसमें नैगोशियेशन की क्या बात है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी, आप बजट पर बोलिये।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्री जी हाउस में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कह रहे थे कि प्रदेश के लोगों को ज़ीरी के अच्छे भाव दिये गये। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि किसानों को ज़ीरी का अच्छा भाव नहीं मिला। उनकी दुर्गति हुई। जैसा कि हुड्डा साहब ने भी चर्चा की थी कि वे मंडियों में गये थे। व्यापारी होने के नाते मेरी भी ज़ीरी की दुकान है और ज़ीरी बेचने का अनुभव है।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कल जवाब में कहा कि सरकार ने किसानों से पहली सरकार के मुकाबले छः गुना ज्यादा जीरी खरीदी और राजस्थान से भी जीरी आकर हरियाणा की मंडियों में बिकी है। मुख्य मंत्री का यह जवाब था जबकि मैं यहां पर जीन्द की एक मण्डी का जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश की जीन्द में भी बहुत बड़ी मण्डी है जिसमें किसान मुख्य रूप से पैडी की पैदावार लाता है और हमारे टाइम में पूरे सीजन में ढाई लाख तीन लाख बोरी पैडी की खरीद होती थी लेकिन इस बार पूरा सीजन चला गया और पूरे सीजन में सरकार ने सिर्फ एक हजार पैडी की बोरी खरीदी। सरकार तो छः गुना पैडी खरीदने की बात करती है यह तो छठा हिस्सा भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी बताएं तो सही कि किसानों को वह भाव कहां मिले हैं ? अध्यक्ष महोदय, बजट में अलॉटमैंट के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि कौन से डिपार्टमैंट फूड प्रोडक्ट्स के लिये क्या साधन जुटाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों की इन्होंने बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। अब मैं लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर आता हूं। लॉ एण्ड आर्डर की बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बजट के अन्दर पुलिस डिपार्टमैंट के लिये कोई अलाटमैंट नहीं की। जिस तरह से गवर्नर साहब की स्पीच में भी जिक्र किया गया है कि पुलिस के लिए और अच्छे हथियार खरीदेंगे, पुलिस की तादात बढ़ायेंगे ? यह काम तो सरकार का था। बजट में इन्होंने इस बात को टच ही नहीं किया कि किस हैड के तहत कितने हथियार खरीदेंगे, कितने मकान पुलिस के लिये बनाएंगे, कितनी और रिक्रूटमैंट करेंगे अथवा और क्या सुविधाएं देंगे। क्राइम रोकने के लिये क्या पैट्रोलिंग होगी ? इस डिपार्टमैंट को तो टच भी नहीं किया गया है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मांगे राम जी भी वित्त मंत्री रहे हैं। इनको सब चीजों का पता है कि सारी बातें विस्तार से बजट स्टेटमैन्ट में नहीं आती हैं। इनके पास कितने बड़े पोथे हैं जो कि सरकार ने इनको दे रखे हैं, उनको ये पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, अब ये सी०डी० की बात करते हैं वह तो इनकी आसानी के लिये बनाई गई ताकि ये जिस डिपार्टमैन्ट के जिस हैड को निकालना चाहें, निकाल कर देख सकते हैं। प्लान में निकालना चाहें तो प्लान में देख लें। नोन-प्लान में देखना चाहें तो नोन-प्लान में देख लें। सरकार ने इनके लिये इतनी सुविधा दे दी है लेकिन ये तो मात्र बजट स्टेटमैन्ट पढ़कर आ गये हैं, उससे तो बात नहीं बनती। अगर इन्होंने मेहनत की होती, पोथे पढ़े होते तो इनको सारी बातों का पता लगता। बजट स्टेटमैन्ट में तो मोटी-मोटी बातें कही जाती हैं। पूरा बजट अगर आज में पढ़ना शुरू करूं तो पढ़ते-पढ़ते अगला हफ्ता आ जाएगा। पूरी रामायण की तरह यह पोथा है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये रैलेवैंट जवाब तो दें। मैं यह तो नहीं कहता कि सारा पोथा ये पढ़ सकते हैं या फिर सारा पोथा पढ़ें लेकिन जो मेन डिपार्टमैन्ट्स हैं जिनसे सरकारें चलती हैं उनकी बजट अलाटमैंट का जिक्र तो बजट में आना चाहिए। ऐसे कह देने से तो काम नहीं चलता कि बहुत सारी किताबें भरी पड़ी हैं। भरी पड़ी हैं कां तो कोई मतलब नहीं होता। रामायण की किताब में भी एक आदमी सारांश में सारी जरूरी बातों को लेता है। इनको मेन-मेन डिपार्टमैन्ट की बजट अलाटमैन्ट तो दिखानी चाहिए थीं जैसे लॉ एण्ड आर्डर डिपार्टमैन्ट है, फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैन्ट है, फिशरीज डिपार्टमैन्ट है, कृषि या बागवानी डिपार्टमैन्ट है। सरकार ने इस तरह से कोई भी डिपार्टमैन्ट टच नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस सरकार के बनने के बाद अपना पहला बजट पेश किया है। यह महकमा कांटों के ताज से भरा हुआ महकमा है। इस विभाग में रहते हुए आप कोई सैर-सपाटा नहीं कर पाएंगे। इस महकमे में बहुत मेहनत के साथ काम करना पड़ता है। जब मैं वित्त मंत्री था तो उस

वक्त तकरीबन सारे मंत्री दूसरे देशों की यात्रा कर आये थे लेकिन मैं तो किसी दूसरे देश क्या बल्कि अपने ही देश के किसी दूसरे प्रदेश में भी नहीं जा पाया था। मैं 5 साल तक वित्त मंत्री रहा और कभी भी एक पैसे का नया टैक्स नहीं लगाया। टैक्स न लगा कर भी हम खजाने में काफी पैसा छोड़कर गए थे। हमने अपने समय में कभी भी घाटे का बजट पेश नहीं किया। सम्पत सिंह जी आप मेहनत के साथ इस विभाग में काम करें या फिर यह महकमा किसी काबिल व्यक्ति को सौंप दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप वाईन्ड अप करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खुद माना है कि इस बजट में कुछ कमी रह गई है। मैं आशा करता हूं कि जो कमियां रह गई हैं उनको ये दूर करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी अब जीन्द डिस्ट्रिक्ट के मुख्य मंत्री हो गए हैं। ठीक है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के साथ इनके अपने पुराने पैतृक सम्बन्ध हैं। वहां पर चीनी मिल और चावल की मिल लगाई जा रही हैं। हमें इस बात की खुशी है कि उस इलाके के लिए अच्छे काम हो रहे हैं। आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि हमारा जीन्द जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है। (विघ्न) मैं इस बात को मानता हूं कि पीछे जीन्द जिले की जो नुमाइन्दगी रही, वह ढीली रही। जीन्द का जो एक मंत्री रहा उसको बंसी लाल जी भी अपने पास रखने में लगे रहे लेकिन वह डटा नहीं। बाद में चौटाला साहब ने उसको डाटने की कोशिश की लेकिन इनके साथ भी वे नहीं डटे। बाद में वे कांग्रेस में आये और वह कांग्रेस में भी नहीं डटा। उसके न डटने से चुनावों में जीन्द जिले में कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 1966 में जब हरियाणा अपने अलग अस्तित्व में आया था तो जीन्द जिला उसी वक्त से अपने अस्तित्व में है। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जीन्द जिले में सीवरेज की बहुत बुरी हालत है। (विघ्न) कुछ भाई बैठे बैठे कह रहे हैं कि जब मैं मंत्री रहा तो मैंने क्या किया। मैं इन भाईयों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा जब मैं मंत्री था तो उस वक्त मैंने वहां की सीवरेज के लिए एक प्रोजेक्ट शुरु करवाया था। उस पर काम करवाने के लिए 4 करोड़ रुपये भी दे दिए थे। बाद में बंसी लाल जी की और चौटाला साहब की सरकार आ गई जिस कारण वह काम बीच में रुक गया। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : जब इस सरकार ने पीछे सत्ता संभाली तो उस वक्त यह महकमा मेरे पास था। मैंने उस वक्त जीन्द जिले की कमेटी को 30 लाख रुपये की ऐड दी थी।

श्री राम कुमार कटवाल : जब मांगे राम जी मंत्री थे तो उस वक्त इन्होंने अग्रोहा मैडिकल कालेज अग्रोहा में खुलने दिया। उसे इन्होंने जीन्द में क्यों नहीं खुलवाया। ये गलत बात कह रहे हैं कि जब ये लोग सरकार छोड़कर गए थे तो उस वक्त 500 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में था। ऐसी गलत बात कह कर ये सदन को गुमराह न करें। जीन्द जिले का इनके वक्त में ही बहुत बुरा हाल हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है आपकी पार्टी के दूसरे 11.00 बजे लोगों ने भी बोलना है। इसलिए आप अपनी बात को समाप्त करें। वैसे तो जितना टाईम आपकी पार्टी का अलॉट किया हुआ है उतना ही आपको मिलेगा जितना ज्यादा आप बोलेंगे वह टाईम आपकी पार्टी के टाईम में से कट जाएगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं यहां पर हाउस में एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी जनता के लाभ की चीज है वह की जाए, चाहे सीवरेज है, चाहे सड़क है, चाहे वह होस्पीटल या दूसरी जरूरत की चीजें हैं वह सब होनी चाहिएं। सरकार बनने के बाद जनता को सुविधा देने के लिए सरकार में यह नहीं होना चाहिए कि पिछली सरकार ने यह काम शुरू किया

[श्री मांगे राम गुप्ता]

था इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम जीन्द में राजपुरा गांव में पौलिटैक्नीक कालेज मन्जूर करके गए थे वह वर्ल्ड प्रोजैक्ट की स्कीम है और इसके लिए पैसा भी अलॉट हुआ पड़ा है, गांव की 25 एकड़ जमीन भी सरकार को ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन आज तक वह पोलिटैक्नीक कालेज नहीं बन पाया है। इसका कारण सिर्फ यह है कि यह चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में मन्जूर हुआ था। कल मुख्य मन्त्री जी जिक्र कर रहे थे कि पत्थर लगे रह गए तो अगर सरकार उन पर काम नहीं करवाएगी तो वे बनेंगे कैसे ? अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जो चीजें सरकार से सैंक्शन हो चुकी हैं चाहे वे किसी भी सरकार के समय में हुई हों, चाहे चौधरी देसी लाल जी की सरकार के समय में हुई हों चाहे चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में हुई हों वे सारी चीजें हरियाणा के लोगों के लिये हैं और उन सब को सरकार द्वारा बनवाया जाना चाहिए तथा सारा काम नेक नीयती से करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास करता हूं तथा मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्तमान सरकार ठीक चल रही है और यह सरकार सभी को एक नज़र से देख कर काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं तथा आपने बोलने के लिए मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बलवन्त सिंह (सढौरा, अनुसूचित जाति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट इस सदन में पेश किया है उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस सदन में पहली बार मैम्बर चुन कर आया हूं इसलिए अगर कोई असंगत बात जाने-अनजाने में मुझ से निकल जाए तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जिस संयत ढंग से तथा सुनियोजित तरीके से बजट तैयार किया है अगर उस पर नज़र डाल कर देखा जाए तो यह पता चलता है कि राज्य ने चहुंमुखी विकास किया है। उसके वार्षिक प्लान में 2530 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो कि वर्ष 1999-2000 की संशोधित व्यवस्था से 39.50% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में पावर, सिंचाई, सड़कों और परिवहन के लिए अधिकाधिक प्राथमिकता दी गई है तथा उसके लिए 1632.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जो कुल प्लान व्यवस्था का 64.05 है अर्थात् बिजली के लिए 626.75, इरीगेशन के लिए 506.22 करोड़ और बाढ़ नियन्त्रण के लिए 20 करोड़ रुपये शामिल है जिससे हरियाणा प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। स्पीकर सर, इसी बजट में सामाजिक सेवाओं के लिए 657.45 की राशि का प्रावधान किया गया है खासकर बुढ़ापा पैंशन, विकलांग, और विधवाओं आदि के लिए भी 320.23 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है। हर व्यक्ति के लिए चाहे वह गरीब है अथवा अमीर है इस बजट में प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए 160 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए 58 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैडिकल शिक्षा के लिए 53.40 करोड़ रुपये और शहरी विकास के लिए 18.81 करोड़ रखे हैं। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हरियाणा की सारी इकोनोमी कृषि पर निर्भर करती है। इसके लिए 111.80 करोड़ रुपए रखे हैं। जो सहायता प्रोजैक्ट सरकार के चल रहे हैं उसके लिए इस बजट में पिछले वर्ष के 624.47 करोड़ रुपए के मुकाबले में 1127.96 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है यानि कि दुगुना पैसा रखा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सढौरा की तीनों तरफ शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हैं। जब बरसात होती है तो उनमें से निकलने वाली भंडियों से हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है। वहां पर जो सोम नदी है उसके पास

20-25 गांव जैसे धनौरा, माजरी, भगवानपुर, भटुवाला, सतावड़ी, हपालगढ़, शेरगढ़, सुन्दर, बहादुरपुर आदि-आदि हैं। इसमें पानी ज्यादा आने की वजह से वे दूसरे इलाकों से कट जाते हैं। इसी तरह से बेमना छोटी नदी है उसमें भी पानी आने की वजह से डैहर, अम्बली, गनौली, गहौली, बेरखेड़ी, ओखल, अडबोन, लखनौरा, अन्धेरी, सादिकपुर आदि गांव हैं जो कट जाते हैं। इन दोनों नदियों पर पुल बनवाने की कृपा करें। सर, जब इन नदियों में पानी आ जाता है तो वहां के किसान को अपनी फसल 20 किलोमीटर दूर से नारायणगढ़ होकर ले जानी पड़ती है। मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि वहां पर दो पुल बनवाने की कृपा करें और नदियों में तेज बहाव से गांव न कटें इसका कोई प्रावधान करें। अध्यक्ष महोदय, राज्य में 45 सौ किलोमीटर सड़कों की रिपेयर, सड़कों का पुनर्निर्माण, और कच्ची सड़कों को पक्का करने का विचार है यह बहुत ही सराहनीय काम है। स्पीकर सर, मेरे कहने का भाव है कि 2000-2001 का जो बजट पेश किया गया है यह बड़ी ही समझदारी और बड़ी सूझबूझ से तैयार किया गया है। इसमें हर वर्ग की भलाई का ध्यान रखा गया है। यह बजट कर रहित भी है जिसके लिए इस सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है। मैं वित्तमंत्री जी का और मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया बजट पेश किया है। धन्यवाद।

श्री देवराज दीवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इस महान सदन के सभी सदस्यों को दसवीं विधान सभा में चुनकर आने के लिए बधाई देता हूं। दसवीं विधान सभा में जो नयी सरकार व नये साथी आए हैं मैं उन सभी को अपनी बधाई देता हूं। वित्त मंत्री जी ने कल जो बजट पेश किया है अब मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट सरकार का एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार की नीति, नीयत और उसकी कारगुजारी को शीशे की तरह दर्शाता है। यह बजट बीसवीं सदी का आखिरी और 21वीं सदी का पहला बजट कहा जा सकता है। वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट पेश किया है इसमें कोई शक नहीं कि यह बजट पूर्ण रूप से राज्य का चारों तरफ से विकास करेगा। इसलिए इस बजट की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को देखते हुए कोई भी सरकार अपनी नीतियां तैयार करती है, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करती है और यह बजट यही सारी बातें दर्शाता है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट जनता की गहन अनुभूतियों का आईना है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कर मुक्त एवं संतुलित बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं। इस बजट को देखने से यह आभास होता है कि चुनावों में इस सरकार ने जनता से जो वायदे किये उन वायदों को मूर्त रूप देने का काम सरकार ने इस बजट में किया है। इस बजट में प्रान्त के चहुमुखी विकास तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने अपना संकल्प व्यक्त किया है। आज समय की मांग है कि सरकार कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय ले जिनसे भविष्य में अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। सरकार को आर्थिक एवं बुनियादी क्षेत्रों के विकास की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। सरकार ने अंतर राज्य करों में समानता लाकर तथा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो नयी औद्योगिक नीति घोषित की है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। गन्ने का भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करके जहां गन्ना उत्पादकों को लाभ दिया गया है वहीं यूरिया एवं डी०ए०पी० खाद के मूल्य में छूट देकर अन्य किसानों को भी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम इस सरकार ने किया है और अपनी किसान समर्थित छवि को सरकार ने निखारा है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सरकार द्वारा किये गये विशेष प्रयासों के कारण ही केन्द्रीय पूल से बिजली का उत्पादन 19% से बढ़कर 27% हो गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, दीवान साहब अपनी लिखी हुई स्पीच यहां पर पढ़ रहे हैं। वे इसको सदन के पटल पर रख दें और इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। वह ठीक स्पीच दे रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह नियमों में भी लिखा हुआ है कि यहां पर कोई सदस्य अपनी लिखी हुई स्पीच नहीं पढ़ सकता। ये अपनी स्पीच पढ़ रहे हैं इसलिए क्यों न इनकी स्पीच को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : वे केवल हैडिंग देख रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें और उन्हें बोलने दें।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि आज के युग में बिजली की कितनी आवश्यकता है ? इसमें संदेह नहीं कि बिजली का उत्पादन हमारे प्रदेश में आवश्यकता से काफी कम है। इस कारण काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था को सुधारने के लिए जो कदम सरकार ने अभी तक उठाए हैं वह सराहनीय हैं। सप्लाई में सुधार करके काफी हद तक बिजली की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। खेत में पानी के बिना किसान अपनी पैदावार को बढ़ा नहीं सकता। सिंचाई की सुविधा किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। सिंचाई के महत्व को मद्देनजर रखते हुए नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए व नहरों की सफाई का कार्य करवाने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है जिसके लिए इस बजट की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। प्रदेश के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2000-2001 में सड़कों को मजबूत करने तथा सड़कों की मरम्मत के लिए करीब 582 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। सोनीपत राठधना सड़क को मेरठ सोनीपत सड़क से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने प्रशासकीय मंजूरी दे दी है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सड़क जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सोनीपत राठधना रोड काफी हद तक बन चुकी है थोड़ी सी बाकी रहती है और इसमें कई जगहों पर दो-दो ढाई-ढाई फुट के गड्ढे हैं यह थोड़ा सा काम भी पूरा कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पुलिस कर्मी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर पुलिस कर्मी के परिवार को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का जो निर्णय लिया है, वह प्रशंसनीय है और इसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। चंडीगढ़ के सैक्टर-39 में 504 नये सरकारी मकान बनाने का प्रस्ताव किया गया है जो कि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की कठिनाई के प्रति जागरूकता को जाहिर करता है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में साफ पीने के पानी की व्यवस्था करना बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है इसके लिए सरकार ने 350 गांवों में 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पीने का पानी उपलब्ध करवाने का प्रयास इस बार इस बजट में किया है जो कि बहुत ही जरूरी व सराहनीय कदम है। वर्ष 1999 में सूखे के हालात होने के बावजूद खाद, बीज और पानी की सुविधायें उपलब्ध करवाने के कारण 116 लाख टन तथा 719 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। नये निवेश को आकर्षित करने से व उद्योगों को विकसित करने से 20 प्रतिशत रोजगार के मौके बढ़ेंगे। नई औद्योगिक नीति नवम्बर-99 में घोषित की गई है, वह एक आदर्श नीति है जिससे राज्य का आर्थिक विकास होगा तथा लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि नयी औद्योगिक नीति प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में

सरकार ने नए-नए अस्पताल, डिसपैंसरियां और सब-सैंटर खोलने के अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। इसके साथ ही महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय की मैचिंग ग्रान्ट को बहाल करके चिकित्सा सेवा के लिए सोने पर सुहागे का एक और सराहनीय कार्य किया है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से 30 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को स्व-रोजगार के साधन जुटाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार के प्रयासों की मैं दिल से सराहना करता हूं। ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की राशि प्रदान करना तथा शूरवीर घायल सैनिकों को 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक की धनराशि का दिया जाना उन शूरवीरों की वीरता का सम्मान है जिसके लिए यह सरकार अत्यन्त सराहना की हकदार है क्योंकि ऐसा करके इस सरकार ने देश की एकता और अखण्डता के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों और उनके परिवारों को एक सम्मान दिया है। हरिजन कन्यादान स्कीम के तहत 5100/-- रुपये की राशि हर गरीब हरिजन कन्या की शादी हेतु उसके माता-पिता को प्रदान कर सरकार ने दलितों को विशेष सम्मान प्रदान किया है जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। वृद्धावस्था पैंशन, विकलांगों तथा विधवाओं और बेसहारा लोगों को दी जाने वाली पैंशन की राशि दुगुनी करके सरकार ने महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। जिसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्त होने के फलस्वरूप नगरपालिकाओं को आर्थिक मदद देने के लिए 23.84 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया है तथा फालतू घोषित किए गए तीन हजार से अधिक कर्मचारियों को अन्य विभागों में नौकरियों पर रख कर सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट एक संतुलित बजट है जिसमें राज्य के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए किसी भी वर्ग पर करों का कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला है और गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, उद्योगपति की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए एक सराहनीय बजट प्रस्तुत किया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। यह बजट समाज के हर वर्ग को एक नई दिशा देने में सक्षम होगा तथा राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक शानदार तथा विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी की कुशलता तथा बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दीवान साहब, वाईंड अप कीजिए।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें जो शमशान घाट हैं वे ऐसे स्थानों पर हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो वहां पर जाने के लिए कच्चे रास्ते तो होते हैं उनमें दो-दो फुट पानी खड़ा हो जाता है आप जानते हैं कि हर इन्सान को इस संसार से एक दिन तो अवश्य जाना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन रास्तों को पक्का करवाया जाये। मेरे हल्के के गांव हैं चिटाना, पिनाना, जुओं, माहरा, मोहाना, चैनातितारपुर, खिरजपुर, जाट माजरा, सादलखुर्द, सांबलकलां, बोहला, बैयांपुर तथा चटिया औलिया। इन गांवों के शमशान घाट को जाने का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्षा के दिनों में शमशान घाट को जाने वाले रास्ते में पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे मृतक को शमशान घाट तक ले जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कई बार तो अर्थी उठाए लोगों के फिसल जाने के कारण काफी दिक्कत हो जाती है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हल्का सोनीपत में सभी गांवों के शमशान भूमि को जाने के रास्ते शीघ्र से शीघ्र पक्के करवाए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी का ध्यान गांव की चौपालों की मुरम्मत और नवीनीकरण की ओर दिलाना चाहूंगा। गांवों में चौपालों की हालत बहुत ही

[श्री देवराज दीवान]

खस्ता है और पिछले कई वर्षों से इनकी मुरम्मत आदि के लिए आवश्यकता के अनुसार राशि का आबंटन नहीं किया गया। मेरे हल्के सोनीपत के गांव मोहाना में बाल्मीकि, धानकान चौपाल, सांदलकलां में हरिजन, धानकान चौपाल, गांव चटाना में बाल्मीकि चौपाल, हरिजन चौपाल, बी०सी० चौपाल, गांव जाहरी में बाल्मीकि चौपाल, गांव ठरू में हरिजन चौपाल, बाल्मीकि चौपाल, गांव शहजादपुर में हरिजन चौपाल, गांव उल्देपुर में हरिजन चौपाल, गांव पिनाना में धानकान चौपाल, बी०सी० चौपाल, गांव जुंआ में बी०सी० चौपाल, जुंआ-II में हरिजन चौपाल, बी०सी० चौपाल, गांव सांदलखुर्द में बी०सी० चौपाल, गांव थरिया में बी०सी० चौपाल, गांव बोहला में हरिजन चौपाल, बाल्मीकि चौपाल, गांव कालूपुर में धानकान चौपाल और हुल्लाखेड़ी में बी०सी० चौपाल का मुरम्मत कार्य तथा निर्माण कार्य होना बहुत ही आवश्यक है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन चौपालों की मुरम्मत वर्षा ऋतु के आरम्भ होने से पहले करने के निर्देश जारी करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे हल्के सोनीपत की गोहाना रोड, बड़वासनी माहरा, पिनाना से बोहला, चटाना से जुंआ, सलीमपुर ट्राली, बोहला-पिनाना, गोहाना मण्डी से झाजी, जुंआ से माहरा की सड़कों के लिए एच०एस०एम०ए० की मंजूरी आ चुकी है इसलिए इन सड़कों को जल्दी ही पूरा करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, सोनीपत हल्के के एप्रोच रोड गांव किलोड़द के लिए, गांव जाहरी से गांव थरिया तक, एप्रोच रोड गांव हुल्लाहेड़ी के लिए, गांव सांदलकलां से गांव थरिया तक, गांव सांदलकलां से सांदलकलां रेलवे स्टेशन तक, गांव जाहरी से कामी रोड तक, गांव सलारपुर माजरा से पिनाना तक, गांव जुआं से पांची तक वाया माहरा, गांव शहजादपुर से गांव किलोड़द तक, पुरखास अड्डा सोनीपत से लेकर चटिया गांव तक, चटिया गांव से माहरा गांव तक लिंक रोड, जाहरी-थरिया लिंक रोड की मुरम्मत करवाने के लिए भी मेरा सरकार से अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हमारे सोनीपत शहर में एक बाई पास है उसका थोड़ा सा काम बाकी है जिसके बारे में मैंने कल भी मुख्य मंत्री महोदय को बताया था। उस बाई पास को शीघ्र ही पूरा करवाया जाए जिससे सोनीपत का ट्रैफिक बाहर का बाहर हो जाएगा और इससे एक्सीडैंट्स कम होंगे तथा रोजाना लगने वाले जामों से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे हल्के में 220 के०वी० सब-स्टेशन चालू हो गया है लेकिन उसके चालू हो जाने के बाद भी उसमें थोड़े सुधार की आवश्यकता है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें थोड़ा सुधार किया जाए। अन्त में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि ककरोई और लहराड़ा गांव के खेतों की सिंचाई के लिए बुर्जी नं० 13800 पर एक मोगे की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके निर्माण के कार्य को शीघ्र अति शीघ्र कराया जाए।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उनके जो भी सुझाव अपने हल्के के हैं वे हमें लिखित में दे दें, जो बोलने पर रह गये हों। दीवान साहब, आप भी अपने सुझाव मुझे दे दें। हम सभी सदस्यों के सुझावों पर गौर कर लेंगे। चाहे वह सुझाव किसी भी मैंबर के हों।

श्री ओम प्रकाश जिंदल (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जिनके बारे में बजट में चर्चा नहीं की गई है या की भी है तो नाम मात्र की है। बजट में बहुत सी कमियां रह गई हैं। जैसे सेल्जटैक्स बारे मेरा सुझाव है कि नई रेट लिस्ट 4 मार्च, 2000 से लागू की गई है। इसे एक अप्रैल, 2000 से लागू किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों को असैसमैंट करने में परेशानी न हो क्योंकि सरकारी वित्त वर्ष भी एक अप्रैल से ही शुरू होता है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हरियाणा में क्रशरों की रोड़ी पर और बजरी पर सेल्ज टैक्स 15%

से बढ़ाकर 20% कर दिया है जबकि मार्बल पर सिर्फ यह टैक्स 10% है और इसका उपयोग अमीर लोगों और व्यापारियों द्वारा किया जाता है। जबकि बजरी और रोड़ी का उपयोग गरीब आदमी ही करता है। इसलिए इस पर बढ़ाया गया टैक्स वापिस लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में दालों व अनाज पर 4% टैक्स लगाया गया है जबकि दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में इन पर कोई टैक्स नहीं है। क्योंकि यह आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इन वस्तुओं पर टैक्स समाप्त किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी थी उस समय हलवाईयों ने खुशी से मिठाइयां बांटी थीं। लेकिन अब उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया और अब वे चौटाला साहब को गालियां दे रहे हैं। इस बात पर भी मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी ध्यान दें क्योंकि वे छोटे व्यापारी हैं, टैक्नीकल आदमी हैं और सरकार ने दूध से बनी वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया है। इससे उनके रोजगार पर असर पड़ सकता है। इससे वे लोग बहुत परेशान हैं इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। **(इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री रामपाल माजरा पदासीन हुए।)** सभापति महोदय, हरियाणा सरकार ने इस समय ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में आई०ए०एस० अफसरों को नियुक्त कर रखा है। जबकि वहां पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स होने चाहिएं ताकि लोगों को सही न्याय मिल सके। क्योंकि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स ठीक ढंग से न्याय करते हैं। आई०ए०एस० अफसर सरकार से संबंधित होते हैं और सरकार के कहने के मुताबिक ही कार्य करते हैं। सरकार के कहने पर वे जिसको चाहें उसको सजा दे देते हैं और जिसको चाहे छोड़ देते हैं। इसलिए वहां पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स की ही नियुक्ति होनी चाहिए और हरियाणा की जनता को न्याय मिलना चाहिए। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जो अधिकारी ट्रिब्यूनल कोर्टस में बैठते हैं वे वहां पर स्थाई तौर पर नहीं बैठते बल्कि सप्ताह में 2-3 घंटे ही वहां बैठते हैं और व्यापारियों को चण्डीगढ़ आना पड़ता है। इससे उनका काफी पैसा और समय बरबाद होता है। इसलिए वहां पर पूरे टाईम के लिए अधिकारी बैठाये जायें। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो तारीख व्यापारियों की पेशी की दी जाती है उस दिन उसकी सुनवाई नहीं होती। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, यदि अधिकारियों की कमी है तो और भर्ती करने चाहिएं। लेकिन जो व्यापारी टैक्स देते हैं उन्हें पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर उनको कोई सजा देनी है तो वह जल्दी ही मिलनी चाहिए। उनके बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगने चाहिएं। बहस होने के बाद भी व्यापारियों का फैसला काफी समय तक रिलीज नहीं किया जाता। जबकि फैसले की कापी व्यापारियों को एक हफ्ते के अंदर मिल जानी चाहिए। सेल्ज टैक्स कमिश्नर, चण्डीगढ़ के दफ्तर से व्यापारियों को कोई स्पष्टीकरण संबंधी सूचना नहीं मिलती है। सेल्ज टैक्स से संबंधित सारी सूचनाएं व्यापारियों को उपलब्ध कराने का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए। सभापति जी, एक तरफ तो सरकार आर्थिक विकास की गति को तेज करना चाहती है दूसरी ओर सरकार नये उद्योगों पर दी जाने वाली सेल्ज टैक्स की छूट को वापिस लेना चाहती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार कैसे उद्योगों को बढ़ावा देगी। इसलिये किस तरह से व्यापार बढ़े और उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, इसके लिये सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। सभापति जी, मुख्य मंत्री जी ने जुलाई, 1999 में शपथ लेते ही अग्रोहा धाम में जाकर अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रान्ट बहाल करने की एक पब्लिक जनसभा में घोषणा की थी और प्रो० सम्पत सिंह के हल्के के लोगों ने तथा अग्रोहा समाज ने खुशियां मनाई थीं। प्रो० सम्पत सिंह का वहां हल्का लगता है। वहां के लोगों ने चौटाला साहब को वोट देकर कामयाब भी किया है। अग्रोहा मैडिकल कालेज की 12 करोड़ रुपये की ग्रान्ट बनती है। मुख्य मंत्री जी की घोषणा से अग्रवाल समाज और वित्त मंत्री जी के हल्के के लोग बहुत खुश हुए क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी ने यह ग्रान्ट बन्द कर रखी थी। उन्होंने यह ग्रान्ट इसलिये बन्द कर रखी थी क्योंकि वह महाराजा अग्रसेन के नाम से

[श्री ओम प्रकाश जिंदल]

चिढ़ते थे। वे चाहते थे कि अग्रोहा मैडिकल कालेज को एक पैसा भी न दिया जाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस कालेज की ग्रान्ट तो बहाल कर दी लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी इस कालेज के विकास के लिये केवल मात्र 50 लाख रुपये की राशि दी गई है। (शोर) जब भी इस बारे में बात करते हैं तो यही बात मिलती है कि हम ग्रान्ट देने को तैयार हैं। यह ठीक है कि काम गवर्नमैंट ने कराना है चाहे वह एक महीने में करे, चाहे 10 साल में करे। काम पी०डब्ल्यू०डी० ने कराना है और वहां पर सामान रखा है और काम अधूरा पड़ा है। जब तक विकास का काम पूरा न हो जाए तब तक इस मैडिकल कालेज की बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैडिकल की वहां कोई क्लासिज़ नहीं लग सकती। सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन है क्योंकि वे वरिष्ठ सदस्य भी हैं और अग्रोहा इनका हल्का भी रह चुका है और इन्होंने ही इस अग्रोहा मैडिकल कालेज के लिये ज़मीन दिलाई थी तथा चौधरी देवी लाल जी ने ही इसकी फाउंडेशन रखी थी, हमारे अग्रवाल समाज ने करीब 15 करोड़ रुपया इस कालेज में लगा दिया है और अब गवर्नमैंट की तरफ से ही कमी है। ये अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। इसलिए ये जल्दी से जल्दी इस कालेज की ग्रान्ट रिलीज़ करायें क्योंकि तकरीबन 100 किलोमीटर के एरिया में मैडिकल कालेज की कोई सहूलियत नहीं है। हरियाणा के अन्दर चार मैडिकल कालेज होने चाहिएं। रोहतक, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़ और अग्रोहा मैडिकल कालेज, हिसार में यह सुविधा होनी चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश के सब लोगों को मैडिकल कालेज की सुविधा मिल सके। इसलिए मैं मुख्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बकाया राशि जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाये ताकि मैडिकल कालेज का कार्य जल्दी से जल्दी शुरु किया जा सके जिससे आम जनता को फायदा हो सके।

सभापति महोदय, सरकार ने एक स्कीम के तहत अनुसूचित जाति और जन-जाति की लड़कियों को उनकी शादी के समय शगुन के नाम पर 5100/- रुपये देने की घोषणा की है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि सरकार की यह स्कीम सिर्फ घोषणामात्र हो कर रह गई है। इससे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। (विघ्न) जब ये लोग पैसा लेने के लिए जाते हैं तो वे चक्कर काटते रहते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाता। अतः इस स्कीम के बारे में मेरा सुझाव है कि सरकार इस स्कीम को इन लोगों तक इस तरह से पहुंचाए ताकि उनको समय पर पैसा मिल सके और उन भाइयों को इसका फायदा हो सके।

सभापति महोदय, अब मैं हिसार हल्के की समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिसार शहर की सड़कों की बहुत बुरी हालत है और उनमें जगह जगह पर खड्डे पड़े हैं। मार्केट कमेटी के पास जो सड़कें हैं उनकी मुरम्मत इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कमेटी के पास पैसा नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार वहां पर पैसे देने का प्रबंध करे ताकि शहर की सड़कें ठीक हो सकें।

सभापति महोदय, अब मैं हिसार शहर में पीने के पानी की कमी के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर पीने के पानी के लिए जो टैंक बनाया गया था वह आज से 20 साल पहले बनाया गया था। उसकी कैपेसिटी उस समय की आबादी को देखते हुए बनाई गई थी। उस के बाद शहर की आबादी कई गुणा बढ़ चुकी है जिस कारण अब वहां पर पीने के पानी की बहुत किल्लत हो गई है। (विघ्न) भागी राम जी आप मुझे अपनी बात कहने दें। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हिसार शहर में पीने के पानी की बहुत कमी है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए तुरन्त कदम उठायें ताकि आम जनता को पीने का पानी मिल सके और उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।

सभापति महोदय, हिसार शहर बहुत पुराना होने की वजह से वहां की सीवरेज की लाईन की भी बहुत बुरी हालत बनी हुई है क्योंकि वह बहुत सारी जगहों से टूटी हुई है। सीवरेज लाईन टूटने के कारण वह पीने के पानी की लाईन के साथ मिल गई है जिस कारण लोगों को गन्दा पानी पीने को मिल रहा है। सीवरेज की व्यवस्था जो आज से हिसार में 20-25 साल पहले शुरु की गई थी वह तकरीबन एक तरह से ठप्प हो गई है। इस सीवरेज की गन्दगी सड़क के ऊपर तक आ गई है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हिसार के सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए वहां की मार्केट कमेटी को फण्ड मुहैय्या करवाए जाएं ताकि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। हिसार की जनता वहां पर खुले दरबार में भी इस मांग को कई बार उठा चुकी है। अतः मेरा सरकार से इस बारे में पुनः अनुरोध है कि वहां के सीवरेज सिस्टम को तुरन्त ठीक कराने के लिए विशेष कदम उठायें। सभापति महोदय, हिसार शहर एक बहुत ही भीड़ वाला शहर है। वहां पर लोगों का तंग गलियां होने की वजह से निकलना भी दूभर है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ भी सरकार ध्यान देते हुए इस का कोई हल निकालने की कोशिश करे। चेयरमैन साहब, आपने यहां पर मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री बंसी लाल (भिवानी) : चेयरमैन साहब, मैं दो-तीन प्वाईंट्स पर ही अपनी बात कहूंगा क्योंकि यह नई सरकार का पहला बजट है। सभापति जी, मैं आपके जरिये श्री सम्पत सिंह जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि इन्होंने इस बजट में बिजली के मद के अन्दर 1070.13 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें से तकरीबन 506 करोड़ रुपया तो प्लान साइड में और तकरीबन 562 करोड़ रुपया नॉन प्लान साइड में रखा गया है। नॉन प्लान साइड में अब से पहले सबसिडी तकरीबन 800-850 करोड़ रुपये की थी जो कृषि क्षेत्र को दी जा रही थी। फरीदाबाद के गैस बेस्ड पॉवर प्लांट की 146 मेगावाट की तीसरी यूनिट और पानीपत थर्मल पावर प्लांट की 210 मैगावाट की छठी यूनिट भी चालू हो जायेगी। इससे कम से कम 10 परसेन्ट बिजली फारमिंग सेक्टर को ज्यादा मिल सकेगी। इसके बाद यह सबसिडी बढ़कर 1100-1200 करोड़ रुपये हो जायेगी। सरकार इस सबसिडी को कहां से पूरा करेगी इस बारे में बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री महोदय ने बजट में डब्लू०आर०सी०पी० और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की क्या गारंटी है कि वर्ल्ड बैंक और हरियाणा सरकार में लोन के बारे में समझौता हो भी पायेगा या नहीं हो पायेगा ? इसके अलावा ओटू वीयर जहां पहले थी वहां से अब बन रही है वह 800 मीटर नीचे है। उसकी जो कैपेसिटी कम हुई है वहां सिल्ट आ गई। जो पानी ठहरता था वहां पर फसल काश्त होती है। मैं समझता हूं कि उस पूरी सिल्ट को निकलवाया जाए और उसके 2-4-5 कि०मी० पीछे तक भी अगर जमीन ऐक्वायर करके पानी से भर लिया जाए तो उसमें खासा काम हो सकता है और अच्छी सिंधाई की व्यवस्था हो सकती है। हमने एक बार स्कीम बनाई थी कि रेलवे लाइन तक ओटू वीयर को ले जाएं, अगर आप ऐसा कर सकें या जितना भी उसको बढ़ा सकें, बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा होगा और प्रदेश को उससे फायदा है। चेयरमैन साहब, एक प्वांयट के बारे में मैं और जिक्र करना चाहूंगा। चौधरी सम्पत सिंह जी ने फ्लड प्रोटैक्शन मैयर्ज़ को हाई प्रायोरिटी पर रखा है लेकिन उसके लिए केवल 20 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में रखा है। 20 करोड़ रुपये से फ्लड प्रोटैक्शन का काम नहीं हो सकता है। जहां पर 2700-2800 करोड़ रुपये का काम है वहां पर 20 करोड़ रुपये में कुछ नहीं हो सकेगा। अभी तो उन्होंने बजट में जो प्रावधान रखा है वह बहुत ही कम है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। चेयरमैन साहब, इस बजट में हिसार-घग्गर ड्रेन का जिक्र भी किया गया है और यह ड्रेन बनाने के लिए काफी पैसे की जरूरत होगी।

श्री सम्पत सिंह : चेयरमैन सर, यह तो इनके टाइम से भी पहले से चली आ रही है इसको वर्ल्ड बैंक के साथ टाई-अप करके तथा उनसे लोन सैंक्शन करवाना है। 2700-2800 करोड़ रुपये का अभी जो इन्होंने ज़िक्र किया इसमें और दूसरे प्रोजैक्ट्स भी हैं जो वर्ल्ड बैंक से जब पैसा आएगा तभी पूरे हो पाएंगे। अभी इन प्रोजैक्ट्स के लिए पैसे का अरेंजमैंट नहीं हुआ है अभी तो केवल स्कीमें ही बनी हैं।

श्री बंसी लाल : चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से मैं एक और बात सरकार को कहना चाहूंगा। चार करोड़ रुपये से ज्यादा की जो भी स्कीम होती है वह सी०डब्ल्यू०सी० से मन्जूर करवानी पड़ती है। उसकी क्लीयरैंस अगर ले ली गई है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर क्लीयरैंस नहीं ली तो ले लेनी चाहिए। इस बारे हमने लिखा भी था। अब क्लीयरैंस नहीं ली गई तो बाद में उनके भी चक्कर लगाने पड़ेंगे इसलिए वक्त से क्लीयरैंस ले लें तो अच्छी बात है। सी०डब्ल्यू०सी० जब मन्जूरी करने लगेगा तो वह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की सरकारों से भी पूछेगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को शायद कोई ऑब्जैक्शन नहीं होगा लेकिन मैं समझता हूं कि शायद राजस्थान को ऑब्जैक्शन हो क्योंकि यह आगे जा कर हनुमानगढ़ को डुबोती है। इसमें जो पानी जाता है वह पौल्यूटिड वाटर है। परवाणु, बनूड़ और आगे जा कर राजपुरा डेराबसी की सब फैक्टरियों का गन्दा पानी घग्गर में जाता है और फिर यह आगे जा कर सब से ज्यादा सिरसा के आखिरी हिस्से में नुकसान करता है। साल डेढ़ साल पहले हनुमानगढ़ में इस गन्दे पानी को पीने की वजह से कई मवेशी मर गए थे और लोगों में पीलिये की बीमारी भी फैल गई थी। इस बारे में सी०डब्ल्यू०सी० और राजस्थान गवर्नमैंट से बात करें। राजस्थान गवर्नमैंट की भी इस पानी में भागीदारी है इसलिए वैसे तो उनको भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 2530 करोड़ रुपये का जो प्लान चौधरी सम्पत सिंह जी ने बनाया है यह मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता इस लिए इसको घटाना पड़ेगा और रिवाईज़ करना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2530 करोड़ रुपये ये जुटा पाएंगे। चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री चन्द्र मोहन (कालका) : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वित्तमंत्री जी ने सदन में जो बजट पेश किया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट को पढ़कर के ऐसा लगता है कि इसमें कहीं पर भी किसान भाइयों को, कर्मचारियों को, व्यापारियों को और मजदूर भाइयों को कोई राहत देने का प्रयास नहीं किया गया है। बजट का घाटा 196.77 करोड़ रुपये से आरम्भ होकर 294.56 करोड़ रुपये का अनुमान है। 97 करोड़ रुपये का घाटा खाली छोड़ा गया है। इस घाटे को पूरा करने के लिए खाली पदों की समाप्ति, नए पदों की भर्ती पर रोक, सरकारी खर्चे में कमी और टैक्सों की वसूली करके अतिरिक्त टैक्स जुटा कर पूरी की जाएगी। ऐसा उसमें लिखा गया है। जब ये सरकार बनने से पहले लोगों के बीच में गए थे तो इन्होंने कहा था कि हम भर्ती करेंगे अब ये भर्ती पर रोक लगा रहे हैं। इन्होंने जो वायदे जनता से किए थे उनका क्या होगा ? इसी प्रकार से ये यह बताएं कि सरकारी खर्चों में किस प्रकार से कटौती की जाएगी। कौन से खर्चे कम करेंगे। बजट अनुमानों पर चर्चा की गई लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि चुनावों से पहले जो किसानों के साथ वायदा किया था कि 5वीं स्लैब प्रणाली लागू करेंगे। उसकी भी इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। इसी प्रकार से ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन देने की बात है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो कनैक्शन काट दिए गए हैं उनके बारे में क्या करेंगे। सभापति महोदय, अग्रोहा मैडिकल कालेज के बारे में हमारे कई साथियों ने चर्चा करते हुए कहा है मैं इस बारे में ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में आदरणीय वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी गए थे, उन्होंने वायदा किया था कि जो चौधरी बंसी लाल जी ने राजनीतिक दुर्भावना

करके उसका दर्जा घटाया था उसको बहाल करेंगे । इसके बारे में सरकार की आज क्या मंशा है। मैं यह जानना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, शराब बंदी की आड़ में चौधरी बंसी लाल जी ने 3000 करोड़ रुपए के टैक्स लगाए थे उस बारे में चुनावों से पहले यह सरकार कहती थी कि हम उनको वापिस ले लेंगे। उनके बारे में इनकी क्या मंशा है। इस बारे में भी बजट में कुछ नहीं आया है। मेहरबानी करके क्या ये इस बारे में क्लीयर करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताना चाहूंगा। कालका क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वह पैरीफरी एक्ट की वजह से है। इस ऐक्ट की स्थापना जब चण्डीगढ़ बना था, तब हुई थी। उसके बाद तो सारा इलाका डिवैल्प हो गया है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि यह सैन्टर गवर्नमैंट से लिंकड है। सभापति महोदय, जैसे पंजाब में डेराबस्सी इन्डस्ट्रीयल एरिया को बैकवर्ड एरिया घोषित करके वहां के रहने वालों को सुविधा प्रदान की गई है तो उसी तरह कालका क्षेत्र को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोषित करके वहां के रहने वालों को सुविधा प्रदान की जाए। अगर ऐसा करेंगे तो वहां पर जो रहने वाले हैं उनके ऊपर जो पैरीफरी की तलवार लटक रही है उससे उनको निजात मिलेगी। सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारे यहां पर जितने भी गांव हैं सब में आबादी बढ़ गई है। लाल डोरे की समस्या हर गांव में आती है, कनैक्शन लेने की समस्या आती है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि लाल डोरे को बढ़ाया जाए ताकि वहां के रहने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। इसी प्रकार हमारा मोरनी क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी समस्या नोतोड़ को लेकर है। श्री भजन लाल जी के शासन काल में कंसौलिडेशन का काम शुरू हुआ था लेकिन श्री बंसी लाल जी ने अपने समय में उसको बंद करवा दिया था। मेरा आपकी सरकार से नम्र निवेदन है कि उस काम को वारफुटिंग पर किया जाए, वहां के लोगों को राहत दी जाए। इसी तरह से दून और रायपुर क्षेत्र में एम०पी० ग्रान्ट से सिंचाई के लिए जो ट्यूबवैल्ज लगाए गए थे उनका आज तक कनैक्शन नहीं लगा है। यह बैकवर्ड इलाका है, पहाड़ी इलाका है सरकार को चाहिए कि इस इलाके में टॉप प्रॉयोरिटी पर कनैक्शन दें। इसी तरह से इन्होंने गवर्नर एड्रैस में कहा है कि शहरों को सुन्दर बनाने का प्रयास करेंगे। यह बात सही है कि घरों के बाहर जो एन्क्रोचमैंट है, वह कोर्ट के आर्डर से तोड़ी गई है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उन जगहों को ये वहां के रहने वाले लोगों को सस्ते दामों पर दे सकते हैं ताकि वह जो जगह है उसको वे लोग अच्छी तरह से मैनटेन कर सकें। इससे सरकार का भी फायदा होगा और लोगों का भी फायदा होगा। एक और बात गवर्नर एड्रैस में थी कि गांवों में जो मैचिंग ग्रांट देते हैं उसको बढ़ाया गया है यह तो बढ़िया बात है लेकिन शहरों में जो कॉलोनियां हैं जहां पर पंचायत नहीं है या जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी नहीं है जैसे पंचकुला है तो अगर वहां के लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके सरकार को दें तो क्या सरकार उसके बदले में ऐसे शहरों को मैचिंग ग्रांट देगी ? यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। इसी प्रकार से जहां तक शिक्षा की बात है आपने भी अखबारों में एडवरटाईजमैंट के माध्यम से पढ़ा होगा कि अब टीचर्ज की भर्ती के लिए हरियाणा का डौमीसाइल होने की जरूरत नहीं है। सर, यह तो हरियाणा के लोगों के साथ धोखा है। अगर यहां पर बाहर के लोग आकर लगेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इसी प्रकार से मेरे हल्के में एक बिटना गांव है वहां पर एक आई०टी०आई० का निर्माण चौधरी भजन लाल जी के समय में हुआ था लेकिन बंसी लाल जी की सरकार ने उसका उद्घाटन ही नहीं किया वह अभी भी बंद पड़ी है। मेहरबानी करके सरकार उसको चालू करवाने की कोशिश करें। इसी तरह से जहां तक पीले कार्ड्स का संबंध है इनको बनाने में बहुत धांधली हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हू कि इस बारे में दोबारा सर्वे करवाया जाना चाहिए और ये पीले कार्ड, सही हकदारों के ही बनाये जाने चाहिएं। इसी तरह से बुढ़ापा पैंशन की जहां तक बात है सरकार ने इसको सौ से दो सौ रुपये किया है। अच्छी बात है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको 500 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।

[श्री चन्द्र मोहन]

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने चालीस साल के लोगों को भी इसका लाभ देने के लिए बूढ़ा बना दिया है इसलिए मेहरबानी करके सरकार को इसका भी दोबारा से सर्वे करवाना चाहिए और उचित लोगों को ही इसका लाभ देना चाहिए। मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री अमर सिंह (गुहला, अनुसूचित जाति) : चेयरमैन महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। आदरणीय वित्त मंत्री श्री सम्पत सिंह जी ने कल जो बजट यहां पर पेश किया है मैं उसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी ने हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए हर मद के लिए जो पैसे का प्रोविजन किया है उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। चाहे वह बिजली की बात थी, चाहे वह सड़कों की बात थी, चाहे वह परिवहन की बात या चाहे वह सामाजिक कल्याण की सेवाओं की बात थी, उन्होंने पूरी तरह से सोच समझ कर हर मद के लिए पूरा पैसा दिया है। चेयरमैन साहब, जहां तक बिजली की बात है हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए यहां पर बिजली का होना बहुत ही आवश्यक है। अब हरियाणा के लोग एक ही बात कहते हैं कि जब-जब भी चौ० देवी लाल जी का या चौटाला साहब का राज आया तब-तब हरियाणा के लोगों को पूरी बिजली मिली और इसी कारण आज भी हरियाणा के लोगों को हमारी सरकार पर पूरा विश्वास और भरोसा है। पिछले 6 महीनों में जो सरकार ने लोगों को बिजली दी है उसके लिए हरियाणा के लोग बहुत आभारी हैं। हमारा कैथल एरिया एक कृषि प्रधान एरिया है। वहां पर लोग जीरी और कनक की खेती करते हैं। अभी पिछले दिनों जब लोग कनक की फसल को पानी दिया करते थे तो वे एक ही बात कहते थे कि दस या बारह साल के बाद पहली बार उनको अपनी इस फसल को दिन में पानी देने का मौका मिला है जबकि पहले वे लोग रात को ही पानी दिया करते थे क्योंकि पहले उनको दिन में बिजली ही नहीं मिलती थी लेकिन अब सरकार ने उनको दिन में बिजली दी तो उनको दिन में अपनी फसल को पानी देने का मौका मिला। इसलिए मैं सरकार का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन साहब, बिजली के विकास के लिए बजट में जो पैसा रखा गया है, चाहे वह नये पॉवर हाउस बनाने की बात हो, चाहे वह नयी नयी लाइनें बिछाने की बात हो, सबके लिए पैसा रखा गया है इसके लिए भी मैं सरकार का, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि बिजली की जरूरत को देखते हुए उन्होंने इस बारे में पूरा पैसा रखने की कोशिश की। सर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरा जो गुहला हल्का है वह कृषि के लिहाज से पूरी तरह से जीरी और कनक की खेती पर निर्भर है इसलिए वहां पर बिजली किसान के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे गुहला हल्के में 232 के०वी० का पॉवर हाउस मंजूर है उसके लिए जमीन भी ऐक्वायर हो चुकी है इसलिए कृपया उस पर काम शुरू करवाया जाए ताकि आने वाले दिनों में किसानों को पूरी बिजली मिल सके और खेती के लिए पूरी बिजली उपलब्ध हो सके। सर, मेरे हल्के में तीन सब डिवीजंज हैं। ये हैं-गुहला सब डिवीजन, चीका सब डिवीजन और सीवन 12.00 बजे सब डिवीजन। जब कांग्रेस का राज था उस समय उन तीनों सब डिवीजनों को एक डिवीजन बनाने के लिए ऐस्टीमेट बनाया गया था और वह पास भी हो गया था लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। हमारा सिविल सब डिवीजन कैथल में पड़ता है और उप मंडल गुहला और चीका व सीवन में पड़ते हैं। हमें अपने कामों के लिए गुहला, कैथल और पेहवा, चीका व सीवन के चक्कर काटने पड़ते हैं मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन तीनों सब डिवीजनों को मिलाकर गुहला में एक डिवीजन बनाया जाए। वहां पर लोगों को बिजली की जरूरत है और उसके लिए कभी कैथल के व कभी पेहवा के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेरे हल्के के गांव काटड़ में 33 के०वी० सब स्टेशन का

काम चालू है जीरी का सीजन आने वाला है उससे पहले-पहले इस सब स्टेशन का काम पूरा हो जाए ताकि लोगों को पूरी बिजली मिल सके। जहां तक सिंचाई की बात है मैं धन्यवाद करूंगा कि सिंचाई की तरफ भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है और पूरा पैसा इसकी मद में रखा गया है। मेरे हल्के में मारकण्डा डिस्ट्रीब्यूट्री है जो हमारे यहां के सभी गांवों को पानी देती है जब कांग्रेस के राज में इस डिस्ट्रीब्यूट्री को पक्का किया गया तो पेहवा हल्के के पास इसके बैड को ऊपर उठा दिया गया। इसकी क्षमता 444.9 क्यूसिक्स की है लेकिन इसमें 360 क्यूसिक्स पानी छोड़ा जाता है जिसकी वजह से इस नहर में सिर्फ चीका तक ही पानी पहुंचता है। चीका से आगे के 20-25 गांवों में पानी नहीं पहुंचता। चेयरमैन सर, जब मैं 1991 में विधान सभा सदस्य के रूप में चुनकर आया था तब मैंने कांग्रेस सरकार को फोटो लाकर दी थी। गांवों में लोग बटोड़े वहां रखते हैं जहां पानी न पहुंच सके। हमारे वहां लोगों ने इस डिस्ट्रीब्यूट्री में बटोड़े रखे हुए हैं और वे इसे सेफ जगह मानते हैं क्योंकि वहां पानी कभी पहुंचा ही नहीं। वह फोटो लाकर दिखाने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और यह सोचकर नहीं दिया क्योंकि गुहला हल्के से हमेशा इनका विरोधी उम्मीदवार जीतता रहा है। पीछे श्री बंसी लाल जी की सरकार ने भी मेरे हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस लेवल को दोबारा से चैक करके पानी पूरा का पूरा टेल एंड तक पहुंचाया जाए। बिजली और पानी हमारे यहां के किसान के लिए बहुत जरूरी चीज है। मैं वित्त मंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सड़कों और पुलों की रिपेयर के लिए भी पैसा रखा है। चेयरमैन सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है पिछली सरकार ने मेरे हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा हल्का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पिछली सरकारों ने एक नया पैसा भी मेरे हल्के की सड़कों के लिए नहीं दिया। मैं चौटाला साहब का धन्यवाद करता हूं कि उनके मुख्य मंत्री बनने के बाद मेरे हल्के की कुछ सड़कों की मरम्मत हुई है मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे हल्के की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि बाढ़ के कारण पूरे हल्के की सड़कों का बुरा हाल हो जाता है कुछ सड़कों की रिपेयर हुई है लेकिन काफी सारी सड़कें अभी भी टूटी-फूटी पड़ी हैं। जहां तक कृषि का सवाल है मैं पहले भी कह चुका हूं कि पूरा जिला कैथल या गुहला हल्का कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे है और पूरा उत्पादन देता है। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बिजली और पानी की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये ताकि मेरे हल्के के किसानों को कृषि की तरफ ध्यान देने में कोई कठिनाई न आ सके। चेयरमैन सर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव से पहले 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के तहत खुले दरबार में कैथल शहर में सीवन अनाज मण्डी की मन्जूरी दी थी। अगर उस मण्डी को बनाने का काम सरकार शुरु कर दे तो मैं बड़ा धन्यवादी हूंगा। इसके अलावा मेरे हल्के में चीका मण्डी की मन्जूरी सरकार की तरफ से हो चुकी है और उसकी जमीन भी ऐक्वायर हो चुकी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस साल में ही चीका मण्डी बनाने का काम शुरू किया जाये। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं सरकार को एक बात और कहना चाहता हूं। गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है परन्तु पिछले सीजन में जो गेहूं की परचेज की गई थी चाहे वह कैथल में हो, चाहे पुण्डरी में हो, चाहे गुहला में हो, वह सारा गेहूं वहां के भण्डारों में ही पड़ा है केन्द्र सरकार ने उस गेहूं को वहां से अभी तक नहीं उठवाया है। नई कनक आयेगी तो उसका भण्डारण कहां किया जायेगा ? इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि केन्द्र सरकार से अनुरोध करके पुरानी गेहूं को भण्डारों में से उठवाया जाये ताकि नई गेहूं के भण्डारण में कोई दिक्कत न हो सके। चेयरमैन सर, मेरे हल्के गुहला में गुहला सब डिवीजन है और वहां पर मार्केट कमेटी है। परन्तु उस मार्केट कमेटी में फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है। इसलिए जब भी कभी कनक के सीजन में आग लग जाती है तो हमें कैथल या पेहवा से फायर ब्रिगेड मंगानी पड़ती है। परमात्मा न करे ऐसा हो परन्तु कनक के सीजन में अक्सर ऐसा हो जाता है।

[श्री अमर सिंह]

फायर ब्रिगेड के लिए हमने पैसे भी जमा करवा रखे हैं सिर्फ सरकार ने मंजूरी ही देनी है। अगर सरकार वहां पर फायर ब्रिगेड स्टेशन खोलने की मंजूरी दे देती है तो किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। इस बजट में बाकी सभी चीजों के लिए काफी पैसा रखा है इसमें चाहे समाज-कल्याण हो, चाहे दूसरी चीज हो। हरियाणा प्रदेश के लिए वर्तमान सरकार ने एक अच्छा बजट पेश किया है। चेयरमैन सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जोकि खासकर हमारे हरिजन भाइयों के लिए है। आज हरियाणा के पूरे हरिजन समाज ने सरकार को 17 में से 14 सीटें दी हैं। कांग्रेस पार्टी जो आज तक ढिंढोरा पीटती रहती थी कि हम हरिजनों का विकास करेंगे लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने हरिजन समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। आज सारे हरियाणा का हरिजन समाज इस सरकार से जुड़ा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह हरिजनों के कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शादी लाल बतरा जी बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन सर, विधान सभा सचिवालय की तरफ से एक पत्र हर सदस्य को मिला है जोकि regarding 'Survey on the Review of the Indian Constitution' है। सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह मुद्दा भारत के संविधान को बदलने का है। इस पर बराबर चर्चा होनी चाहिये। यह देश के दलितों और गरीब लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करने की साजिश है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हाउस की कार्यवाही स्थगित करके संविधान के विषय पर चर्चा होनी चाहिये और मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे एक प्रस्ताव पारित करें कि हिन्दुस्तान के संविधान को जिसे डा० बी०आर० अम्बेडकर ने बनाया था उसे बदलना नहीं चाहिये। इस पर चर्चा होनी चाहिए और सभी सदस्यों को इस विषय पर बोलने का समय मिलना चाहिये।

श्री सभापति : देखिये दलाल साहब, इस पत्र के द्वारा सिर्फ व्यक्तिगत राय ही पूछी है। हाउस से इस बारे में नहीं पूछा गया है। केवल व्यक्तिगत राय जानने के लिए ही यह पत्र सदन में बंटवाया गया है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है।

श्री धीरपाल सिंह : सभापति महोदय, इस सरकुलर का अभिप्राय व्यक्तिगत रूप से सबकी राय जानना है इसमें डिस्कशन का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सभापति : जिस इंस्टीच्यूशन ने आपको यह लैटर भेजा है, आप उसको अपनी राय भेज दें, इसमें डिस्कशन का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, सरकुलर का मतलब प्रत्येक मैम्बर से राय जानना नहीं होता इसलिए इस मुद्दे पर ओपन डिसकशन करवाई जाए।

श्री सभापति : किसी इंस्टीच्यूशन ने आपकी इंडीविजुअल राय जाननी चाही है, इस बारे में हम कोई प्रस्ताव नहीं पास करना चाहते हैं।

श्री धीरपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि ये पहले इस लैटर को अच्छी तरह से पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है बीफोर 15-3-2000 और यह 15-3-2000 आज ही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि इसमें राय जानने की बात है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * *

श्री सभापति : कर्ण सिंह दलाल जी जो कुछ भी कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी राय दें इसलिए आप इसमें अपनी राय लिखकर भेज दें। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति महोदय, आज आदरणीय सम्पत सिंह जी की तरफ से लैटर आया है कि आज आप सबका डिनर है तो आप इसके बारे में भी हमारे ओपीनियन जानना चाहेंगे कि हम जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह क्वैश्चमेयर है कोई हाउस का एजेन्डा नहीं है। कर्ण सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है वह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम इससे अनकन्संर्ड नहीं रह सकते। इनका सुझाव है कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। आज संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है।

श्री धीरपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई एजेन्डा नहीं है तो इस पर डिस्कशन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भूपेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं इस कागज की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कर्ण सिंह दलाल ने जो मुद्दा उठाया है वह पूरे हरियाणा और पूरे हिन्दुस्तान का मुद्दा है। (शोर) हमारा काम संविधान की रक्षा करना है, संविधान के हिसाब से ही हम सब यहां पर बैठे हैं।

श्री सभापति : हुड्डा साहब आप बैठिए। (शोर) एक इंस्टीच्यूशन आपकी राय जानना चाहती है आप लिखकर बाई पोस्ट भेज दें, केवल इतनी सी यह बात है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * *

श्री सभापति : जो कुछ भी कर्ण सिंह दलाल जी कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति महोदय, पहले आप मेरी बात तो सुनें। उसके बाद आप जो भी फैसला करें, वह ठीक है।

श्री सभापति : दलाल साहब आपकी बात सुन ली। आपकी जो भी ओपीनियन है वह आप बाई-पोस्ट भेज देना। इंस्टीच्यूशन आफ पार्लियामैंट्री अफेयर्ज ने जो इंफार्मेशन भेजी है दलाल साहब वह आपको दे दी गई है और आपने इस बारे में जो भी ओपीनियन देनी है वह बाई-पोस्ट भेज देना। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, अब बजट पर बहस चल रही है। इसलिए अब किसी दूसरे मुद्दे पर बहस नहीं हो सकती। अगर मेरे विपक्ष के भाइयों को कोई और बात करनी है तो वह किसी और समय कर लेंगे। लेकिन अब नहीं हो सकती। आज सुबह जीरो ऑवर हो चुका है अब कोई दूसरी बात नहीं हो सकती और कालिंग अटैंशन मोशन के लिए भी आज समय रखा गया था। (विघ्न) उस कालिंग अटैंशन का जवाब भी दिया गया था सभापति महोदय, अगर मेरे विपक्ष के भाई कुछ और

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री सम्पत सिंह]
लिखकर देंगे तो हम उसका जवाब भी देंगे। लेकिन इस समय बजट पर चर्चा चल रही है। इसलिए वे बजट पर ही बोलें। कोई दूसरी बात न करें। अगर ये दूसरा मुद्दा उठायेंगे तो वह वाजिब नहीं होगा। सभापति महोदय, भजन लाल जी विपक्ष के नेता हैं। ये ही बता दें कि बजट पर चर्चा चल रही हो और बीच में कोई दूसरा मुद्दा उठाया जाये। क्या यह वाजिब है ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, यह ठीक है कि बजट स्पीच पर बजट के बारे में ही बोलना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो यह कागज सबको दिया है यह भी बजट के बीच में नहीं देना चाहिए था। यह भी कल ही देना चाहिए था। अगर ये इस तरह से बीच में कागज देंगे तो उस पर बोलना भी पड़ेगा।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, यह जो सर्कुलर है यह हरियाणा सरकार का सर्कुलर नहीं है। यह तो इंस्टीच्यूट ऑफ पार्लियामैंट्री अफेयर्ज, गांधी भवन, कुमार पार्क, ईस्ट बंगलोर का सर्कुलर है। सभापति महोदय, इसी तरह से पार्लियामैंट की भी जो कमेटियां बनी हुई हैं, उनसे भी सर्कुलर आते रहते हैं। कामन वैलफेयर आदि की जो कमेटियां बनी हुई हैं, उनसे भी आते रहते हैं। सभापति महोदय, इन कमेटियों की तरफ से सैक्रेटरी को इंफार्मेशन आती है कि सभी सदस्यों को यह सर्कुलर दिया जाये और सैक्रेटरी ने यह सर्कुलर आज सभी सदस्यों को दे दिया। उस इंस्टीच्यूशन को सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी ओपीनियन देनी है। वह चाई-पोस्ट भेज देना। यह कोई सरकारी डोक्यूमैंट नहीं है कि इस पर यहां बहस हो। इससे हरियाणा सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर यह सरकारी कागज होता तो आपको इस पर ऐतराज होना चाहिए था और हम इसका जवाब भी देते। सभापति महोदय, मैं भजन लाल जी को बताना चाहता हूं कि इस तरह से सर्कुलर पहले भी आते रहे हैं। अधिवेशन नहीं होता था तब भी आते रहे हैं। सभापति महोदय, अधिवेशन नहीं होता तब भी सैक्रेटरी इस तरह के सर्कुलर सभी मैम्बर्ज के पास पहुंचवाता है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंवोल्वमैंट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टीसीपेट कर सकें तथा अच्छी राय दे सकें। यह कोई सरकारी डोक्यूमैंट नहीं है और न ही सरकार से कंसर्न है। इसलिए इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। (विघ्न)

श्री सभापति : इस सर्कुलर के बारे में पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने स्पष्टीकरण दे दिया है। इसलिए इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : सभापति जी, चौधरी सम्पत सिंह कह रहे हैं कि यह सरकारी डोक्यूमैंट नहीं है। सचिव, विधान सभा ने भी यह डोक्यूमैंट नहीं भेजा तो फिर विधान सभा में यह डोक्यूमैंट कहां से आ गया। (शोर)

श्री सम्पत सिंह : सभापति जी, विधान सभा सचिवालय ने ही यह डोक्यूमैंट भेजा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : सभापति जी, विधान सभा का डोक्यूमैंट कैसे हो गया। या तो विधान सभा कहे कि यह डोक्यूमैंट विधान सभा का है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : यह डोक्यूमैंट विधान सभा का ही है और विधान सभा ने यह डोक्यूमैंट सरकुलेट किया है।

श्री भजन लाल : मैं सदन में एक बात कहना चाहूंगा। सभापति जी, संविधान से छेड़छाड़ करने के हक में देश के बहुत थोड़े लोग हैं। कम से कम 2/3 लोग संविधान से छेड़छाड़ करने के हक में नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : सभापति जी, अभी तक संविधान को रिव्यू करने की कोई बात नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : सभापति जी, * * * * *

Mr. Chairperson : Whatever has been spoken by Sh. Bhajan Lal is not to be recorded.

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : कर्ण सिंह जी, जब आपको बोलने का समय दिया गया तब तो आप बोले नहीं। (शोर)

Shri Sampat Singh : Haryana Vidhan Sabha cannot review the Constitution. We have no power to review the Constitution. It is only for suggestion and not for discussion.

श्रीमती अनिता : सभापति जी, मुझे एक बात कहनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : अनिता यादव जी, आप बैठिए। (शोर)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : सभापति महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : डा० कादियान, आप बैठिए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति जी, मेरी बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : शादी लाल जी, आप बोलें। अगर आप नहीं बोलेंगे तो दूसरे सदस्य को संबोधित करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) डा० कादियान, आप बैठिए। चौधरी कर्ण सिंह दलाल आप भी बैठिए। आप तो एक अच्छे पार्लियामैन्टेरियन हैं। (शोर) शादी लाल जी नये मैम्बर हैं, इनको बोलने में सहयोग दें। (शोर एवं व्यवधान)संसदीय कार्य मंत्री का ब्यान आ चुका है और उन्होंने अपने आप एक्सप्लेन कर दिया है। अब तो आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। (शोर)

श्री सम्पत सिंह : सभापति जी, विपक्ष में सदन के जो नेता हैं, वे बोल चुके हैं तो अब इनके बाकी मैम्बरों के बोलने की तो कोई जरूरत नहीं है। (शोर) You cannot discuss the Constitution here. Everything has been cleared now.

श्री जय प्रकाश : सभापति जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : जय प्रकाश जी बैठिए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति जी, (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : दलाल साहब, आप बैठिए। शादी लाल जी को बोलने में सहयोग दें क्योंकि ये नये मैम्बर हैं। आप बीच में बाधा न डालें। अब सब बातें क्लीयर हो चुकी हैं और आप लोगों की समझ में भी आ गई हैं। इसलिये इस इश्यू पर अब बोलने की जरूरत नहीं है। (शोर)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति जी, आप मेरी बात तो सुन लें। (शोर)

श्री सभापति : दलाल साहब जब आपको बोलने का समय मिलेगा तो उस वक्त आप बोल लेना। अभी बैठिए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं * * * (शोर)

श्री सभापति : कर्ण सिंह दलाल जो बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए।

वाक-आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति जी, अगर आप मुझे इस बारे में बोलने का मौका नहीं देते तो मैं सदन से वाक-आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक-आउट कर गए।)

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री शादी लाल (रोहतक) : सभापति महोदय, जो लैटर आज सर्कुलेट हुआ है उसको मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। (विघ्न एवं शोर)

श्री वीरपाल सिंह : सभापति महोदय, आप इनको कहें कि यह लैटर पढ़कर सदन में गलत परम्परा न डालें। ये बजट पर जो कुछ कहना चाहते हैं, कह लें। (शोर एवं विघ्न)

श्री सभापति : शादी लाल जी, आप केवल बजट पर ही अपनी बातें कहें।

श्री शादी लाल : ठीक है जी। सभापति महोदय, मैं इस महान् सदन में पहली बार चुनकर आया हूं। मेरा कहना यह है कि चाहे हम किसी भी पार्टी से या किसी भी क्षेत्र से चुनकर आये हैं लेकिन हम सदन के अन्दर सारे एक हैं और हमें सभी ने मिलकर हरियाणा के हितों की बात करनी है। ऐसी सोच हमारे सभी सम्मानित सदस्यों की होनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने भी यहां पर कहा कि हमें यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें पूरे प्रदेश में काम करने के लिए कुछ न कुछ पैसा दिया है। मेरा कहना यह है कि सरकार को अपनी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रखना चाहिए। जब कोई सरकार अपनी कथनी और करनी में फर्क करती है तो फिर उस सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाता है। सरकार को हर जगह विकास के कार्य करवाने चाहिए। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पूर्व रोहतक के एक पूर्व मंत्री पर, उसके लड़के पर और उस वक्त के ऑफिसर्ज जो वहां पर कार्यरत थे, मुकद्दमा दर्ज हुआ कि उस मंत्री ने रोहतक में काम करवाने के लिए 11 करोड़ रुपये वहां के विकास के नाम पर खर्च किए हैं। रोहतक जिले के साथ शुरु से ही पक्षपात होता रहा है। वे मुकद्दमे राजनीति के तहत दर्ज हुए हैं या नहीं इस बात में मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वहां पर जो विकास के कार्य हो रहे थे उन्हें बीच में रोका नहीं जाना चाहिए था। (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सम्मानित सदस्य से अनुरोध है कि जो मामला कोर्ट में लम्बित हो उसके बारे में यहां पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर विकास के नाम पर ठगी-ठोरा हुआ था। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिली। आप अपने हल्के के विकास कराने की बात करें या और जो सुझाव आप देना चाहते हैं, वह दें। एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम कर रही है और दूसरी तरफ आप उनका पक्ष ले रहे हैं। अच्छा यही होगा कि आप अपने हल्के के विकास की बात करें।

श्री शादी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा। न ही मैं इस चक्कर में पड़ रहा हूं कि वह किस पार्टी से हैं ? मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि रोहतक में जो विकास के कार्य हो रहे थे उनको रोका नहीं जाना चाहिए था। अब वे कार्य रोक दिए गए हैं इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर विकास के कार्य तेज किये जायें ताकि वहां की जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार के नोटिस में मैं लाना चाहूंगा कि रोहतक में गवर्नमैंट स्कूल में एक बूस्टर लगना था। वह बूस्टर भी लगाना बन्द कर दिया गया है। यदि यह बूस्टर वहां पर लग जाता तो पीने के पानी की सप्लाई ठीक तरह से हो सकती थी। रोहतक जिला 1966 से चला आ रहा है। वहां पर पीने के पानी की बहुत कमी है। वहां पर अब भी बहुत सारी कालोनीज ऐसी हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है। ये कालोनीज हैं, जवाहर कालोनी, सैनी कालोनी, इन्दिरा कालोनी व नेहरू कालोनी आदि। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रोहतक में जो गवर्नमैंट स्कूल में बूस्टर लगना था, उसे लगाया जाना चाहिए ताकि वहां पर लोगों को पीने का पानी अच्छी मात्रा में मिल सके। अब वहां पर घन्टे आधे घन्टे के लिए पीने के पानी की सप्लाई हो रही है जिससे उन लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। मेरा इस बारे में केवल इतना ही कहना है कि वहां पर जो विकास के कार्य हो रहे थे उनकी स्पीड बराबर जारी रहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा कहना यह है कि वहां पर 1962 में मैडिकल कालेज बना था। उस वक्त की अपेक्षा अब जनसंख्या में भी काफी बढ़ौतरी हो चुकी है। वहां पर अब मरीजों की बहुत अधिक भीड़ रहने लग गयी है क्योंकि उस वक्त जो ओ०पी०डी० बनाई गई थी वह उस वक्त की जनसंख्या के हिसाब से बनाई गई थी। इसी तरह से रोहतक मैडिकल कालेज में इन्डोर पेशेंट भी पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में ऐडमिट हो रहे हैं। भीड़ का अधिक रहने का कारण यह है कि पहले की अपेक्षा अब जनसंख्या कई गुना अधिक बढ़ चुकी है और जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां पर खड़े होने की जगह नहीं है लेकिन उसकी एक्सपैंशन के लिए आज बजट में कुछ प्रोविज़न नहीं आया और न ही कुछ सुपर स्पैशलिटीज़ ही हैं। इससे दो नुक्सान हो रहे हैं एक तो सारे हरियाणा प्रदेश में केवल एक ही गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज है जो या सिर्फ उन आदमियों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं या उनके लिए है जो बहुत ऊंचे लोग हैं जो यहां से रैफर हो कर अपोलो या ऐस्कोर्ट में जा कर अपना ट्रीटमैंट करवाते हैं। अगर अपोलो या ऐस्कोर्ट की सुविधाएं हम मैडिकल कॉलेज रोहतक में ही दे दें और उसका एक्सपैंशन कर दें, ओ०पी०डी० बढ़ जाए, इनडोर बढ़ जाए तो मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश वासियों को काफी फायदा होगा और गवर्नमैंट को भी काफी फायदा होगा क्योंकि गवर्नमैंट को जो राशि रि-इम्बर्स करनी पड़ती है, वह नहीं करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैडिकल कॉलेज को स्ट्रैंथन करने के लिए, उसकी ओ०पी०डी० के लिए कुछ प्रावधान जरूर किया जाए और बजट में उसके लिए और पैसा आना चाहिए। जहां तक स्वास्थ्य की बात थी तो सीवरेज और पानी के हैड में भी जो पैसा रखा गया है वह काफी कम है तथा मैंने जो समस्याएं आपके सामने रखी हैं

[श्री शादी लाल]

उनके समाधान के लिए यह पैसा काफी नहीं रहेगा इसलिए मैं चाहूंगा कि रोहतक के लिए कोई स्पैशल ग्रान्ट दी जाए ताकि वहां पर सीवरेज और पानी की समस्याओं को हल किया जा सके और लोगों को बुनियादी सहूलियतें मिल सकें। तीसरी बात मैं और कहना चाहूंगा। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं वकील हूं। यह बात मैं भी समझता हूं लेकिन मैं विपक्ष में आ गया और विपक्ष के विधायक के साथ आज राज्य में कैसा बर्ताव हो रहा है वह मैं मुख्य मन्त्री जी के सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले मैं होटल कलिंगा में था। रात को पौने ग्यारह बजे का टाईम था और होटल में दो आदमी आए। उस वक्त होटल बन्द हो चुका था उन आदमियों ने कहा कि खाना खाना है। होटल बन्द हो चुका था और सारे इम्पलॉयज़ जा चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने गोलियां चलाईं। क्यों चलाई ? शायद मैं विपक्ष का विधायक था इसलिए चलाई या उसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी, उसका मुझे कुछ पता नहीं है और आज मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए क्योंकि उस वक्त टैलीफोन कर दिया गया था और पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने वह ऐस्टीम तो पकड़ ली लेकिन वे मुल्ज़िम आज तक पकड़े नहीं गए हैं। कारण क्या है, वे कौन हैं, किस कौंसीप्रसी के तहत वे आए थे और क्या करना चाहते थे अध्यक्ष जी, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए ताकि एक भय का जो वातावरण बन गया है वह दूर हो जाए और हम सब ठीक तरीके से रह सकें (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पैंशन की स्कीम अच्छी है लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पैंशन का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि गवर्नमैंट इम्पलॉयज़ का भुगतान ट्रेजरी के थ्रू होता है उससे पैंशन की राशि का जो मिसयूज होता है वह बन्द हो जाएगा और हर महीने की पहली तारीख को बूढ़ों, विकलांगों, विधवाओं आदि को बैंक के थ्रू पेंशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद मैं कुछ और बातें भी आपके सामने रखना चाहूंगा। इस बजट में कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया गया है लेकिन पहले हरियाणा में 100/- रुपये तक के जूते पर टैक्स फ्री था आज इस पर 5% टैक्स लगाया गया है लेकिन हमारे साथ लगते प्रदेश दिल्ली में 200/- रुपये तक के जूते टैक्स फ्री हैं। हम भी अगर 100/- या 200/- रुपये तक के जूते को टैक्स से ऐग्जम्पट कर दें तो गरीब आमदियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी और इससे वे भाई फायदा उठा सकेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। दूसरी बात मैं किसान की कहना चाहूंगा। किसान गेहूं, चना, जौ या दूसरी फसल ले कर मण्डी में आता है तो उस पर साढ़े ग्यारह परसैंट टैक्स पड़ता है। इसमें 4% टैक्स, 4% मार्कीट फीस, अढ़ाई परसैंट डामी और 1% लेबर लगती है। व्यापारी वर्ग बड़ा होशियार होता है और वह साढ़े ग्यारह परसैंट की कीमत किसान को कम देता है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम यह खर्चा काट दें तो जो पैसा व्यापारी किसान को कम देता है तो किसान जब माल लेकर मण्डी में आए तो उसको ज्यादा पैसा मिल सकता है। यह बात किसान के हित में है और किसान जब मण्डी में माल ले कर आएगा तो उसकी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वह नहीं होगी इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह काम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि दालों पर 8% टैक्स लगा दिया लेकिन दिल्ली में दालों पर टैक्स नहीं है। जो टैक्स दिल्ली में नहीं है अगर वह यहां पर लगाया जाएगा तो उससे व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा और हम सब भाइयों को नुकसान होगा। इसी तरह से खल, तूड़ी और पशु आहार पर भी 4% टैक्स लगा हुआ है लेकिन यह टैक्स दूसरी जगहों पर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री चन्द्र भटिया (फरीदाबाद) : आदरणीय स्पीकर साहब, वित्त मंत्री सम्पत सिंह जी ने वर्ष 2000-2001 का जो बजट सदन में रखा है मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में जनहित के बहुत से आंकड़े हैं जो जनता को आकर्षित करते हैं। मेरे से पहले बजट पर बोलते हुए विपक्ष के साथियों ने काफी कुछ कहा और कुछ इसके विरोध में बोलने के लिए खड़े हुए थे। सही मायने में उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले शादी लाल जी ने कहा कि सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। मांगे राम जी ने भी अपने समय में बोलते टैक्स न बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया। हरियाणा की जनता ने इस बजट को बहुत ही सराहनीय बताया है। विपक्ष के साथी बार-बार यह कह रहे हैं कि यह बजट सही नहीं है। सर, मन तो उनका भी मान रहा है कि यह बजट बहुत अच्छा है लेकिन वे इस सदन में विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं इसलिए उन्होंने इसके विरोध में बोलना ही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे से पहले जिनका राज यहां पर होता था आज वे विरोधी पक्ष में बैठे हैं। उन्होंने अपने समय में अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रान्ट बंद कर दी थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस समय इसका बहुत विरोध किया था लेकिन बंसी लाल जी ने माना नहीं। आज हरियाणा की जनता ने उन सभी साथियों को विपक्ष में बिठा रखा है। मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस ग्रान्ट को बहाल किया यह बहुत ही अच्छा कदम है। अध्यक्ष महोदय, बुजुर्गों के लिए जो पैंशन को दोगुना किया है यह बहुत ही सराहनीय कदम है। पहले 100 रुपए पैंशन मिलती थी और उसको देने का काम चौधरी देवी लाल जी ने किया था। अब बुजुर्गों को इस पैंशन से बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा जो कन्या दान की स्कीम चालू की है उसको लेकर विरोधी पक्ष के भाई विरोध करते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर उसमें कोई कमी है तो वह वे बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता इसको बहुत ही सराहनीय कदम बता रही है। हमारे विपक्ष के साथी भी उसका बार-बार विरोध करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारे विपक्ष के साथी खड़े होकर बजट का विरोध भी करते हैं वहीं बाद में अपने हल्के की बातें भी कहते हैं। ये लोग पहले सरकारों में रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी और वे लोग जब हरियाणा के हितों, हरियाणा के लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रहे थे तो लोगों ने उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी को सत्ता सौंपी। चौधरी बंसी लाल जी का भी तीन साढ़े तीन साल तक राज रहा और हम भी उस सरकार में होते थे। उस समय हम अपनी बात को अपनी पार्टी के अंदर और सरकार में मुख्य मंत्री के सामने बार-बार रखते थे। हमारे कांग्रेस के लोग भी उसी चीज का विरोध यहां पर करते थे और चौधरी बंसी लाल जी को गालियां निकाला करते थे लेकिन अध्यक्ष महोदय, अचानक ही कांग्रेस पार्टी ने बंसी लाल जी को समर्थन भी दे दिया। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बंसी लाल जी के गलत कामों का विरोध किया करते थे और जब हम भी उस सरकार में रहकर मुख्य मंत्री के सामने अपनी बातों को कहते थे तो उस समय चौटाला साहब, और कांग्रेस के साथी भी कहते थे कि हमारी बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, हम तो सरकार में रहकर भी बोलते थे उस समय हमारे विपक्ष के साथी टेबल थपथपाकर कहते थे कि हम सही बातें कह रहे हैं लेकिन अचानक ही चौधरी बंसी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने उस समय समर्थन दे दिया, जब हमने वापस लिया था। हमें तो उस समय कहा जाता था कि हम गलत हैं लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लोग उनको साढ़े तीन साल तक गालियां निकाला करते थे उन लोगों ने सरकार को समर्थन दे दिया था। अध्यक्ष महोदय, जो लोग हरियाणा की जनता के साथ इस तरह खिलवाड़ करते हैं वह उनको दोबारा नहीं आने देती। एक मौका चौटाला साहब को मिला और उन्होंने 6 महीने के अंदर ही बहुत विकास के काम किए। जब उनका 6 महीने का समय चल रहा था तो कांग्रेस के लोग यह कहते थे कि इस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि यह सरकार उन्होंने जोड़तोड़ करके बनायी है।

[श्री चन्द्र भाटिया]

इसलिए दोबारा से चुनाव करवाएं जाने चाहिएं। अगर जनता इनको अच्छा समझेगी तो इनको दोबारा मुख्य मंत्री बना देगी उस समय ये कहते थे कि मुख्य मंत्री जनता की मर्जी से नहीं बने बल्कि जोड़तोड़ करके बने हैं लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए तो पिछले 6-7 महीनों में चौटाला साहब ने जो काम किए थे उनको देखकर हरियाणा की जनता ने उनको फिर से चुनकर मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पहले सदन के कुछ सदस्यों ने कहा था कि चुनाव के अंदर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया क्योंकि उस दौरान जगह-जगह पर काम किए गए, गांव-गांव में खड़ंजे बनाये गये, नालियां बनायी गयीं और स्कूलों को बनाने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने तो चुनावों के दौरान किसी भी बात का जिक्र नहीं किया था। कांग्रेस की भी हुकूमत रही थी इनका भी राज था लेकिन उस समय तो केवल पत्थर ही लगे हुए थे। जिन पर आज तक भी काम नहीं हुआ है। इसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने भी बताया था। लेकिन चौटाला साहब ने जिन बातों की घोषणा की वह पूरी हुई। पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने 90 विधान सभा क्षेत्रों में घूम-घूम कर खुले दरबार लगाए और आम आदमी की बात सुनी। लोगों को लगता था कि मुख्य मंत्री जी हमारी सीधी बात सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछली चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में हम भी विधायक थे। हम तो पहली बार चुनकर आए थे इस बार फरीदाबाद की जनता ने दोबारा से मौका दिया और हमें विधान सभा के अंदर चुनकर भेजा। हमने तो वह समय देखा जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे तो आम जनता को उनसे मिलने की बात तो दूर की थी, विधायकों और मंत्रियों की बात भी नहीं सुनी जाती थी। आज जब हरियाणा की जनता के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जाते हैं तो आम आदमी यही सोचता है कि यह मुख्य मंत्री हमारा अपना है आम आदमी भी खुलेमन से अपनी बात कह सकता है। इन बातों को लेकर हमारे कांग्रेस के साथी बेचैन हैं। हमने फरीदाबाद हल्के के बारे में अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा था। चौधरी बंसी लाल जी बैठे नहीं हैं। इन्होंने भी हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं जब हमारे हल्के के गरीब लोगों पर उनकी बस्तियों पर बुलडोजर चलते थे और हमारे यहां विकास के काम नहीं होते थे तब हम अपने हल्के के लोगों की बात को यहां पर कहा करते थे, हमारी बातें सरकार को रास नहीं आती थी तो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमें बनाए जाते थे लेकिन क्योंकि हमारे पीछे फरीदाबाद की जनता थी इसलिए हमने उन ज्यादतियों की परवाह नहीं की और अपने हल्के के लोगों की मांगों को मजबूती से यहां रखा। मेरे हल्के में स्लम बस्तियां भी हैं और वहां सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है थोड़े समय जब हमारा चौधरी बंसी लाल से झगड़ा चल रहा था वह हल्के के विकास की बात को लेकर था। अभी भी हमारे हल्के में काफी कमियां हैं चुनावों में जब हम जनता से वोट मांगने जाते हैं तो उनसे तरह-तरह के वायदे करके आते हैं कि हम जीत गए तो तुम्हारे ये काम करवाएंगे वह काम करवाएंगे। स्लम बस्तियों के लिए केन्द्र सरकार से पैसा आता है और वह पैसा स्लम बस्तियों पर खर्च किया जाता है लेकिन हमारे हल्के में व उसके आसपास बल्लबगढ़, एन०आई०टी० और पुराने फरीदाबाद इन तीनों में जो स्लम बस्तियां हैं उनमें काम नहीं होते हैं पिछली बंसी लाल की सरकार में भी हमने इन बातों को बहुत जोरदार तरीके से उठाया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया मुझ से पूर्व मेरे हल्के से कांग्रेस के नुमाइन्दे हुआ करते थे उन्होंने भी फरीदाबाद की जनता के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की थीं। हम तो विधायक रहे थे लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार में तो वहां से मंत्री रहे लेकिन उनके मंत्री होते हुए उस क्षेत्र में कोई विकास के काम नहीं हुए। कांग्रेस की हुकूमत में हमारे फरीदाबाद की जनता पर हाउस टैक्स लगाया था और कांग्रेस के ही राज में जब ऐक्ट बनाया जा रहा था तो यह कह दिया गया था कि पांच साल बाद जब सर्वे होगा तो यह हाउस टैक्स 10 गुणा हो जाएगा। फरीदाबाद की जनता 10 गुणा हाउस टैक्स नहीं

दे सकती थी। मैंने पिछले सदन में यह बात उठाई थी। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इस हाउस टैक्स को ठीक कराएंगे। अब उस पर रोक लगी हुई है। सिर्फ फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हाउस टैक्स को ठीक कराने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी। हमारे विपक्ष के साथी अपने हल्के की बात को कहते हैं हम यह कहना चाहेंगे कि उस समय तो राज होता था। तब भी काम नहीं होते थे आज अच्छे काम हो रहे हैं उन अच्छे कामों पर भी विपक्षी भाइयों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जहां तक सड़कें और नाली और पानी की बात कही। जब कांग्रेस की सरकार थी और उनका राज था उस समय मेरे हल्के में न सड़कों का काम हुआ, न नालों का काम हुआ और न ही पानी के बारे कोई काम हुआ। उस समय वे काम करा सकते थे। मैं विपक्ष के भाइयों को कहना चाहता हूं कि वे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से अपने हल्कों का काम करायें क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कभी किसी सदस्य में फर्क नहीं रखते। इस बात का प्रमाण उन्होंने 90 हल्कों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करके दिखा दिया है। मैं अपने विपक्ष के भाइयों को कहूंगा कि अगर यह सरकार अच्छे काम करती है तो उस काम की सराहना करें। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री चौधरी सम्पत सिंह जी का भी धन्यबाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट पेश किया।

श्री लछमन दास अरोड़ा : स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बजट पर बोलने का समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि जिस सदस्य को अब तक बोलने का समय नहीं मिला है उसको पहले मौका दिया जाये।

श्री लछमन दास अरोड़ा (सिरसा) : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं इस सदन में बिराजमान दसवीं विधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री महोदय भाई सम्पत सिंह जी ने जो बजट पेश किया है मैं उस बजट को टैक्स फ्री बजट कहूंगा। क्योंकि इस बजट के रिजल्ट्स तो हमें आगे आने वाले सैशन तक ही मिल पायेंगे। इसलिए उस वक्त ही मैं इस बजट पर कोई बात कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने हल्के सिरसा के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शायद याद होगा कि 1990 में जब ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सी०एम०के० कालेज सिरसा में एक समारोह में इन्होंने एक बात का ऐलान किया था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र का रिजनल सैन्टर सिरसा में खोल दिया जायेगा। उस समय 14 महीने तक ये मुख्यमंत्री रहे लेकिन किन्हीं कारणों से किसी वजह से उस रिजनल सैन्टर को नहीं खोल पाये। उसके बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और कांग्रेस की सरकार ने गांव फुल्का में 100 एकड़ जमीन ऐक्वायर की और एक करोड़ रुपये की लागत लगा कर इस रिजनल सैन्टर के लिए बिल्डिंग बनवाई। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं रही। उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी का राज इस प्रदेश में आया और चौधरी बंसी लाल जी ने उस कार्य को वहीं का वहीं ठप्प करवा दिया। भवन बनाया गया था उस पर ताला लगवाया गया। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस रिजनल सैन्टर को जल्दी से जल्दी चालू किया जाये क्योंकि सरकार का पैसा लगा हुआ है अगर रिजनल सैन्टर नहीं खुलता है तो सरकार का सारा पैसा बर्बाद हो जायेगा। जहां तक सिरसा शहर के बाई-पास की बात है। सिरसा शहर में जो फाटक हैं उस पर इतनी भीड़ लगी रहती है और वह फाटक ज्यादातर बन्द रहता है। अगर किसी आदमी को मैडिकल हैल्प की जरूरत पड़ जाये तो उस आदमी को उस फाटक की वजह से समय

[श्री लछमन दास अरोड़ा]

पर मैडिकल हैल्प नहीं मिल सकती। मुझे याद है कि पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिरसा बाई-पास के लिए एक करोड़ रुपया मंजूर किया था लेकिन उसके बाद वह सरकार चली गई। वह एक करोड़ रुपया पता नहीं लैप्स हो गया था नहीं यह मैं नहीं कह सकता। मेरी खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह विनती है कि उस बाई-पास को जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक फोर लेनिंग की बात है, पूरे हरियाणा के अन्दर जितने भी जिले हैं वहां नैशनल हाइवे हैं तथा सड़कें बनी हुई हैं लेकिन सिरसा जो कि मुख्यमंत्री महोदय का होम डिस्ट्रिक्ट भी है वहां पर फोर लेनिंग सड़कें नहीं बनी हुई हैं इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सिरसा के अन्दर जल्दी ही सड़कों को फोर लेनिंग करवाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सिरसा में रेलवे क्रौसिंग पर ओवर ब्रिज की चर्चा काफी लम्बे समय से चली आ रही है परन्तु पता नहीं क्यों वह चर्चा कामयाब नहीं हो पाती और वह ब्रिज बन नहीं पाता इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि वे रेलवे क्रौसिंग पर शीघ्र ही ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीवरेज मास्टर प्लान की बात है, बहुत लम्बे समय से यह कोशिश हो रही है कि यह मसला हल हो जाए। ज्यों-ज्यों हम इस मसले का हल करते हैं त्यों-त्यों यह मामला और बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाया जाए और इसको लागू किया जाए ताकि इस मसले का हल हो सके। सिरसा में जब बारिश होती है तो बारिश के पानी की निकासी का कोई रास्ता ही नहीं होता है और हालत यह बन जाती है कि सिरसा शहर एक तालाब सा बन जाता है, इसके कारण लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे हमारे सिरसा शहर की इस समस्या का भी जल्दी ही निवारण करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक घग्घर बांध की बात है। 1995 में कांग्रेस की सरकार के समय में यह बांध बनना शुरू हुआ था और तकरीबन आधा बना हुआ है और बाकी आधा रह गया है उस बांध के न बनने के कारण गांवों के गांव तबाह हो जाते हैं, फसलें बरबाद हो जाती है। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है कि वे बारिश के आने से पहले उस बांध को कम्पलीट करवाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सिरसा शहर की कई कालोनियों में पीने के पानी की कमी है, वहां जमीन का पानी खारा है और वहां ट्यूबवैलों के कामयाब होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के लोग गर्मियों में 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और उनको बड़ी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे वाटर वर्क्स का पानी उन कालोनियों में सप्लाई करवाने का काम करवाएं। इसके अलावा सिरसा में 25-26 एकड़ जमीन पर भाखड़ा नाम का तालाब है जो आज गन्दगी का अड्डा बन गया है और यह तालाब सिरसा शहर के सैन्टर में पड़ता है।

1983-85 में हमने भारत सरकार से कोशिश करके 50 लाख रुपये सैंक्शन करवाए परन्तु सरकार बदलने के बाद वह रुपया लैप्स हो गया और वह पैसा वहां लग नहीं पाया इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि टूरिज्म विभाग की तरफ से उस तालाब को साफ करवा के वहां एक टूरिस्ट कम्पलैक्स बनवाया जाए ताकि लोगों को सैर करने की जगह मिल सके। अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिरसा शहर गुरूओं की नगरी है, सच्चा सौदा यहां पर है, राधा स्वामी यहां पर हैं, नामधारी यहां पर है, लाखों की संख्या में यहां लोग इकट्ठे होते हैं। जहां तक सिरसा के नक्शे की बात है सारे हरियाणा में सिरसा के नक्शे के मुकाबले किसी शहर का नक्शा इतना सुन्दर बना हुआ नहीं है। अगर सिरसा के सभी विकास के कार्य ठीक ढंग से हों तो सिरसा शहर राजधानी बनाने के काबिल है। यहां पर बार-बार नई राजधानी बनाने की बात होती है इसलिए सिरसा को राजधानी बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने गवर्नर ऐड्रस पर बोलते हुए पशु धन को बढ़ाने का भी जिक्र किया था। हिसार में लाइव स्टाक फार्म में रिसर्च सैन्टर है उसके माध्यम से सिरसा में भी एक ब्रांच खोली जाए क्योंकि सिरसा में भी अच्छी नसल की भैंसे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिरसा शहर की मार्किट के अन्दर एक मीट मार्किट है यदि उसको मार्किट से बाहर निकाल दिया जाए तो वह मार्किट एवन मार्किट बन सकती है। अध्यक्ष महोदय, इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप समय निर्धारित करके दें कि बजट पर कितना समय अभी सभी साथियों ने बोलना है और हमें किस समय जबाव देना है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी दो घंटे में विपक्ष के तकरीबन सभी सदस्य बोल लेंगे। उसके बाद 13.00 बजे 3 बजे आप बोल लेना।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नहीं बोल पाये। पहले उन्हें बोलने का अवसर दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, तीन पार्टियों के जो एक-एक सदस्य हैं, उन्हें भी तो बजट पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आपकी पार्टी की सदस्य संख्या सदन के 90वें हिस्से के बराबर है। उससे ज्यादा समय आप ले चुके हैं। प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) दलाल साहब आपकी कालिंग अटैंशन मोशन कल लगी हुई है आप उस पर कल बोल लेना। प्लीज आप बैठ जायें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, हम तो बजट पर बोलने के लिए समय मांग रहे हैं। हमें बजट पर बोलने के लिए समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, समय होगा तो आपको भी बजट पर बोलने का समय दिया जायेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बजट पर बोलने के लिए चाहे थोड़ा ही समय दें। लेकिन समय जरूर दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि आप सब अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। 5 मिनट तो आप लोगों ने शोर-शराबे में ही नष्ट कर दिये। प्लीज आप सभी बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अच्छे सद्भावनापूर्ण वातावरण में यह सदन चल रहा है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने सबको खुले दिल से बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए हम पहले भी आपका आभार व्यक्त कर चुके हैं और पुनः भी करते हैं। विपक्ष के नेता की इस बात से भी हम सहमत हैं कि जो सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल चुके हैं, उनके अलावा जो नहीं बोले, सर्वप्रथम उन सबको समय दिया जाये। ताकि हरियाणा विधान सभा के 90 के 90 सदस्य बोल लें। फिर भी अगर समय होगा तो दूसरों को भी बोलने का अवसर दिया जायेगा। लेकिन कुछ लोग यहां अपनी ठेकेदारी क्यों समझते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ठेकेदारी की बात कैसे कर सकते हैं। मैं तो जनता द्वारा चुनकर यहां आया हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सब बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरे हल्के के लोगों ने मुझे यहां चुनकर भेजा है और चौटाला साहब ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। आप मुझे इस बारे में रूलिंग दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सब बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं किसी की मेहरबानी से यहां नहीं आया। बल्कि जनता द्वारा यहां पर चुनकर आया हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी मैम्बर बराबर हैं और सब को बराबर समय मिलेगा। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम भी बराबर का समय मांग रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप दूसरों को बोलने देंगे या नहीं। अगर समय होगा तो आपको जरूर दूंगा। अभी आप बैठिए। आपका नब्बेवां हिस्सा है और आपको नब्बेवें हिस्से से ज्यादा समय दूंगा। अभी जो सदस्य नहीं बोले हैं उनको बोलने दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारे हिस्से का हमें समय देंगे तो ठीक है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा ये कह रहे हैं कि मैं चुनकर आया हूं और किसी के रहमो-कर्म पर नहीं हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यहां पर हर मैम्बर चुनकर आया है। केवल चौटाला साहब दो जगह से चुनकर आये और एक जगह उन्होंने खाली कर दी है। हर मैम्बर को आपने पूरा समय बोलने के लिये दिया है। सदन के नेता और विपक्ष के नेता दोनों ने यह कमिटमैन्ट भी की है कि जिनको बोलने को मौका नहीं मिला उनको समय मिलना चाहिए। आप उनको समय दे भी रहे हैं चाहे किसी पार्टी का सिंगल मैम्बर हो उसको भी पूरा समय आपने दिया। अध्यक्ष महोदय, जितना ऐकोमोडेट हर मैम्बर को आप कर रहे हैं उतना तो शायद आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इसलिये किसी का यहां एस्पर्शन कॉस्ट की बात करना ठीक नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैंने एस्पर्शन कास्ट वाली कोई बात नहीं की है। (शोर) कोई इस तरह से हमें दबाना चाहे तो हम नहीं दबेंगे। (शोर)

श्री बलबीर पाल शाह (पानीपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पुनः बोलने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें कोई नये कर नहीं लगाये। (इस समय मेजें थपथपाई गई) लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि छः महीने के बाद इसके जो रिएक्शन होंगे उसके ऊपर दोबारा हम यहां चर्चा करेंगे। अभी तो मुझे एक ही बात कहनी है जो हरियाणा की ज्वलंत समस्या है। इसके ऊपर बोलकर मैं बैठ जाऊंगा। पानीपत की मैं कोई बात नहीं कर रहा। यह समस्या मेवात से जुड़ी हुई है। मेवात में गौकशी हो रही है जबकि हरियाणा में गौकशी बन्द है जबकि मुख्यमंत्री जी ने शपथ कुरुक्षेत्र में ली जहां गौपालक श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि हमारे मेवात के भाई किस कारणवश गौकशी करते हैं। ये सभी भाई पहले हिन्दु थे, बाद में समाज की किसी व्यवस्था के कारण इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया और हमसे अलग हो गये। इसके अलावा जो इनके अन्दर बहने वाला खून है वह भी हिन्दू का है, हिन्दुस्तानी का है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अकबर के काल में भी गौकशी नहीं होती थी लेकिन आज मेवात में गौकशी हो रही है। क्यों हो रही है, इसका कारण हमें जानना

चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मेवात पिछड़ा हुआ इलाका है और हजरत मौहम्मद साहब ने भी एक बात कही थी कि केवल आपातकाल में ही गौकशी की जाए। जब तक कोई और साधन है तब तक गौ को मारा न जाए लेकिन आज गौ को मारा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्टडी किया है उसमें पाया है कि मेवात के लोग अपनी स्वेच्छा से गौकशी नहीं कर रहे हैं। गौकशी करना उनकी मजबूरी है क्योंकि आने वाली जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने मेवात के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। सैल्फ एम्पलाएमैन्ट के कोई साधन नहीं जुटाये और न ही वहां पर कोई हैवी इंडस्ट्री लगाई। इस तरह के कोई कार्य नहीं किये जिससे कि मेवात के लोग गौकशी को छोड़ दें। वे लोग मजबूरी में गौकशी कर रहे हैं। वे जो गौकशी कर रहे हैं वे अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। वहां पर सारा मांस दिल्ली जाता है और वहां से जो लोग मांस के निर्यात का काम करते हैं उनके द्वारा उसे विदेशों में भेजा जाता है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि मेवात के लोगों के लिए इस बजट में कुछ न कुछ प्रावधान अवश्य किया जाये ताकि वहां के जो नौजवान साथी हैं वे इस गौकशी के काम को छोड़ सकें और वे पहले की तरह होली व दिवाली का त्यौहार सभी के साथ मिल कर मना सकें ताकि वे दुबारा से हरियाणा की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। यह तभी हो सकता है जब वहां से गौकशी की लानत को खत्म किया जा सकेगा। इसके लिए मेरा सरकार को सुझाव है कि वहां पर लड़कों को नौकरियां दी जायें और सेल्फ ऐम्पलॉएमेंट के तहत अधिक से अधिक बच्चों को काम दिया जाये ताकि किसी को मजबूरी की हालत में गौकशी न करनी पड़े। वहां पर जितनी अधिक मात्रा में गौकशी होती है उसका मांस वहां पर खाया नहीं जाता बल्कि बाहर भेजा जाता है। वहां की गरीबी ही इस जड़ की मूल ज्वलन्त समस्या है। यदि हम इसको रोक पाएंगे तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्धार वहां के लिए हो सकेगा और उन लोगों का भी उद्धार हो सकेगा जो इस काम में लगे हुए हैं। गौकशी को रोकना एक धार्मिक कार्य है। गौकशी होने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको सेल्फ एम्पलाएमेंट के तहत नौकरी दी जाये और फिर उनसे लिखवा कर ले लिया जाये कि वे भविष्य में गौकशी नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा कर पायेंगे तो यह हिन्दू समाज के लिए और मेवात के लोगों के लिए एक महान कार्य होगा। धन्यवाद।

पशु पालन राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद इलियास) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे आदरणीय शाह साहब ने कहा कि मेवात में गौकशी हो रही है उसे रोका जाना चाहिए। मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मेवात एरिया का जितना शिक्षित वर्ग है, योग्य वर्ग है या यों कहिए कि जो सम्मानित वर्ग है वह नहीं चाहता कि गौकशी हो। वहां पर पढ़े-लिखे, समझदार लोगों का व वहां की 36 बिरादरियों का विचार है कि गौकशी नहीं होनी चाहिए। मेवात में केवल मेव ही नहीं रहते बल्कि 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। वहां का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि गौकशी हो। मेव जाति के लोग गौकशी का काम नहीं करते। इसमें कोई दो राय नहीं कि वह एरिया बहुत ही बैकवर्ड एरिया है और वहां पर बहुत ही गरीबी है। शाह साहब ने मेव जाति पर जो आरोप लगाया है कि मेव लोग गौकशी कर रहे हैं यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद व निराधार है क्योंकि मेव जाति के लोग गौकशी नहीं कर रहे। पहले तो मैं खुद कहता हूं वहां पर 36 बिरादरी के आदमी हैं वहां पर न कोई गौकशी करता है और न ऐसी कोई बात है (विघ्न) जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा में वजीरेआला की हैसियत से कार्यभार सम्भाला है, मैं अपनी नॉलेज के आधार पर कहता हूं कि पिछले छः महीने के अन्दर कहीं पर गऊ का कोई ज़िक्र नहीं आया है। इसके लिए मैं चौधरी साहब की सराहना करता हूं और मैं खुद इस बात की ताईद भी करता हूं तथा अपनी तरफ से खुद छूट भी देता हूं कि हम चौधरी साहब के सिपाही हैं और सरकार की हैसियत

[श्री मोहम्मद इलियास]

से हम मेवात में गौकशी नहीं होने देंगे। मैं हाउस को भी विश्वास दिलाता हूं क्योंकि चौधरी साहब की खुद की नीति और पौलिसी भी यही रही है इसलिए मेवात में गौकशी नहीं होगी। न तो हम गौकशी की सराहना करेंगे और न गौकशी होने देंगे (विघ्न एवं शोर) जहां तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेवात वाकई में ही गरीबी से मुत्तासिर है और हमें मालूम है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मेवात की किसी चीज से अनभिज्ञ नहीं हैं और पूरी तरह से परिचित हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह सन् 1987 में जब चौधरी देवी लाल जी हरियाणा के रहनुमा थे उन्हीं के नक्शेकदम पर चल कर माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे मुख्यमन्त्री बने हैं तो किसी प्रकार से मेवात को पीछे नहीं रहने देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है कि जैसे पहले चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में मेवात ने तरक्की की है चाहे वह रोजगार की बात थी चाहे किसी दूसरी चीज की बात थी मुख्तलिफ विभागों की बात थी वैसी ही तरक्की अब भी होगी। थैंक्यू वैरीमच।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी में मेवात के अन्दर गौहत्या होती रही है, यह ठीक है (विघ्न) इन्होंने माना है (विघ्न) चाहे इनके पहले राज से होती आ रही है। (विघ्न) मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर यह है कि गऊ जिसे हम अपनी मां कहते हैं और मानते हैं उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार गौ हत्या के ऊपर कोई आयोग बनाने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है, अब आप बैठें। (विघ्न)

श्री मुहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कर्ण सिंह दलाल जी से एक बात जानना चाहता हूं। चौधरी बंसी लाल जी जब मुख्यमन्त्री थे और उनका एक प्रोग्राम पुन्हाना के अन्दर था तब गौकशी की बात उनके सामने आई तो आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी ने उस वक्त कहा था कि गौकशी तो पहले से होती आई है यह कोई बात ही नहीं है। भाई दलाल साहब को मैं यह बताना चाहता हूं जब इनकी सरकार थी और ये खुद मन्त्री थे तो उस वक्त इन्होंने यह बात क्यों नहीं की। शाह साहब ने एक बात और कही है कि पहले हम हिन्दू थे और अब मुसलमान हो गए हैं। मैं भाई से यह गुजारिश करता हूं माफ कीजिएगा हिन्दुस्तान के अन्दर खाने का अधिकार, रहने का अधिकार और धर्म को मानने का अधिकार बहुत पुराने वक्त से है। यह सही बात है कि हम हिन्दू थे लेकिन इसमें भी कोई सन्देह की बात नहीं है कि हम कल्मागोयम हुए हैं उसमें हम मुस्तहिक हैं। जब से हमने कल्मा पढ़ लिया तो बात खत्म हो गई उसके बाद के हालात की बात कोई मायने नहीं रखती। उस वक्त कहां था, क्या था, क्यों कन्वर्ट हुए, कैसे कन्वर्ट हुए। मुआफी चाहूंगा कि यह मामला हाउस के अन्दर नहीं कहना चाहिए था। बलबीर पाल शाह जी को ऐसी बात यहां नहीं उठानी चाहिए थी, यह सब को बराबर का अधिकार है और अपनी प्रवृत्ति की बात है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बलबीर पाल शाह द्वारा

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उस समय ऐसे हालात हुए जिससे इन्होंने कन्वर्शन की। मैं इनकी किसी बात के खिलाफ नहीं

हूं। हम और आप भाई-भाई हैं मैं कोई कटाक्ष करना नहीं चाहता था हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि मेवात के अन्दर गौकशी होती रही है वह बन्द होनी चाहिए, मैं सरकार से यह मांग करता हूं। ये किसी धर्म को मानें, हम किसी धर्म को मानें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री मोहम्मद इलियास : हम इसके लिए पहले से ही वचनबद्ध हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलबीर पाल शाह : हम आपका इसके लिए धन्यवाद करते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस विषय में अपनी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : अब इस टॉपिक पर और डिस्कशन नहीं होगी, आप सब बैठ जाएं। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर बात कही गई है। आप चाहें तो कार्यवाही में देख सकते हैं।

श्री गोपी चन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, कभी कोई मैम्बर कहीं से खड़ा हो जाता है तो कभी कोई। अध्यक्ष जी अपनी सीट पर खड़े होते हैं फिर भी ये बोलते रहते हैं। मैं इसको यह बताना चाहूंगा कि बाकी मैम्बर्ज भी बोल सकते हैं उनको भी बोलने का अधिकार है। ये बिना इजाजत के मत बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ पर्सनल ऐक्सप्लनेशन है। अभी मंत्री जी ने जैसा कहा कि हमारे सामने यह बात आई कि वहां पर गौ हत्याएं हुई हैं * * * * * * * * * * * * * * *।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी जो कह रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री धर्मपाल (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कल दिनांक 14-3-2000 को वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह कर-रहित है। यह बहुत ही सूझ-बूझ का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 3-4 सालों में अराजकता का माहौल बन गया था चाहे वह किसी भी वर्ग की तरफ से हो। विकास नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कोई सुरक्षित ही नहीं था। किसी भी तरफ विकास कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। इसके लिए मैं पिछली सरकारों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को दोषी नहीं ठहराऊंगा क्योंकि यह ठीक नहीं है। इस बजट से उम्मीद होती है कि शायद पिछली कमियां ठीक हो जाएंगी। जब इस बजट का परिणाम आएगा यह तो उससे ही पता चलेगा। मैं अपनी कांस्टीचुएंसी सोहना की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। वहां पर सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पूछो नहीं। वहां पर 3-4 सालों में कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ था। यह मैं मानता हूं कि अब थोड़ा सा काम हुआ है। किसी काम को न करना अच्छी बात नहीं है। इसके साथ-साथ मैं खासतौर पर बताना चाहूंगा जितनी अप्रोच रोड्ज हैं। चाहे बल्लभगढ़ रोड

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री धर्मपाल]

है, दिल्ली से अलवर रोड है और चाहे नैशनल हाई-वे रोड से कहीं को है। ऐसे कई रोड्ज हैं मैं कितने नाम यहां पर गिनाऊं। इस बारे में मैं सबसे पहले बादशाहपुर गौलवास सड़क जिसका 8 कि०मी० का टुकड़ा खराब है, का जिक्र करना चाहूंगा। इसकी हालत यह है कि इस पर बस का जाना भी बंद हो गया है। रोडवेज ने अपनी बस वहां पर इसलिए भेजनी बंद कर दी क्योंकि उस सड़क में बहुत गड्ढे थे बस आ जा नहीं सकती थी सब का बहुत नुक्सान होता था। इसी तरह से दूसरी सड़क दिल्ली से अलवर रोड पर घामरोज लिंक रोड़ है इसकी भी बहुत बुरी हालत है इसी तरह से दिल्ली अलवर रोड़ पर अलीपुर गांव की जो सड़क है उसका भी यही हाल है उसी के साथ-साथ एक गढ़ी बाजीपुर को रोड़ जाती है उसकी भी हालत खराब है। इसी तरह से पिचरसा से बाया बल्लभगढ़ रोड़ है यह 18-20 कि०मी० तक खराब है। अध्यक्ष महोदय, ये सारी ऐप्रोच रोड्ज हैं जोकि सारी ही टूटी हुई हैं। इसी तरह से बादशाहपुर से दरबारपुर हसनपुर रोड़ है उस पर भी बस का आना जाना बंद है क्योंकि वह टूटी हुई है। इसी तरह से मानेसर से कासन तक की सड़क भी बहुत खराब है। नैशनल हाई-वे नं० 8 से गांव ग्वालियर की सड़क और खेड़की की सड़क की भी हालत बहुत खराब है मैं इन सभी सड़कों के बारे में सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनको बनाने की तरफ जल्दी ध्यान दिया जाए और जनता को सुविधा दिलायी जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक जन-स्वास्थ्य विभाग की बात है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया था और बजट में भी इसका उल्लेख है। सन् 1994-95 में एक स्कीम आयी थी जिसमें आधा पैसा भारत सरकार और आधा पैसा हरियाणा सरकार का था। इस स्कीम के तहत पटौदी, सोहना, नारनौंद और कनीना आदि कस्बों को पेयजल की व्यवस्था की गयी थी। सरकार बताए कि इस स्कीम के तहत कितने बोरिंग और ट्यूबवैल्ज लगे ? मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि सोहना में कुछ कालोनीज में जैसे शिव कालोनी, पहाड़ कालोनी, वार्ड नं० आठ एवं वार्ड नं० दस में पीने का पानी नहीं पहुंचा है जबकि सरकार ने दावा किया है कि उसने 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया है। लेकिन जिन जगहों का मैंने नाम लिया है वहां पर दस लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस स्कीम को पूरा करवाया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, कृषि तथा उससे संबंधित कार्य ही किसानों की आय के साधन हैं। पशुपालन का जहां तक सवाल है। आज गाय और भैंसें बहुत महंगी हो गयी हैं। वैसे तो हरियाणा में दूध की मात्रा काफी अच्छी है यह मात्रा मेरे ख्याल में पूरे देश में पंजाब के बाद दूसरे नम्बर पर है। यहां पर 621 ग्राम यानी लगभग आधा किलो दूध एक आदमी के लिए उपलब्ध है। यह मात्रा बहुत अच्छी है लेकिन पशुओं के रख-रखाव के लिए और खासकर उनके उपचार के लिए मैं सरकार से और सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि पहले इस बारे में एक स्कीम थी हर जिले में एक पौली-क्लीनिक बनाने की। इस स्कीम के तहत ही हमारे गुड़गांव जिले में भी एक पौली-क्लीनिक का शिलान्यास चौधरी भजन लाल जी ने किया था उस पर सात या आठ लाख रुपये भी खर्च हो चुके थे लेकिन उसके बाद से वह बिल्कुल बंद पड़ी है। मेरा अनुरोध है कि इस पौली-क्लीनिक को पूरा करवाया जाए। इस क्लीनिक के लिए गांव खनीला वालों ने अपनी बहुत ही महंगी जमीन दी थी। अगर इसको पूरा करवा दिया जाता है तो इसका बहुत ज्यादा फायदा हमारे गुड़गांव जिले को मिलेगा। कई बार पशु चारे में सुई या कोई लोहे की चीज खा जाते हैं या उनको कोई और बीमारी हो जाती है अगर यह क्लीनिक पूरी हो जाएगी तो इसके द्वारा उनका उपचार अच्छी तरह से हो सकेगा और ऑपरेशन करके उस बीमारी को भी दूर किया जा सकेगा व किसान को होता हुआ नुकसान बच जाएगा साथ ही किसान की पशुपालन में रूचि भी बढ़ेगी। अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। वैसे तो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ किया गया है लेकिन जो तकनीकी

शिक्षा है उसे भी महत्व दिया जाना चाहिए। हमारे गांव मानेसर में जिला गुड़गांव की एक पौलीटैक्निक मानेसर के नाम से कार्यरत है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पॉलिटैक्निक में चार ट्रेड सैंक्शन किए गए थे। 1. मैकेनिकल, 2. इलैक्ट्रोनिक 3. प्लास्टिक इंजीनियरिंग और 4. इंस्ट्रूमैंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इन चारों में से एक ही ट्रेड चल रही है इसका कारण यह है कि कुछ तो भवन का अभाव था, लैबोरेटरी भी नहीं बन सकी थी। इसके अलावा यह भी पता चला है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेड है वह नीलोखेड़ी में चल रही है मेरा अनुरोध है कि हमारे वहां चारों ट्रेड चालू की जाएं। ताकि देहात के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके और इस इलाके का सुधार हो सके। इसके साथ-साथ और कई ऐसी बातें हैं जो कहने की हैं जैसे कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मात्र सात दस जमा दो स्कूल हैं अब भी ऐसे कई इलाके बाकी हैं जहां 10-10 गांवों में जमा दो स्कूल नहीं हैं मेरा अनुरोध है कि दस जमा दो स्कूलों को बढ़वा दिया जाए ताकि हर आदमी को और विशेषकर लड़कियों को मौका मिल सके। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री नफे सिंह राठी (बहादुरगढ़) : आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पिछले महीने की 22 तारीख को हरियाणा प्रदेश में असैम्बली के चुनाव हुए और किस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता ने समर्थन व्यक्त किया और समर्थन व्यक्त करते हुए सरकार बनाने का पुनःअवसर प्रदान किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने समर्थन लेते ही जो काम किए उन कामों की लोगों ने सराहना की और हरियाणा में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के स्तर पर उसकी सराहना हुई और इसी कारण चौटाला साहब की सरकार दोबारा सत्ता में आई। आज बजट पर जो चर्चा चल रही है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। प्रौफेसर संपत सिंह जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना शानदार बजट प्रस्तुत किया है जो हरियाणा की जनता के लिए विकास के नये मार्ग खोलेगा और हरियाणा में अमन, चैन और शांति कायम करेगा। लोगों की भावनाओं की कद्र होगी, आदर होगा। स्पीकर सर, पिछली सरकार के समय में जिस तरह से हरियाणा में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया वह आपके सामने है। पूरे हरियाणा की जनता जानती है कि चौधरी बंसी लाल के समय में किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई थी। विकास के कार्य नहीं हुए। लोगों से जो वायदे किए गए उनके बरखिलाफ काम करने का काम किया गया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी जिस तरह से कानून-व्यवस्था के मामले में और विकास के मामले में बहुत भेदभाव हुआ है। बहादुरगढ़ हल्के की बात मैं कहना चाहूंगा। स्पीकर सर, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में बहादुरगढ़ में एक नहीं दो नहीं बल्कि एक दर्जन छोटी-छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हुए। आठ साल की छोटी-छोटी बच्चियों को मार कर फैंक दिया जाता था। बेबी किल्लर कांड होते रहे लेकिन कांग्रेस सरकार आँख मीचकर बैठी रही और कोई कार्रवाई नहीं की गई। झूठे मुकदमे एक या दो आदमियों के खिलाफ जरूर बनाये गये। लेकिन अब बहादुरगढ़ में कानून-व्यवस्था की हालत में काफी सुधार है। मेरे हल्के बहादुरगढ़ का 70 किलोमीटर एरिया दिल्ली की सीमा से लगता है दिल्ली के कस्बों नजफगढ़, नांगलोई, चण्डी आदि में जो छोटी-छोटी कालोनियां होती है वहां दूसरे स्टेट्स से आकर लोग रहते हैं जिनमें क्राईम पेशे के लोग भी होते हैं। वे लोग हरियाणा में दाखिल होकर अपराध करते हैं फिर दिल्ली में चले जाते हैं। बहादुरगढ़ शहर को हरियाणा प्रदेश का गेट वे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। वे लोग बहादुरगढ़ में क्राइम करके दिल्ली में भाग जाते हैं। लेकिन जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार इस प्रदेश में आई है तब से उन दरिन्दों का हरियाणा प्रदेश में आने पर अंकुश लगा है और बहादुरगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। स्पीकर सर, इस बजट में बिजली

[श्री नफे सिंह राठी]

की समस्या को हल करने के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है और पिछले बजट के हिसाब से लगभग 142 करोड़ रुपया ज्यादा रखा गया है इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। स्पीकर सर, जहां तक पानी का सवाल है। मेरे एरिया में 22 टेलें नहरी पानी की हैं उन 22 टेलों में से 17 टेलें ऐसी थीं जिन पर लगभग आठ साल से पानी नहीं पहुंचता था। लेकिन आपको सुनकर खुशी होगी कि जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार इस प्रदेश में आई है तो उसने तमाम रजबाहों की सफाई करवाकर और सभी नहरों की सफाई करवाकर आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। नहरों के मामले में जो 775.17 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है वह बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। स्पीकर सर, जहां तक सड़कों का सवाल है। 1995 में प्रदेश में बाढ़ आई थी उस समय चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी लेकिन पूरे प्रदेश में बाढ़ के बाद किसी भी सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई। वे कहते थे कि सड़कों को मैंने ही बनवाया है और मैं ही सड़कों की मरम्मत और थेकली लगवाने का काम करूंगा। उन्होंने भी सड़कों की मरम्मत का काम नहीं करवाया। लेकिन जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई है आप देख रहे हैं कि प्रदेश की सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है कहीं पर गड्ढे भरने का काम चल रहा है तो कहीं पर सड़कों की रिपेयर का काम चल रहा है। स्पीकर सर, अब मैं खेलों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछली सरकार ने खेलों के मामले में खिलाड़ियों की अनदेखी की है और उस का परिणाम आज यह है कि हरियाणा के खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरियां करने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने खिलाड़ियों का नौकरियों में कोटा खत्म करने का काम किया था। 1992 में पुलिस विभाग के खिलाड़ियों को रिवर्ट कर दिया गया था जिसके कारण उन खिलाड़ियों को हाईकोर्ट में जाना पड़ा था। जबकि माननीय चौधरी देवी लाल जी ने खिलाड़ियों को नौकरी में कोटा देना शुरू किया था और जो खिलाड़ी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का होता उसे नौकरी में प्रमोशन दिया जाता था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने प्रमोशन देने की बजाए रिवर्शन करने का काम किया। स्पीकर सर, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं इसलिए मैं खिलाड़ी की भावना को जानता हूं। इन खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जितने भी खिलाड़ियों की रिवर्शन की गई है उनकी रिवर्शन वापस लेकर उनको पदोन्नति प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछली बंसी लाल जी की सरकार के समय में जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय हम भी इस सदन के सदस्य थे और आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी भी विपक्ष के लीडर थे किस तरह से बंसी लाल ने शहीदों को दी जाने वाली अनुदान राशि रो-रो कर पचास हजार से पांच लाख रुपये करने का काम किया था लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी ने आते ही उस राशि को 10 लाख रुपये करने का काम किया इसलिए हरियाणा के लोगों ने पूरी तरह से एकजुट होकर ओम प्रकाश चौटाला जी को, चाहे वे किसानों के लिए, चाहे व्यापारियों के लिए, चाहे कर्मचारियों के लिए, चाहे शहीदों के लिए काम कर रहे थे, जनादेश दिया। इसी प्रकार ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुंगी प्रणाली को खत्म करने का काम किया। यह चुंगी प्रणाली अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही थी। पिछली सरकार ने न केवल व्यापारियों को बल्कि शहर में रहने वाले 36 बिरादरी के लोगों को जो छोटा-मोटा सामान बाहर से लाया करते थे, चुंगी लगाकर परेशान करने का काम किया था। ओम प्रकाश चौटाला जी ने गन्ने का भाव 110 रुपये करके एक काबिले तारीफ काम किया है। कांग्रेस की सरकार गन्ने का भाव 50 पैसे बढ़ाया करती थी और आज ये वही कांग्रेस के लोग इस सरकार पर छींटा-कशी करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में बिजली की क्या दुर्दशा थी और बंसी लाल जी के टाइम में भी क्या थी, इस बात को आप सभी

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY

जानते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने आते ही बिजली के क्षेत्र में जो काम करके दिखाया है उससे लोग लाभान्वित और खुश हुए हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे हल्के में गए और वहां जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी तकलीफें दूर करने का काम किया। एक वे मुख्यमंत्री थे जिनसे एम०एल०ए० और मंत्री नहीं मिल पाया करते थे और एक ये मुख्यमंत्री हैं जो लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने का प्रयास ही नहीं बल्कि उनका निराकरण करते हैं। 1995 में कांग्रेस की सरकार थी उस समय बहादुरगढ़ में ऑटो मार्किट बनाने के लिए 21 एकड़ जमीन पर दफा 4 और 6 के तहत नोटिफिकेशन हो गई थी और नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों ने मिलकर प्रापर्टी डीलर्ज और जमींदारों को कहा कि तुम्हें सरकार कुछ नहीं देगी और उन पर दबाव डालकर उनको 3-3, 4-4 लाख रुपये देकर उनकी जमीनें खरीद ली, उन जमीनों में हरिजनों की भी जमीनें थीं। 21 एकड़ जमीन में एक कालोनी बनाकर 1200-1200, 1500-1500 रुपये गज के हिसाब से प्लाट काटने का काम किया गया उसके बाद बंसी लाल की सरकार आई जैसा कि अभी शादी लाल जी ने जिक्र किया था कि एक पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया, उस मंत्री का लड़का भी उस कालोनी में हिस्सेदार था और उन्होंने करोड़ों रुपए के वारे-न्यारे किए। इस तरह से लोगों को लूटा गया। पिछली सरकार में और उससे भी पहले की कांग्रेस की सरकार में लोगों पर जुल्म और ज्यादतियां हुईं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में सैक्टर 9 और 9-ए के लिए 1995 में दफा 4 के तहत नोटिफिकेशन हुई थी। बहादुरगढ़ शहर 1162 साल पहले बसा था और उस समय का एक शमशानघाट था उसको भी ऐक्वायर कर लिया गया है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पिछली सरकार में लोगों पर हुए जुल्मों और ज्यादतियों को सुधारा जाए और बहादुरगढ़ में सैक्टर 9 और 9-ए में ऐक्वायर किए गए शमशानघाट को छोड़ दिया जाए। स्पीकर सर, बहादुरगढ़ में कुछ ऐसे कार्य हैं जो पिछली सरकारों के समय में नहीं हो सके और वे इसलिए नहीं हुए क्योंकि वहां से हमेशा ही अपोजीशन का विधायक रहा है। वहां पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो होने बहुत ही जरूरी हैं। जैसे सोहटी सब-माईनर का काम पिछले काफी समय से नहीं हुआ है। इसी तरह से टांडाहेड़ी-नूनामाजरा माईनर है। इसका काम भी पिछले 20 सालों से नहीं हुआ है। वहां पर यह काम न होने से किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय जी से नम्र निवेदन है कि इस काम को जल्द से जल्दी पूरा करवायें। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त सांखोल और जसराणा माईनर हैं। उन पर भी विगत 20 साल से काम नहीं हुआ है। यह काम भी मुख्यमंत्री महोदय जल्दी ही करवायें ताकि वहां के किसानों की समस्या दूर हो। स्पीकर सर, हरियाणा के सभी शहरों की जो मेन समस्या है वह यह है कि जो सीवरेज हैं वे अक्सर बंद हो जाते हैं और उन सिवरेजों को खोलने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या को दूर करने के लिए सिवरेज का महकमा नगरपालिका को दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 29 नगरपालिकाएं तोड़ दी हैं। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नगरपालिका तोड़ी गई है उसका स्टाफ उसके नजदीक लगती नगरपालिका में ही भेजा जाये। खरखौदा नगरपालिका को भी तोड़ दिया गया है इसलिए इसका स्टाफ भी इसके लगती नगरपालिका में ही भेजा जाये। स्पीकर सर, बहादुरगढ़ में सिवरेज सिस्टम में बड़ी भारी समस्या है और इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब वहां पर डिस्पोजल सिस्टम लगाया जाये। इस सिस्टम के लिए वहां पर 4 एकड़ जमीन के लिए दफा-4 और दफा-6 के तहत नोटिफिकेशन हो चुकी है। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर दफा-9 के तहत नोटिफिकेशन करके जल्दी ही वहां पर काम शुरू किया जाये। स्पीकर सर, इसी के साथ जो बजट माननीय वित्तमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है जिसमें

[श्री नफे सिंह राठी]

कृषि, व्यापार, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, नहरों, पीने के पानी आदि को ध्यान में रखकर जो प्रावधान किया गया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस तरह से संपत सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और मैं इसका समर्थन करता हूं और सभी माननीय साथियों से निवेदन करता हूं कि वे भी इसका समर्थन करें। धन्यवाद।

श्री राम कुमार (गोहाना) : परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस गरिमामय सदन में मेरे को इस शताब्दी के प्रथम वार्षिक बजट का समर्थन करने के लिए आपने समय दिया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जो विकास का बजट पेश किया है इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। वाकई में यह बजट हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिये बनाया गया है। यह बजट आज तक का सबसे अधिक सार्थक और उपयोगी बजट है। इस बजट से यह साफ झलकता है कि सरकार प्रदेश की तरक्की के लिये सजग है और सही अर्थों में हरियाणा का विकास करना चाहती है। आज से पहले इतना बढ़िया, सार्थक और उपयोगी बजट कभी नहीं आया। इस बजट में बिक्री कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये बिक्री कर फार्म संख्या 14 तथा बिक्री कर फार्म संख्या 15 को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। कर रहित बजट पेश किया गया है इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। इस बजट में सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिये विशेष प्रावधान किया है तथा ग्रामीण व शहरों क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार सभी उपभोक्ताओं को नियमित बिजली सप्लाई करने के लिये वचनबद्ध है। सरकार ने यह भी एक सराहनीय कार्य किया है। सरकार ने इस बजट में गरीबी कम करने, आय तथा रोजगार के अवसर जुटाने, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा अन्य कृषि संबंधी विकास कार्यों का प्रावधान करके एक सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तम स्वास्थ्य मानव जीवन की सर्वोत्तम पूंजी है। सरकार ने इस सर्वोत्तम पूंजी के परिरक्षण के लिये राज्य में 2299 उप केन्द्रों, 401 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 44 अस्पतालों का प्रबन्ध करने का प्रावधान किया है। इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। इस बजट में गांवों तथा शहरों में बसने वाली 36 बिरादरियों के लोगों के लिये जो सराहनीय कार्य करने का प्रावधान किया गया है उसके लिये सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। यह बजट प्रदेश की तरक्की का बजट है। स्पीकर सर, मेरे हल्के गोहाना में बहुत सी समस्यायें हैं जिनके बारे में मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 50 सालों से गोहाना में एक शुगर मिल की स्थापना किये जाने की मांग चली आ रही थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आने से पहले भी बहुत सी सरकारें आईं लेकिन किसी ने भी गोहाना हल्के के लोगों की सुनवाई नहीं की। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने सत्ता में आते ही एक ही कलम से गोहाना के लोगों की इस मांग को स्वीकार कर लिया। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह बिसला चेयर पर पदासीन हुए) सभापति महोदय, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए उनसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नवम्बर से पहले-पहले इस शुगर मिल को चालू करा दें ताकि जिन किसानों ने अपना गन्ना जो रखा है उनका गन्ना नवम्बर में इस मिल में लाया जा सके। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र गोहाना की दूसरी समस्या यह है कि हमारे शहर में जमीन के नीचे का पानी खारा है और कड़वा पानी है और ट्यूबवैल लगाकर यही पानी घरों में दिया जाता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां डिग्गी बनवाकर नहर का पानी घरों में सप्लाई कराया जाए ताकि लोगों को पीने का

स्वच्छ पानी मिल सके जिससे कि उनकी सेहत और स्वास्थ्य ठीक रहे। सभापति महोदय, तीसरी समस्या देहाती जमीनों में भी खारा और कड़वा पानी होने की है। खारा पानी होने की वजह से जमीनें खराब हो जाती हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमारी नहरों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाए ताकि पानी टेल तक पहुंच सके और सारे खेतों की सिंचाई हो सके। इसके अलावा लड़कियों के लिए भी अलग से कालेज होना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे यहां मिनी सचिवालय भी नहीं है और अधिकारियों को इधर-उधर किराये की बिल्डिंग लेकर दफ्तरों में बैठना पड़ता है जिससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गोहाना में एक मिनी सेक्रेटेरिएट भी होना चाहिए। सभापति महोदय, हमारी पांचवी समस्या बाई पास की है क्योंकि गोहाना में बड़े-बड़े वाहन शहर के अन्दर से होकर गुजरते हैं जिससे सड़क पर जाम लग जाता है और पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है, आने-जाने में बड़ी असुविधा होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि गोहाना के अन्दर एक बाई-पास बनाना चाहिए जिससे कि बड़े-बड़े वाहन बिना किसी दिक्कत के अपने गन्तव्य स्थानों को जा सकें और लोगों को भी कोई परेशानी न हो। सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह गरिमामय बजट है। इस बजट की जितनी तारीफ की जाये कम है। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि यह बजट हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ले जायेगा। अन्त में सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री अजय सिंह : चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब ने मुझे बजट पर समय देने के लिए कहा था।

श्री सभापति : अभी आप बैठिये। बाद में आपको समय देंगे। अब श्री भागी राम जी बोलेंगे।

श्री भागी राम (ऐलनाबाद अनुसूचित जाति) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। बजट पर बोलते हुए सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हू कि इन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। इसके बाद में चौटाला साहब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने राज्य सभा की सीट के लिए होने वाले चुनाव में एक हरिजन जाति के व्यक्ति श्री फकीर चन्द जी को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। मैं इसके लिए चौटाला साहब का सभी हरिजन भाइयों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने अपने-अपने विचार हाऊस के सामने रखे। कई साथियों ने कहा कि सरकार की तरफ से हरिजन कन्याओं की शादी के समय कन्यादान देने वाली स्कीम जिसके तहत 5100 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं नाकामयाब रही यानी इस स्कीम का फायदा हरिजन भाइयों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा विधान सभा में हरिजन मैम्बरों की संख्या 17 है और इन 17 मैम्बरों में से 14 मैम्बर अकेले ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी के हैं। इसके अलावा दो मैम्बर्ज भी हमारी ही पार्टी जैसी पार्टी के मैम्बर्ज हैं। इसके अलावा जो एक मैम्बर बचे हैं श्री रामफल फौजी वे भी अपनी ताकत से कांग्रेस की नीतिओं के खिलाफ हाउस में जीत कर आये हैं। (विघ्न)

श्री रामकिशन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि हरिजन लड़कियों की शादी की स्कीम के तहत जो 5100 रुपये दिए जाते हैं यदि सरकार इसके साथ साथ उन्हें 40 किलो चावल और एक बोरी चीनी की और दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

श्री भागी राम : हरिजन भाइयों ने फैसला करके सारे के सारे विधायक चौटाला साहब की पार्टी 14.00 बजे के जिताए हैं तो आखिर कोई न कोई कारण तो है। चेयरमैन साहब जब से देश आज़ाद हुआ है या जब से हरियाणा बना है तब से ले कर हर चुनाव के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने हरिजनों के वोट बटोरने के लिए तरह-तरह के नारे दिए। कभी जमीन बांटने का नारा दिया, कभी प्लाट बांटने का नारा दिया, कभी गरीबी हटाने का नारा दिया और कभी कोई और नारा दिया। सभापति महोदय, इस चुनाव के अन्दर कोई अलग ही नारा दिया और वोट बटोरे। लास्ट में हरिजन भाइयों को हरिजन भाइयों से लड़ाने का काम भी इस कांग्रेस पार्टी ने किया। (विघ्न) आखिर में जब हरिजन ने सोचा तो उसको समझ आई। जब से देश आज़ाद हुआ और हरियाणा बना हरिजन वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते रहे लेकिन इस चुनाव के अन्दर सब हरिजन भाइयों ने सोच-समझ से काम लिया और आज सारे के सारे विधायक चौटाला साहब की पार्टी के जिताए (विघ्न) चेयरमैन साहब, चौटाला साहब ने आखिरकार हरिजनों के लिए कुछ काम किए होंगे। थोड़े से समय के लिए चौधरी देवी लाल जी को और चौटाला साहब को हरियाणा में राज करने का मौका मिला है। करीब 4-5 साल के शासनकाल में हरिजनों के लिए जो काम किए उनसे पता चलता है कि वे हरिजनों के कितने हितैशी हैं चाहे गांव में हरिजन चौपाल बनाने का काम किया, चाहे घुमन्तू परिवारों के बच्चे पढ़-लिख नहीं सकते थे उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के बाद हररोज एक रुपया हाजरी इनाम देने का काम किया। चेयरमैन साहब, सम्पन्न परिवार के किसी आदमी को पैंशन मिले चाहे न मिले लेकिन हरिजन परिवार जो कि गरीब हैं उनके घर के अन्दर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है जब उस परिवार के बुढ़े को 200 रुपये और बुढ़िया को भी 200 रुपये मिल जाते हैं तो उनको बहुत बड़ी मदद उससे मिलती है जिसके कारण वह बूढ़ा या बुढ़िया जब तक जीयेंगे चौधरी देवी लाल जी को हमेशा याद रखेंगे (विघ्न) आज वे लोग चौटाला साहब तथा चौधरी देवी लाल जो याद कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, इसी तरह से हरिजन कन्या के लिए 5100/- रुपये कन्यादान के रूप में देने का फैसला किया गया है। जब कभी कोई हरिजन आदमी पहले किसी अमीर आदमी से कर्ज लेने के लिए जाता था तो उसको कितने तो ऐफिडैविट्स पर दस्तखत करवा कर उससे दुगना-तिगुना ब्याज लगा कर वसूल करता था और उसके लड़के को घर में नौकर रखता था। 5100/- रुपये कन्यादान की राशि देने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बधाई के पात्र हैं। वह गरीब आदमी जिसके घर में बेटी जवान है और शादी के समय 5100/- रुपये मिल जाता है तो हरिजन के लिए इससे बड़ा और कोई सहारा नहीं हो सकता है। चेयरमैन साहब, इसी तरह से इन्टरव्यू के लिए जब कोई गरीब आदमी का बेटा जाता था तो उसे बड़ी दिक्कत होती थी और कई बार तो पैसे की कमी के कारण वह इन्टरव्यू पर जा नहीं पाता था लेकिन चौधरी देवी लाल जी ने इन्टरव्यू पर जाने के लिए आने-जाने का फ्री पास करके बहुत बड़ा फैसला किया था। अगर कोई बच्चा सिरसा से चल कर चण्डीगढ़ इन्टरव्यू देने के लिए आएगा तो उसको किराये के पैसे जुटाने में जो मुश्किल पेश आती थी उससे उसको राहत मिली है। नौकरी उसको मिले या ना मिले यह बाद की बात है लेकिन अब वह हर इन्टरव्यू अटैंड कर रहा है क्यों कि सिरसा से लेकर चण्डीगढ़ तक 200-300 रुपये किराये की राहत उसको मिल गई है। चेयरमैन साहब, इसी प्रकार से कई और महत्वपूर्ण फैसले हरीजनों के लिए किए हैं। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी तो उस सरकार ने पीले कार्ड का मामला टेकअप किया था। सारा हाउस चर्चा कर रहा है कि सभी हल्कों में पीले कार्ड बनने से बहुत से लोग राशन कार्ड के लाभ से वंचित रह गए हैं इसलिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह अपील करना चाहूंगा कि क्योंकि सम्पन्न परिवार वालों के तो पीले कार्ड बन गए हैं लेकिन जो असली गरीब लोग हैं उनके पीले कार्ड नहीं बने हैं और वे पीले कार्ड बनने से वंचित रहे गए हैं इसलिए मैं मुख्यमन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पूरी तरह से दोबारा से सर्वे होना चाहिए और जो वास्तव में गरीब

लोग हैं और पीले कार्ड बनने से वंचित रहे गए हैं उनके पीले कार्ड बनवाए जाएं। चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने हल्के की कुछ बातें कहना चाहूंगा। 1977 में मैं पहली बार चुनाव जीत कर आया था। एक चुनाव को छोड़कर मैं चुनाव जीतता रहा हूं। थोड़ा सा समय चौधरी देवी लाल जी को हरियाणा में राज करने का मिला था बाकि समय चौधरी भजन लाल जी और चौ० बंसी लाल जी का राज रहा है। इन्होंने ऐलनाबाद और सिरसा जिले के साथ भेदभाव रखा और इनके भेदभाव की वजह से आज सदन में लक्ष्मण दास जी रो रहे थे वे भजन लाल जी को अपनी बात तो कह नहीं सकते थे लेकिन हमारी सरकार के सामने रो रहे थे। मैं उनकी बात से सहमत हूं। (विघ्न) 1979 में चौधरी देवी लाल की सरकार बनी उस समय इन्होंने ऐलनाबाद में हॉस्पिटल बनाने के लिए नींव पत्थर रखा था, बिजली का 132 के०वी० का सब-स्टेशन बनाने के लिए, सिवरेज सिस्टम का और वाटर वर्कस बनाने का शिलान्यास किया था। भजन लाल जी की सरकार आई लेकिन उन पर काम नहीं किया गया। बंसी लाल जी की सरकार आई फिर भी उन पर कुछ काम नहीं किया गया। वहां पर शिलान्यास के पत्थर के पत्थर लगे रहे। उन शिलान्यासों के बाद न जाने कितने 132 के०वी० के सब-स्टेशन बने, सिवरेज, वाटरवर्कस और हॉस्पिटलज़ बने लेकिन ऐलनाबाद में आज तक कोई काम नहीं किया गया है। यह सब वहां पर बदले की भावना की वजह से किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर जो अभी तक काम नहीं किए गये हैं वे काम करवाएं। चेयरमैन साहब एक बार मैं भी मंत्री बना था। उस वक्त मैंने ढानी लक्षजी, काशीराम कबार और ऐलनाबाद में वाटर वर्कस बनाने की मंजूरी दी थी और उनका शिलान्यास भी किया था। उसके बाद वहां पर ट्यूबवैल्ज़ बोर हुए। चूंकि उस समय वहां पर गांवों के लोगों को पानी की दिक्कत थी इसलिए मैंने बिना बिल्डिंग के, बिना चार दीवारी के वहां पर कनेक्शन दे दिए और काम शुरू करवा दिया। सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनकर हैरान होंगे कि आज तक वहां पर बदले की भावना से न तो चार दीवारी बनवाई गई है न ही कोई बिल्डिंग बनवाई गई है। वहां पर आज भी बड़ा बड़ा घास खड़ा है। चौधरी भजन लाल ने और चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा में राज किया। चौधरी देवी लाल जी को तो राज करने का थोड़ा सा समय मिला था। अभी थोड़ी देर पहले सभी मैम्बर्स यहां पर इस बारे में कह रहे थे, रो रहे थे तो वे सब इन दोनों को ही रो रहे थे। क्योंकि वे इनके राज से दुखी थे। आज इन दोनों के कारनामों की वजह से आदरणीय चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने हैं। चेयरमैन साहब, मैं चौटाला साहब का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही नये ओटू वीयर को बनाने का शिलान्यास किया। बरसात के सीजन में पंजाब एवं हिमाचल का पानी हमारे सिरसा जिले से होकर गुजरता है जब ज्यादा पानी वहां पर हो जाता है तो उससे वहां की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पुराना ओटू वीयर अंग्रेजों के जमाने का था और अब वह बिल्कुल कंडम हो चुका था लेकिन अब मुख्यमंत्री द्वारा नये ओटू वीयर का शिलान्यास करने के बाद उस पर रात और दिन काम चल रहा है। चेयरमैन महोदय, मैं इसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि डबवाली रोड पर जो रेलवे लाइन है, वहां तक जमीन ऐक्वायर करके पानी इकट्ठा किया जाना चाहिए। बाद में इस पानी को नहरों में दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय अभी बैठे नहीं हैं लेकिन वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री यहां पर बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ऐलनाबाद और रानियां दो कस्बे हैं इन दोनों कस्बों में नगरपालिकाएं हैं और दोनों कस्बों में ही प्लस टू स्कूल है। आज शिक्षा की हर जगह जरूरत है हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है हर मां-बाप अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहता है इसलिए मेरा इन दोनों मंत्रियों से अनुरोध है कि ऐलनाबाद और रानियां में एक-एक कॉलेज जरूर बनाया जाना चाहिए। इस बारे में मेरा एक क्वैश्चन भी है। अंत में मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिना टैक्स का बजट पेश किया। धन्यवाद।

श्री भीम सेन (इंद्री) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद। सर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में जो वित्त मंत्री जी ने कर मुक्त बजट पेश किया है उससे प्रदेश के सभी वर्गों को सभी लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई कर नहीं लगाया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। आज से कुछ महीने पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे इंद्री में "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत गए थे। उस समय उन्होंने वहां पर काफी घोषणाएं की थीं जिनमें काफी घोषणाएं तो उनकी कार्य कुशलता के कारण पूरी हो गयीं मगर कुछ घोषणाएं ऐसी रह गयीं जिनका उल्लेख मैं यहां पर करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है, आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी हल्के की बकाया घोषणाओं को भी पूरा करेंगे। उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि वहां पर हैफेड का शैलर लगाया जायेगा। इसके अलावा उन्होंने वहां पर जो शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज है उसको सरकारी कालेज बनाने का वायदा किया था। इसी तरह से उन्होंने वहां पर डब्ल्यू०जे०सी० के ऊपर एक पुल बनाने की भी बात कही थी। इसी तरह से मेरे हल्के के गांव बीना में एक पावर हाउस बनाया जाना है उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है मैं अनुरोध करूंगा कि उस पर भी काम शुरू करवाया जाए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणाओं में से अभी तक जो पूरी नहीं हुई है उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे पूरी की जाएं। इसके साथ ही हमारे हल्के के अंदर जो सड़कें टूटी पड़ी हैं जिनकी काफी खस्ता हालत है उनकी भी मरम्मत की जाए। ऐसी ही एक सड़क मुरादगढ़ गांव से लेकर बड़े गांव एवं शाहपुर तक की है उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है और एक बात कहते हुए मैं फख्र महसूस करता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो बात कहते हैं वही करते हैं। ऐसा हमने पिछले शासन काल में जब हम इनकी सरकार में मंत्री थे, तब देखा था। जितने भी कार्यों की घोषणा की थी वह कार्य पूरे किए हैं और उसी विश्वास के साथ आज फिर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं और याद दिलाता हूं कि जो घोषणायें उन्होंने मेरे हल्के के लिए की थीं उन्हें पूरा करें ताकि मेरे हल्के के अंदर जो विकास के कार्य बकाया पड़े हैं वह पूरे हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापति : श्री जीतेन्द्र सिंह मलिक अभी तक इस हाउस में नहीं बोले हैं मैं चाहता हूं कि यदि वे बोलना चाहें तो विपक्ष के नेता उन्हें बोलने के लिए बुला लें। तब तक श्री भगवान सहाय रावत बोल लें।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन) : आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस सहस्त्राब्दी के प्रथम वार्षिक बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए इस बजट की वास्तविकता से परिचित होते हुए सदन के सम्मुख इसके सकारात्मक पहलू पर अपने कुछ विचार मैं रखना चाहूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि एक जनकल्याणकारी सरकार की स्थापना के बाद राज्यपाल का अभिभाषण जहां दिशानिर्देश करता है वहां सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट भविष्य की योजनाओं पर दृष्टिपात करता है। हमारे सभी साथी विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आए हैं उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रवार समस्याओं व उनमें विकास के कार्य करवाने के प्रति रूचि है इसके साथ-साथ पूरे राज्य को दृष्टिगत रखकर बजट का प्रावधान किया गया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। सर्वप्रथम तो मैं यह जो करमुक्त बजट है उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता इससे पहले बजट प्रस्तुत होते रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि किसी बजट में टैक्सिज का न लगाया

जाना एक सकारात्मक पहलू में आता है। केन्द्र स्तर पर सबसिडी में कटौती अभी भी विचाराधीन है हमारी प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है कि ऐसे में उसने सबसिडी को मेनटेन किया है और कई ऐसी जगह भी हैं जहां उन्होंने सबसिडी को इन्क्रीज किया है जैसे पॉवर सैक्टर, फूड, फर्टीलाइजर सैक्टर में सैन्ट्रल गवर्नमैंट सबसिडी रिड्यूस करने जा रही थी उस सबसिडी में बढ़ोत्तरी करके सराहनीय काम किया है। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। सिंचाई सुविधाओं के बारे में सरकार ने 412 करोड़ रुपये का जो बजट में विशेष प्रोविजन किया है उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। खाद और बीज जैसी चीजों पर विशेष ध्यान देकर उसके लिए भी सरकार ने विशेष राशि का प्रावधान इस बजट में किया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इसका एक जो सकारात्मक पहलू है वह यह है कि केन्द्र सरकार के स्तर पर सेलटैक्स की समान दर स्वीकार की गई है और उस यूनीफार्म दर का पालन करते हुए भी एक डायनामिक बजट प्रस्तुत किया है। खासकर हमारा जो ऐग्रीकल्चर सैक्टर है उसमें ज्यादा उत्पादन करने के लिए एम०आई०टी०सी० और जो दूसरी सिंचाई सुविधायें हैं उनमें वृद्धि करके सरकार ने सराहनीय काम किया है। चेयरमैन सर, मैं मेवात क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं वह क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी और वर्तमान सरकार भी हम लोगों के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मेवात क्षेत्र में सिंचाई के लिए या तो मेवात कैनाल या फिर आगरा कैनाल से पानी मिलता है। लेकिन आगरा कैनाल की मैनेजमैंट का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथों में है जिसके कारण हमें अपना पूरा पानी समय पर नहीं मिल पाता। तत्कालीन चौधरी देवी लाल जी की सरकार में भी मैं विधायक था उस समय भी मैंने इस बात को उठाया था और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इस सदन में लाया गया था। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आगरा कैनाल की मैनेजमेंट का कार्य सरकार अपने हाथों में ले इसके लिए चाहे केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई समझौता किया जाये। ताकि मेवात ऐरिया को अपने हिस्से का उचित पानी मिल सके। सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि समतल भूमि होने के कारण मेवात क्षेत्र का हरियाणा प्रदेश के उत्पादन में काफी योगदान रहा है। माननीय सदस्य श्री बलबीरपाल शाह ने गौ हत्या के बारे में मेरे हल्के का जिक्र किया। इसलिए मैं उनके सवाल का जवाब देना वाजिब समझता हूं। सभापति महोदय, मैं उस हल्के का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें 36 बिरादरी हैं। शायद इन्होंने सुना है देखा नहीं है कि साम्प्रदायिक सद्भाव कैसा होता है। एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि जब 1947 में हिन्दू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई तब भी मेवात क्षेत्र के हिन्दू-मुसलमान एक थे उनकी तब भी आपस में लड़ाई नहीं हुई। वहां पर हिन्दू-मुसलमानों के दो गुट थे कभी लड़ाई होती थी तो उन दोनों गुटों की ही होती थी। जैसे मैं रावल हूं तो रावत और डमरोथ मुसलमानों की पाल एक तरफ होती थी और दूसरी तरफ जाट शोरोथ और बिरकलोथ मुसलमानों की पाल होती थी। ये जाट और मुसलमान की दो पाल थी इन दोनों गुटों की लड़ाई ही होती थी। लेकिन जैसा कि शाह साहब ने गऊ हत्या की बात की है। (विघ्न)

श्री जयप्रकाश : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है क्योंकि यह कोई बजट पर स्पीच नहीं है।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : सभापति महोदय, मेरी एक सबमिशन है कि कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों ने 2-3 नई परम्पराएं शुरू की हैं। पहले किसी बात की शुरूआत कर देते हैं जब उस बात का जवाब दिया जाता है तो सारे साथी खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य श्री बलबीर पाल शाह ने मेवात क्षेत्र की इस सदन में चर्चा की है तो हमारी पार्टी के साथी ने उसका जवाब देना शुरू किया तो अब वे इसका एतराज कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री भगवान सहाय रावत : सभापति महोदय, मैंने तो एक मिनट की भी चर्चा नहीं की कि माननीय कांग्रेस के सदस्य उसी में तिलमिला गये हैं। मेरे हल्के का नाम आया था इसलिए मैं उनकी बात का जवाब देना जरूरी समझता था। सभापति महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है इसलिए कृषि के क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करके इस सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाया है जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इसके अतिरिक्त सोशल सैक्टर के बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आदरणीय देवी लाल जी ने सामाजिक क्षेत्र में समाज कल्याण हेतु 36 बिरादरी के लोगों के लिए एक समान व्यवस्था करके, समान पैंशन देकर जो सराहनीय कार्य किया है, मैं समझता हूं उनके लिए एक इतिहास लिखा जाना चाहिए और हम सभी सदस्यों को एकमत होकर प्रस्ताव पास करना चाहिए। यह निहायत ही एक अनुकरणीय कदम है। सरकार ने जो हरिजनों की लड़की की शादी के लिए 5100 रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी है उसके बारे में मैं रिपीटीशन में नहीं जाना चाहता, लोग सुनते-सुनते थक जाते हैं। यह इतनी कल्याणकारी योजना है जिसका बजट में स्पैशल प्रोविजन किया गया है इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। एजुकेशन का मुद्दा एक मुख्य मुद्दा है। मैं एक अध्यापक रहा हूं। मुझे सौभाग्यवश दूसरी बार इस विधानसभा में आने का मौका मिला है। मैं एजुकेशन को सबसे ज्यादा इम्फेसाइज करके इस बारे में कहना चाहूंगा। आज इस बजट प्रोविजन में शिक्षा के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं, उसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूं। सभापति महोदय, मैं हथीन क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं। मैं शैक्षणिक दृष्टि से अपने क्षेत्र पर आपका दो मिनट का समय लेना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं फख्र के साथ कहता हूं कि चौ० देबी लाल जी ने उटावड़ में एक पौलिटैक्निक कालेज खोला जो कि हमारे मेवात क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के द्वारा कार्य किया जा रहा है लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से हमारा क्षेत्र लड़कियों की शिक्षा में बहुत पीछे है। लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से पौलिटैक्निक कालेज की स्थापना के लिए प्रार्थना की और कालेज खोल दिया गया था। इस बजट में शिक्षा के लिए टोटल 1352.99 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। जब मुख्यमंत्री महोदय, पलवल के पौलिटैक्निक कालेज उटावड़ में गए थे तो वहां उनको उनकी लोकप्रिय नीति सरकार आपके द्वार के द्वारा हमारी ग्राम पंचायतों का एक डैपुटेशन मिला था जिसमें लोगों ने उनको सम्बोधित करते हुए कहा था कि हमारे इलाके की एक ही मांग है कि बहीन में जो 900 बीघा पक्की जमीन पड़ी हुई है वहां पर रिजनल सैन्टर और एग्रीकल्चर कालेज की स्थापना के लिए हमसे किए गये वायदे को पूरा करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस कालेज की स्थापना के लिए कोई कदम उठाना चाहिए और इस बजट में उसका कोई प्रावधान होना चाहिए था अन्यथा भविष्य में सरकार इस बात को ध्यान में रखे। उटावड़ पौलिटैक्निक कालेज की स्थापना वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत की गई थी और उसके साथ भारनौल में भी एक पौलिटैक्निक कालेज की स्थापना की गई थी। दोनों कालेजों का इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत सुविधाएं बराबर की हैं। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां के कालेजों में आज भी नान इंजीनियरिंग के 2 कोर्सिज हैं और इंजीनियरिंग का केवल एक ही कोर्स है। जबकि टैक्नीकल कालेजों में सारे इंजीनियरिंग कोर्सिज होते हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने नीलोखेड़ी और रोहतक के कालेजों को जहां पर सारी सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध थीं, को इंजीनियरिंग कालेज घोषित कर दिया। इसी आधार पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उटावड़ के पौलिटैक्निक कालेज में इंजीनियरिंग के और कोर्स शुरू किए जाएं। आज पूरे दक्षिणी हरियाणा के लोगों की एक भूख और प्यास है कि उनके मेवात एरिया में कोई यूनिवर्सिटी खोली जाए।

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के पास लगती है जहां पर सम्पूर्ण भारत बसता है। हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सटीज़ पहले से ही हैं, मेवात एरिया में यूनिवर्सिटी खुल जाने से हम पूरे हरियाणा को दिल्ली की तुलना में खड़ा कर देंगे। मैं चौ० ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने देवी लाल जी की गोद में, उनके चरणों में राजनीतिक शिक्षा ग्रहण की है, से और उनकी सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे दक्षिणी हरियाणा के मेवात एरिया के लोगों की जरूरतों को देखते हुए एक यूनिवर्सिटी खोलने की कृपा करें। इसके लिए जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ अरावली हिल्स के साथ जमीन भी उपलब्ध है और सारी फैसीलिटीज भी उपलब्ध हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय की भावनाओं का आदर करते हुए इनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कर रहित बजट प्रदेश के लोगों को दिया। इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (धन्यवाद)

श्री सीता राम (डबवाली, अनुसूचित-जाति) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से बजट के ऊपर मुझे बोलने का समय मिला इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और वित्त मंत्री महोदय ने जो कर रहित बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान डबवाली हल्के की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहूंगा। पिछली सरकारों ने इस हल्के के प्रति भेदभाव की नीति अपनाई और इस हल्के में विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं किया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस हल्के की तरफ वे विशेष रूप से ध्यान दें। ताकि वहां के लोगों की भी समस्याएं दूर हो सकें। सभापति महोदय, सिरसा जिले के अंदर डबवाली पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां पर विधार्थियों के लिए एक भी सरकारी कालेज नहीं है। यहां के विधार्थियों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि डबवाली में भी एक सरकारी कालेज की स्थापना की जाए। सभापति महोदय, चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में डबवाली में कालेज के लिए जमीन अधिग्रहण हुई थी लेकिन बाद की सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं चौटाला साहब से अनुरोध करूंगा कि वहां पर सरकारी कालेज बनवाया जाये। सभापति महोदय, यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। इसके साथ पंजाब का मुक्तसर जिला लगता है जिसे पंजाब ने पिछड़ा हुआ इलाका घोषित किया हुआ है। इसी कारण से वहां पर उद्योग पलायन कर रहे हैं। मेरा भी मौजूदा सरकार से अनुरोध है कि डबवाली को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ इलाका घोषित किया जाये ताकि वहां भी नये-नये उद्योग लग सकें और वहां के युवकों को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि डबवाली में बहुत ही भयंकर अग्निकांड हुआ था। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार यह नीति बनाये कि उस काण्ड में जिन लोगों की जानें गईं उनके परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाये। सभापति महोदय, यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहां के किसानों की माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर कृषि पर आधारित ऐसा उद्योग लगाया जाये जिससे वहां के किसानों की माली हालत सुधर सके। सभापति महोदय, इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए अंत में मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री दरियाव सिंह (झज्जर, अनुसूचित-जाति) : सभापति महोदय, वित्तमंत्री महोदय ने कर रहित बजट प्रस्तुत किया इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झज्जर जिले की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहूंगा कि झज्जर जिला तो बन गया है लेकिन वहां पर जिले जैसी सुविधाएं नहीं हैं। वहां पर रेलवे लाइन भी नहीं है। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री

[श्री दरियाब सिंह]
महोदय को कहना चाहूंगा कि वे केन्द्र सरकार से बात करके वहां पर एक रेलवे लाइन बिछाने का प्रबंध करवायें। सभापति महोदय, झज्जर शहर के अंदर बस-अड्डा भी नहीं है और न ही बस का डिपू है इसे सब-डिपू बना रखा है। इस बारे में मैं चौटाला साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर बस-अड्डा और सब-डिपू की जगह बस डिपू बनवाया जाये। सभापति महोदय, चौटाला साहब ने अपने 8 महीने के कार्यकाल में यह साबित कर दिया कि वे ही हरिजनों के सबसे बड़े हितैषी हैं। वे जो कुछ कहते हैं वह करके दिखाते हैं। सभापति महोदय, बहन जी अनिता यादव कह रही थीं कि झज्जर के अंदर हरिजन की लड़की की शादी के समय जो कन्यादान का पैसा 5100/- रुपये मिलता है वह कन्यादान का पैसा नहीं मिला। यह बात वे बिल्कुल गलत कह रही थीं। क्योंकि झज्जर के अंदर सभी को यह पैसा मिला है। एक-आध केस ऐसा हो सकता है जिसके कागज पूरे न होने की वजह से उसको ये पैसे न मिले हों बाकी सभी हरिजन लड़कियों की शादी के वक्त 5100/- रुपये कन्यादान के रूप में सरकार की तरफ से मिले हैं। सभापति महोदय, चौटाला साहब ने बुढ़ापा पैंशन 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करके बहुत ही अच्छा काम किया और अपना वायदा भी पूरा किया। सभापति महोदय, चौधरी देवी लाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ही ऐसे नेता हिंदुस्तान और हरियाणा में हैं जो अपना वायदा निभाते हैं। कांग्रेस के नेता भी हैं, चौधरी बंसी लाल जी भी हैं, ये जो कुछ कहते हैं वह नहीं करते। अपना वायदा पूरा नहीं करते। लेकिन चौधरी देवी लाल जी और चौटाला साहब ने जो कहा है वह करके दिखाया है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सरिता (कलानौर, अनुसूचित-जाति) : सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूं। बजट में बहुत से प्रावधान रखे गये हैं जो कि बहुत ही सराहनीय हैं। हरियाणा में आर्थिक आधारभूत सुविधाओं के लिये विशेष ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा और स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य, अनुपूरक पोषण, आवासीय क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये 120 करोड़ रुपए का प्रावधान करना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को इस बजट में रखा गया है। इसके अलावा चुंगी समाप्त करना, अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रान्ट बहाल करना, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नई मंडियों के विकास और वर्तमान मंडियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, मंडी व्यापारियों को जनवरी, 2000 से 21 वस्तुओं पर मार्किट शुल्क दो प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करना, पशु धन विकास को सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा पशु धन विकास बोर्ड का गठन करना जैसे महत्वपूर्ण काम सरकार ने किये हैं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने हल्के कलानौर की तरफ दिलाना चाहती हूं। यह बहुत ही पिछड़ा हुआ हल्का है। अगर इसे सुधारने के लिये 10 साल भी मिलें तो भी कम हैं। अध्यक्ष महोदय, 1995 में कलानौर में आई०टी०आई० के निर्माण के लिये नींव पत्थर रखा गया लेकिन उसके लिये ऐसी जगह चुनी गई जो बहुत ही गहरी है। अगर इस आई०टी०आई० के निर्माण के लिये 10 लाख रुपये भी मिलते हैं तो 10 लाख रुपये उस गहरी जमीन को मिट्टी भरने में और उसका लैवल सड़क के बराबर करने में लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपने हल्के की ओर दिलाते हुए यह बताना चाहती हूं कि इस हल्के में पानी की भी बहुत समस्या है और वहां की महिलाओं को दूर-दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर बहुत सी सड़कों के निर्माण के लिए टैण्डर तो पास हो चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। वहां पर सड़कों पर मिट्टी भी डाली हुई है और पत्थर-रोड़ी वगैरा भी पड़ी है लेकिन काम शुरू होने के बाद भी अधूरा पड़ा है। इन सड़कों के नाम इस प्रकार है : बनियानी से माडोधी तक, भाली से गढ़ी खेड़ी तक का 2 किलोमीटर का

रास्ता, सांगा हेड़ा से पिलाना तक का पक्का रोड, आंबल से निगाना रोड, बहुजमाल पुर से छोटा सिंहपुरा तथा जींदराण से बेरी रोड तक का 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि अभी तक मेरे हल्के की अनदेखी की गई है। मेरे हल्के के साथ बड़ा ही सौतेला व्यवहार हुआ है। मेरे हल्के की पूर्व विधायिका ने इस हल्के की अनदेखी की है और मेरे हल्के में सुधार नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे हल्के में शिक्षा का भी बड़ा अभाव है। खेरड़ी गांव में एक आठवीं तक का स्कूल है इस स्कूल को भी अपग्रेड कराकर दसवीं तक करायें क्योंकि वहां की हमारी जवान-जवान बेटियों को जीपों और बसों में लटक-लटक कर भिवानी या कलानौर आना पड़ता है। कलानौर में एक ही भवन में सुबह और शाम की दो-दो क्लासिज लगती हैं इसलिये मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर स्कूल के और कमरों का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा खेड़ी गांव में बच्चों के लिये कोई स्कूल नहीं है। निगाणा और सांगाहेड़ा में यातायात की भी बड़ी असुविधा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि इन गांवों में बस सेवाओं को बहाल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री रामफल कुण्डू (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, 14 मार्च को हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा बजट है। सरकार ने 2000-2001 की वार्षिक योजना में सभी वर्गों के उत्थान के लिए पैसे का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि मैं सभी वर्गों को 24 घंटे बिजली दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री ने अपने अल्प काल के समय में ही सभी वर्गों को 24 घंटे बिजली देकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बिजली की सप्लाई ठीक ढंग से हो सके इसलिए हर पावर हाउस के ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। इतना ही नहीं जहां जहां पर बिजली की तारें बदलने की आवश्यकता है वहां पर तारें भी बदली जा रही हैं। ये सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हर जगह 24 घंटे बिजली लोगों को बराबर मिलती रहे। इस नेक कार्य के लिए मैं पुनः चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। हमारी सरकार ने अल्प समय के अन्दर ही नहरों की सफाई करके, उनकी गाद आदि निकलवा कर और उनकी खुदाई करवा कर हर टेल तक पानी पहुंचाया है। इसके अलावा सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए 770 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस स्कीम पर भी जल्दी से जल्दी कार्य शुरु करवाने का फैसला लिया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वृद्धावस्था, विकलांग व विधवाओं की पैन्शन को भी पहले से दुगुना करके 200 रुपये प्रतिमास करके एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सरकार ने इन लोगों की जो पैंशन डबल की है उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार आपके द्वार जो प्रोग्राम सरकार ने चलाया था उसके तहत जो-जो वायदे वहां पर किए गए थे उन सब पर 90 की 90 कान्स्टीच्यूएंसीज में काम चल रहा है। कई साथियों ने आरोप तो लगाया कि जो-जो वायदे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोग्राम के तहत किए थे उन पर काम नहीं हुआ लेकिन इन विरोधी भाइयों में से किसी ने यह नहीं कहा कि हमारे हल्के में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत यह वायदा किया था और उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो जो वायदे किए थे उन सब को

[श्री रामफल कुण्डु]

पूरा किया जा रहा है। भजन लाल जी ने भी कहा था कि सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत इतने वायदे कर लिए हैं कि वे आने वाले 30 सालों में पूरे नहीं हो सकते। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहता हूं कि आने वाले 30 महीनों में सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत जो-जो वायदे किए थे वे सभी के सभी पूरे कर लिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो सड़कें 7-8 साल से टूटी पड़ी थी उनका पैच वर्क भी सरकार ने नवम्बर तक मुक्कमल करवा दिया है और अब आने वाले मई-जून महीने तक उन पर कारपेट का काम भी पूरा कर लिया जायेगा। अन्त में स्पीकर साहब, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब श्री सूरजमल जी बोलेंगे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप उन्हीं के मैम्बर्ज को बोलने का समय दे रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी पार्टी के मैम्बर्ज को बोलने के लिए आप समय दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आपकी पार्टी को अब तक 300 मिनट में से 126 मिनट का समय दिया जा चुका है। मैं सभी को पार्टी अनुपात के हिसाब से बोलने के लिए समय दे रहा हूं। अब श्री सूरजमल जी बोलेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) दलाल साहब, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए आपकी बात रिकार्ड नहीं की जा रही है। (विघ्न) जो दलाल साहब बोल रहे हैं रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) श्री सूरज मल जी अब आप बोलें।

श्री सूरज मल (राई) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय प्रदान किया। वित्त मन्त्री जी ने जो कर रहित बजट पेश किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मेरे से पहले बजट पर बोलते हुए मेरे साथियों ने काफी बातें उठाई हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी ने बजट को सराहा है और मैं भी इस बजट की सराहना करता हूं। मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की कुछ बातें मुख्यमन्त्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के राई से 12-13 सालों से ओपोजीशन का ही विधायक रहा है। इसलिए हर सरकार ने राई हल्के की उपेक्षा की है। चाहे चौधरी भजन लाल जी का राज रहा हो या चौधरी बंसी लाल का राज रहा हो लेकिन मेरे हल्के में कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। (विघ्न) मैं अपने हल्के की एक-दो महत्वपूर्ण बातें माननीय मुख्यमन्त्री जी को बताना चाहता हूं। मेरा हल्का यमुना के साथ लगता है यमुना के साथ लगती हमारी जमीनों को जबरदस्ती यू०पी० के लोग बो रहे हैं तथा हमारी फसलें जबरदस्ती काट ले जाते हैं। वहां पर यू०पी० के लोगों का और हमारा झगड़ा रहता है। कई बार वहां पर गोलियां चलती हैं और वहां पर बड़ा खतरा रहता है लेकिन किसी भी पिछली सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और इस बात का कोई समाधान नहीं ढूंढा है। दीक्षित अवार्ड के बावजूद यू०पी० के लोग जबरदस्ती उन जमीनों को बो रहे हैं और हमारी अपनी जमीनों पर हमें फसल नहीं बोने देते हैं। मैं मुख्यमन्त्री जी को इस बात से अवगत करवाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं दीक्षित अवार्ड को लागू करवाएं तथा हमारी जमीनें जिन

**चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

पर जो हमारा हक बनता है हमें दिलवाई जाएं। पिछली किसी भी गवर्नमैंट ने दीक्षित अवार्ड को लागू करने का प्रयास नहीं किया। अब जब कि हमारी अपनी सरकार आई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमन्त्री जी इस बारे ध्यान देंगे और हमारा हक हमें दिलवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के राई के अन्दर रेत की खानें हैं तथा गवर्नमैंट उनको नीलामी पर ठेके पर छोड़ती है। लेकिन ठेकेदार क्या काम करते हैं कि गवर्नमैंट से जो ठेके लेते हैं उन ठेकों को आगे बेच कर लोगों से नाजायज तौर पर जबरदस्ती जमीनें किराये पर लेते हैं और वक्त पर उन लोगों को पैसा भी नहीं दिया जाता है जिसके कारण हमारे लोगों को काफी परेशानी होती है। गवर्नमैंट का कर बचाने के लिए उन खानों के बजाए जबरदस्ती दूसरी जगहों का इस्तेमाल करते हैं तथा काफी रुपया इस ढंग से वे ठेकेदार कमाते हैं तथा गवर्नमैंट को दिए जाने वाले कर को भी चोरी करते हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर पूरा ध्यान दे कर काम करे तो इसमें सरकार को बहुत बड़ी आमदनी भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, राई गांव में मार्किटिंग बोर्ड ने मण्डी बनाने के लिए जमीन एक्वायर की हुई है लेकिन वहां पर आज तक मण्डी का काम नहीं हुआ है। वह काफी जमीन है और ऐसे ही पड़ी हुई है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि राई गांव में मण्डी बनाने का काम करवाएं। हमारे एरिया के अन्दर लड़कियों का कोई कालेज नहीं है, हां सोनीपत शहर में कालेज हैं। हमारे यहां पर लड़कियां 12वीं जमात तक पढ़कर घरों में बैठ जाती हैं क्योंकि उनको कालेज में पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता है जोकि बहुत दूर है। बसों में लड़कियों को चढ़ने नहीं दिया जाता है और उनको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि मुरथल में लड़कियों का एक कालेज बनाया जाए ताकि उनको आगे पढ़ने का मौका मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक बीयर फैक्टरी थी चौधरी भजन लाल जी ने उसको बेच दिया था बेचने के बाद ये तो उसको छोड़ कर चले गए। जब चौधरी बंसी लाल जी आए तो इन्होंने उसको बिल्कुल बंद ही कर दिया। उस फैक्टरी में 300-400 के करीब लोग काम करते थे और वे बेरोजगार हो गए। इस बारे में हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बताया तो उन्होंने 30-40 को काम पर लगवाया है। मैं चौधरी साहब से फिर से कहूंगा कि वहां पर जो लोग काम करते थे उनको दोबारा से काम पर लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के वक्त मुरथल में 30 बैड का एक हास्पीटल मंजूर किया गया था। उस वक्त वहां की पंचायत ने उसके लिए 70 हजार रुपए जमा करवाए थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस हास्पीटल को दोबारा से मंजूर करके बनवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर 500-600 एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है उस पर कुछ लोग नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। हम उस जमीन को गवर्नमैंट को फ्री में देना चाहते हैं। अगर सरकार उस जमीन को एक्वायर करके वहां पर कोई एग्रीकल्चर संस्था खोल दे तो बहुत ही अच्छा होगा उससे वहां के लोगों को भी फायदा हो सकेगा। मैंने जो बातें कहीं हैं उस पर सरकार गौर करे और उन कामों को करवाने की कृपा करें यही मेरा सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तक रूलिंग पार्टी से 6 सदस्य बोल चुके हैं लेकिन हमारी तरफ से कोई भी सदस्य नहीं बोला है। हमें भी बोलने का समय दें। अगर आप ही हमें बोलने का समय नहीं देंगे तो हम अपने हल्के की बात कैसे कह पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी 21 में से 7 मैम्बर्ज आपके बोले हैं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि अपोजीशन इस बात से सहमत थे कि जो सदस्य गवर्नर साहब के एड्रैस पर नहीं बोले हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

आपको तो स्पीकर साहब, की उदारता का आभार प्रकट करना चाहिए। (विघ्न) चौधरी साहब, यह संख्या के हिसाब से हैं आप 30 पर सिमट कर रह गए हैं। तय यह हुआ था कि सब के सब बोलेंगे आज आप सात बोल चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संख्या के हिसाब से इन्हें बता दें, समय के हिसाब से बता दें और इनकी रेशो के हिसाब से बता दें कि इनको कितना समय बोलने का मिलना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें। मैं विपक्ष के नेताओं को बताना चाहूंगा कि विपक्ष की तरफ से 126 मिनट बोले हैं।

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, अगर दो सदस्य उस साईड से बोले हों तो एक सदस्य इधर से भी बोलना चाहिए (विघ्न) 6 सदस्य उधर की साईड से बोल चुके हैं तो हमारी तरफ से भी एक सदस्य को आप बोलने के लिए समय दें। जब तक मैम्बर्ज बोलना चाहें आप उनको समय दें चाहे आपको हाउस का समय ही क्यों न बढ़ाना पड़े। (विघ्न) आप हाउस का समय बढ़ा दें।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया हाउस चल रहा है। जब से विधान सभा सैशन बैठा है तब से ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से भी और अपोजीशन की तरफ से भी पूरा कोआपरेशन मिल रहा है। हमारे विपक्ष के नेता ने जो बात कही थी हमने तो उस पर ही ऐग्री किया है। जैसे उन्होंने कहा था कि 89 मैम्बर्ज का जो हाउस है इसमें जो सदस्य अभी तक बोलने से रह गए हैं उन सभी को बोलने का पहले मौका मिलना चाहिए। उसमें चाहे वह ट्रैजरी बैंचिज के मैम्बर हों या विपक्ष के हों, चाहे इंडीपैंडैन्ट मैम्बर हों, चाहे किसी अन्य पार्टी से हों और चाहे वह आपकी पार्टी के हों। इनके कहने के अनुसार ही आप हाउस की कार्यवाही चला रहे हैं। सर, ऐसा पहली बार हो रहा है वरना तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी और मांगे राम गुप्ता जी उस समय मंत्रिमंडल में थे तो 7-3-96 को जो बजट पेश हुआ था वह बजट 35 मिनट में ही पास हो गया था। उस समय केवल एक ही मैम्बर बोला था।

श्री भजन लाल : आप उस समय भाग गए होंगे।

श्री सम्पत सिंह : चौधरी साहब, हम भागे नहीं थे बल्कि हमें बोलने ही नहीं दिया गया था। अगर हमें बोलने ही न दिया जाए और ये मार्शल ले आएं तो हम क्या कर सकते थे। इतनी जान तो हममें भी नहीं थी। एक मार्शल हो तो अलग बात है ये तो दो सौ मार्शल लाकर यहां पर खड़े कर देते थे। ऐसे में हमारे क्या वश की बात थी ?

श्री भजन लाल : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अब जो हाउस में मार्शल खड़े हैं क्या ये वी०आई०पी० हैं। इन्होंने यहां पर सारे पुलिस के जवान खड़े कर रखे हैं। इनमें से आधों को तो मैं जानता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ये तो सारे पास होल्डर्ज हैं।

श्री भजन लाल : पास तो इनको देने पड़ते हैं। मैं इनको जानता हूं इनमें आधे पुलिस वाले हैं। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री को बताना चाहूंगा कि ये तो सारे पास होल्डर्ज हैं। ये सारे अपने पास दिखा सकते हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस्तीफा दे सकता हूं अगर इनमें से आधे पुलिस वाले न हों तो। मैं जानता हूं कि ये पुलिस वाले हैं।

श्री सम्पत सिंह : पता नहीं आप क्या क्या करोगे। आप तो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इस्तीफा दूंगा लेकिन आपने दिया तो कभी नहीं। आपने यह भी कहा था कि मैं कीकर से लटककर मर जाऊंगा लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। (विघ्न) हमने तो आपकी पूरी सुरक्षा रखी हुई है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आपने तो सबको समय देने के लिए कहा था। (विघ्न) मंत्री जी हर बात टॉटिंग-वे में करते हैं। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अपोजीशन ने जैसा सुझाव दिया था उसी सुझाव की लाईन लीडर ऑफ दी हाउस ने की थी कि जो मैम्बर्ज अभी तक बोलने से रह गए हैं वे पहले बोलेंगे। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं कि दस या 15 मिनट हाउस का समय बढ़ाने की जरूरत है तो आप बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को आपने बुलवाना है तो यह आपने ही देखना है। सर, जिस ढंग से आप कार्यवाही चलाना चाहते हैं उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है हमारा आपको पूरा कोआपरेशन मिलेगा। जिस तरीके से आप हाउस चलाना चाहते हैं वैसा आप चलाएं। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, हम भी बोलना चाहते हैं आप हमें समय दें।

श्री अध्यक्ष : अगर आप बोलना चाहते हैं तो अनिल विज क्या करना चाहते हैं। वे भी तो बोलना चाहते हैं इसलिए आप उन्हें बोलने दें।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर डिसकशन के लिए तीन बजे तक का टाइम 15.00 बजे तय किया था इस टाईम को पांच बजे तक करिए तभी सारे सदस्य बजट पर बोल सकेंगे।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, टाईम पूरा मिल जाता है लेकिन इनके कहने से कल की एक सिटिंग गई।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बजट पर डिसकशन के लिए आधे घंटे का समय और दिया जाता है। अब श्री अनिल विज बोलेंगे।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर अपने विचार रखने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी सरकार के लिए जो सबसे कठिन काम होता है वह होता है अपने कार्यों की प्लान करना। नीतियां तो बहुत बन जाती हैं लेकिन उन नीतियों को लागू करने के लिए धन को मुहैया कराना सबसे कठिन काम होता है There is an old sayings 'Plan your work and work your plan' किसी भी काम को करने के लिए व किसी भी सरकार को चलाने के लिए यह दोनों पार्ट बहुत आवश्यक होते हैं Plan your work.

अगर वर्क को प्लान नहीं किया जाता तो उसका करना कठिन होता है। Plan your work and work your plan. जो योजना बनाई गई है उस योजना पर कार्य करना भी आवश्यक होता है जब यह पार्ट पूरी तरह से सजगता से, पूरी सूझबूझ से व सोच से किए जाते हैं, तब ही कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। मैं समझता हूं कि प्रौफेसर सम्पत सिंह जी ने जो बजट इस विधान सभा के प्रथम सत्र में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने काम को जो कि बहुत कठिन काम था उसे बखूबी निभाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जो शपथ ग्रहण की वह कुरुक्षेत्र की धरती पर की है।

[श्री अनिल विज]

हम सब जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है वह धर्मक्षेत्र है गीता का प्रथम श्लोक है—धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः—मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सनजे।। यानी जो पहला श्लोक है वह श्लोक ही कुरुक्षेत्र को अनादि काल से, सनातन काल से धर्मक्षेत्र मानता है। इस सरकार ने उस धर्मक्षेत्र पर जो शपथ ग्रहण की मैं इस बजट से ऐसा महसूस करता हूं कि उस धर्मक्षेत्र की भावना का पूरी तरह से समावेश इस बजट में किया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे-यानी जो हमारा धर्म है हमारे धर्म की जो सबसे मूल भावना है उसमें यह कहा गया है कि—सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारा जो धर्म है वह समाज के किसी वर्ग विशेष या जाति के लिए अलग से नहीं है बल्कि हमारे धर्म में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना-यानी समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो, सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। इस बजट की तमाम धाराओं को जब मैं देखता हूं तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस बजट में उस सर्वे भवन्तु सुखिना का पूरी तरह से पालन किया गया है। समाज के सभी वर्गों के लिए चाहे वह विकलांग हों, चाहे वह वृद्ध हों, चाहे वह विधवा हों सबके लिए इसमें कुछ न कुछ सोचा गया है। वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये की गई है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारे जो जबान सीमा पर शहीद होते हैं उनके बारे में सोचा गया है उनकी भी सहायता राशि बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दी गई है। इसमें कर्मचारियों के बारे में भी सोचा गया और कहा गया कि अन्य मांगों के साथ-साथ कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कर्मचारियों के वैल्फेयर की बात है, इस बजट में कर्मचारियों को 504 मकान बनाकर देने की बात कही गई है यह एक अच्छी बात है और इससे कर्मचारियों को रिहायशी मकानों की दिक्कत में राहत मिलेगी। यह एक अच्छा कदम है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कर्मचारियों का हैड क्वार्टर का क्षेत्रफल बढ़ाकर 60 किलोमीटर तक की सीमा तक कर दिया जाये तो इससे कर्मचारियों को मकानों की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पंजाब और दिल्ली में ऐसा किया जा रहा है। अगर यह सीमा बढ़ाई गई तो जो कर्मचारी चण्डीगढ़ में मकान नहीं बना सके वे सस्ते मकानों में अम्बाला और पटियाला में जाकर रह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटी को स्ट्रैंथन करने के लिए ज्यादा जोर दिया गया है जिसके लिए 2530 करोड़ रुपये की प्लान आउट ले को इस बजट में तैयार किया गया है। जिसमें से 1632 करोड़ रुपये का प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटी प्रोवाईड करने के लिए बजट में किया गया है। जहां तक बिजली की बात है। बिजली में सुधार के लिए इस बजट में 626 करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें बताया गया है कि जो पिछली सरकार के समय केन्द्रीय पूल से हमें 19 प्रतिशत बिजली मिलती थी उसको बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने में यह सरकार कामयाब रही है। इस बजट में फरीदाबाद में 143-143 मैगावाट के गैस पर आधारित दो संयत्र बनकर तैयार हो गये हैं और तीसरी इकाई के छः महीने के अन्दर-अन्दर बनकर तैयार होने का जिक्र किया गया है। हमें उम्मीद है कि इस इकाई के पूरा होने पर हमारी बिजली की समस्या काफी हद तक दूर हो जायेगी। बिजली के बारे में आगे यह बताया गया है कि संप्रेषण और जनरेशन के लिए इस बजट में काफी प्रावधान किया गया है। 220 के०वी०ए० की लाईन अब्दुलपुर से शाहबाद तक डाली गई है यह एक अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं अम्बाला कैन्ट के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। अम्बाला कैन्ट में बिजली की सप्लाई धूलकोट के 220 के०वी०ए० के सब-स्टेशन से की जाती है उसके अलावा अम्बाला कैन्ट में बिजली की सप्लाई का दूसरा वैकल्पिक साधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तेपला के 220 के०वी०ए० सब-स्टेशन को शीघ्र चालू करने का ध्यान सरकार को देना चाहिये। अगर तेपला का सब स्टेशन अम्बाला कैंट

से जोड़ दिया जाता है तो फिर अम्बाला कैन्ट में बिजली की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। अम्बाला कैंट में रेलवे का कार्यालय है, कन्टोनमैन्ट है, पी०एण्ड टी० का कार्यालय है, एम०ई०एस० वगैरा का इंस्टालेशन है। अगर किसी कारणवश धूलकोट के सब-स्टेशन में कोई खराबी हो जाती है तो अम्बाला कैन्ट को बिजली सप्लाई करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाढ़ राहत के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यह एक अच्छी बात है। क्योंकि हर साल हरियाणा प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप हो जाता है जिससे काफी बर्बादी हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमने अम्बाला कैंट और शहर के लिए तीन चरणों में होने वाली योजना तैयार की थी जिसके दो चरण पूरे हो चुके हैं अगर तीसरा चरण भी पूरा हो जाये तो अम्बाला कैंट बाढ़ मुक्त शहर घोषित किया जा सकता है इस तीसरे चरण पर 23-24 लाख रुपये का खर्चा हो जाने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, रोड्ज के लिए बजट में काफी प्रावधान किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें शहरों की सड़कें भी शामिल होंगी जिनको ठीक करने का काम किया जायेगा। क्योंकि आज सबसे अधिक कठिनाई शहरों की गलियों की है। बजट में कहा गया है कि गांवों की गलियों को पक्का कराया जाएगा, वह तो ठीक है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि शहरों की सड़कों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बजट में सड़कों की मरम्मत के लिए जितने पैसे का प्रावधान किया गया है उसमें से शहरों की सड़कों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। शहरों की गलियों की सड़कों को पक्का करवाने के काम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पीने के पानी की समस्या की ओर भी इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पीने के पानी के लिए सरकार ने अपने संकल्प को दोहराया है। यह सरकार प्रदेश के लोगों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाने का टारगैट अचीव करना चाहती है और इसके लिए बजट में अनेकों योजनाओं का जिक्र किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अम्बाला, रोहतक और भिवानी में इन योजनाओं को लागू करवाने की तरफ वह ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आजाद विधायक हूं मुझे पूरे हरियाणा का तो ज्ञान नहीं है लेकिन मैं अपने शहर अम्बाला छावनी के बारे में जानता हूं कि आज वहां पानी की इतनी किल्लत है कि आज सही मायने में मुझे भी नहाकर यहां आने में बहुत कठिनाई का अनुभव करना पड़ा है। इसलिए अम्बाला छावनी में पानी की इस समस्या को सरकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को कोई समय निर्धारित करना चाहिए ताकि निश्चित समय के अन्दर अम्बाला छावनी के लोगों को पानी पहुंचाया जा सके। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी सरकार ने अपने संकल्प को दोहराया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर की सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। सरकार ने अपने बजट में कई इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर्ज को सुधारने की भी बात की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अम्बाला में साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके लिए केन्द्र से 400 करोड़ रुपये की मंजूरी भी आ चुकी है। साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर बावल के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर के साथ ही बनना चाहिए था लेकिन किन्हीं कारणों से उसके बनने में देरी हो गई। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा देरी साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर बनने में हुई है उतना ही ज्यादा ध्यान इसकी ओर दिया जाए ताकि यह बाकि सैन्टर्ज के बराबर आ सके। अध्यक्ष महोदय, हैल्थ के बारे में की योजनाएं बनाई गई हैं। लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यूरोपियन कमीशन से 1000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त करके एक योजना तैयार की जा रही है। पूरे हिन्दुस्तान में 21 जिलों का चयन किया गया है जिसमें से तीन जिले हरियाणा के होंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये तीन जिले जी०टी० रोड के साथ लगते हुए लिए जाएं क्योंकि इस रोड पर एक्सीडैंटस ज्यादा होते हैं और मरीजों को पी०जी०आई० या रोहतक मैडीकल कालेज तक पहुंचाते-पहुंचाते काफी मरीजों की जिन्दगियां खो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं

[श्री अनिल विज]

आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अम्बाला के सरकारी अस्पताल की 75 बैडस की कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 बैडस किया जाए। शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने गवर्नर एड्रैस पर भाषण देते हुए बताया कि हम नई शिक्षा नीति भी बनाने जा रहे हैं। मैं इसका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा की जो नीति बनाएं उसके बारे में सभी से विचार विमर्श करें और सभी की राय लें और वे ले भी रहे हैं जिसका मुझे पता भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाएं और उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सब को शिक्षा के एक समान अवसर मिल सकें। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो एडिड स्कूल हैं वहां के शिक्षकों को 15-16-18 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षकों को पहली तारीख को ही तनख्वाह मिल जानी चाहिए नहीं तो वह पूरे मन से बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। (विघ्न)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, अध्यापक बच्चों को शिक्षा नहीं देते। वे तो सिर्फ अपनी तनख्वाह बनाने के लिए स्कूल में आते हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, भाई रामकिशन जी जो बात कह रहे हैं वह मैं तो नहीं कह सकता और न ही ऐसी मेरी संस्कृति है। यह बात तो रामकिशन जी ही कह सकते हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी चाहें तो स्कूलों में चैकिंग करवा लें, वहां पर अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के बजाय हुक्का पीते हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने व्यापारियों को भी सहूलियतें देने के लिए काफी कार्य किये हैं। सेल्सटैक्स के फार्म 14 व 15 को खत्म किया है और 50 लाख रुपये तक की सैल्फ-असैसमैंट की स्कीम लागू की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा जहां पर यह व्यवस्था लागू की गई है। मैं सरकार का इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नगरपालिकाओं की हालत सुधारने की भी व्यवस्था बजट में की है। शहरों का विकास करने के लिए पहले गवर्नर एड्रैस में भी और अब बजट में भी बात कही गई है। स्पीकर सर, सरकार ने चुंगी समाप्त करके बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसके लिए मैं दिल से सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। जो कर्मचारी सरप्लस थे उनको भी सरकार ने दूसरे विभागों में एडजैस्ट किया है। इसके लिए भी मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम गांवों को बेहतर बनाना चाहते हैं। वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज प्रोवाईड करना चाहते हैं। कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि हर घर के सामने गली पक्की हो, सीवरेज की एक लाईन हो, पीने का पानी हो, स्ट्रीट लाईट हो। ये सुविधाएं हर शहर में मुहैया कराने के लिए सरकार को कोई न कोई योजना जरूर बनानी चाहिए और कोशिश करें कि शहरों की सीवरेज व्यवस्था भी सुदृढ़ की जाये। खासतौर से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि शहरों में जो ग्रुप लैट्रिन बनी हुई हैं वे ओल्ड टाईप की हैं। उनको भी सुलभ शौचालय में प्राथमिकता के आधार पर बदलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप जल्दी वाईड-अप करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में वाईड अप कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हुडा की नई नीति बनाई है और कई बार कहा भी है कि दूसरे शहरों में भी हुडा के आवास की व्यवस्था करने के प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान अम्बाला छावनी की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि अम्बाला छावनी हरियाणा का सबसे सुव्यवस्थित और पुराना शहर है। लेकिन यह जानकर सभी को दुख होगा कि शायद अम्बाला छावनी ही हरियाणा में एक ऐसा शहर है जहां पर हुडा का कोई सैक्टर नहीं है। काफी समय पहले हुडा के लिए वहां पर जमीन एक्वायर की गई थी। लेकिन उसमें से कुछ जमीन हाई कोर्ट के आदेश से रद्द कर दी गई। अब वहां कहीं पर तो हुडा की एक्वायर की हुई भूमि है और बीच-बीच में कहीं पर लोगों की अपनी भूमि है, जो हुडा ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद छोड़ दी थी। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा अम्बाला छावनी में आवास की बहुत ज्यादा समस्या है। जहां पर सरकार दूसरे शहरों की तरफ ध्यान दे रही है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि अम्बाला छावनी को इसके लिए अछूता न रखा जाये और अम्बाला छावनी में भी हुडा का सैक्टर बनाया जाये। स्पीकर सर, पुलिस के लिए भी मौजूदा सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किये हैं। काफी समय के बाद किसी सरकार ने पुलिस के बारे में सोचा है और किया है कि अगर पुलिस कर्मचारी देश की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो हरियाणा सरकार उसे 5 लाख रुपये देगी। इसके लिए मैं सरकार को वधाई देता हूं। लेकिन मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने पुलिस के लिए हफ्ते में एक दिन का अवकाश देने की बात की है। इसलिए हमारी सरकार भी इस पर विचार करे और पुलिस कर्मियों को हफ्ते में एक दिन का अवकाश दे। स्पीकर सर, हम पुलिस कर्मियों से बहुत कठिन ड्यूटी लेते हैं, फिर हम उनसे अच्छे नतीजों की उम्मीद किसी हालत में नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इस बारे में मैं एक घटना बताता हूं। स्पीकर सर, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई। दो राजनीतिक कार्यकर्ता आपस में बहस कर रहे थे कि सरकार किसने बदली। एक कह रहा था कि सरकार इंदिरा गांधी ने बदली, दूसरा कह रहा था कि सरकार जय प्रकाश नारायण ने बदली। पास खड़ा एक पुलिस कर्मचारी यह बात सुनकर उनको कहने लगा कि सरकार न इंदिरा गांधी ने बदली और न जय प्रकाश नारायण ने बदली। फिर उन कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाले से पूछा कि भाई आप बतायें कि सरकार किसने बदली। वह पुलिस वाला कहने लगा कि सरकार पुलिस ने बदली। उन्होंने पूछा कि पुलिस ने सरकार कैसे बदली। इस पर पुलिस वाले ने कहा कि इंदिरा गांधी ने हमें कहा शक्ति बरतो, जहां एक डंडा मारने को कहा वहां हमने चार डंडे मारे और जनता परेशान हो गई और सरकार बदल दी। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार ने कहा कि पूरी तरह से ढिलाई करो और चोर को भी चोर जी कहकर बुलाओ। वह कहता है कि हमने किसी को भी पकड़ा नहीं और इतनी अफरा-तफरी मच गई कि लोगों ने सरकार फिर बदल दी। कहने का मतलब यह है कि पुलिस का सरकार में महत्वपूर्ण रोल होता है। सारा-सारा दिन वे वी०आई०पी० ड्यूटी देने के लिये भूखे-प्यासे सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस सरकार ने पुलिस की ओर ध्यान देने की कोशिश की है। इसलिये मैं इस सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सरकार पुलिस को भी एक साप्ताहिक छुट्टी दिये जाने की तरफ विशेष ध्यान देगी। एक रैस्ट तो होना ही चाहिए। यह तो मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री भी मानते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार पुलिस को सप्ताह में एक रैस्ट दिये जाने की बात पर अवश्य अमल करेगी। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने अपने एक संकल्प को दोहराया कि वे इस बात में विश्वास करते

[श्री अनिल विज]

हैं कि प्रशासन का दायरा छोटा होना चाहिए। यानी लोगों को नजदीक सुविधा मिलनी चाहिए। उसके लिये उन्होंने कुछ सब-डिवीजनस और तहसील वगैरा बनाने की बात भी कही। मैं इस बारे में आपके माध्यम से उनको एक सुझाव देना चाहूंगा। अगर वे चाहें तो उस पर गौर कर सकते हैं। आज तक हमने देखा है कि जितने भी सब-डिविजन या जिले बनाये गये वे किसी न किसी पोलिटिकल कम्पलशन को ध्यान में रखकर बनाये गये। मैं यह नहीं कहता कि मुमकिन है या नहीं लेकिन केवल मात्र मेरा सुझाव है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हर विधान सभा क्षेत्र को एक सब-डिवीजन बनाना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से प्रशासनिक सुविधा मिल सके। मैं तो यह कहता हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र में एस०डी०एम० और एम०एल०ए० का कार्यालय साथ-साथ होना चाहिए ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और सरकार मिलकर जनता के हित में काम कर सकें। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो सके तो हर लोकसभा क्षेत्र को जिले के बराबर बनाना चाहिए। ताकि कोई मांग न करनी पड़े और सारी प्रशासन व्यवस्था ठीक तथा दुरुस्त हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं अपने हल्के की कुछ मांगे रखना चाहता था लेकिन आपसे डरते हुए वह सब मांगे न रखकर सिर्फ एक बात कह रहा हूं और मैं समझता हूं कि उस एक बात में मेरे हल्के की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। गवर्नर एड्रैस में भी जिक्र आया और सी०एम० साहब ने भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी ने हर विधान सभा क्षेत्र में खुले दरबार आयोजित किये। ये दरबार हर विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये यानी 89 विधान सभा क्षेत्रों में तो लगाये गये लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में खुला दरबार आयोजित नहीं हो सका। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अम्बाला छावनी में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दरबार लगाया जाए और उसमें मैं अपने हल्के की मांगे रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाह रहा था जिसके लिये मेरे साथ बैठे कई साथी भी कह रहे हैं। जो एम०एल०ए० ग्रान्ट हिमाचल, पंजाब और दिल्ली में दी जा रही है वह ग्रान्ट हरियाणा में भी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी मुझे कह सकते हैं कि आपने पिछली सरकार के समय यह क्यों नहीं कहा। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि एम०एल०ए० ग्रान्ट दी जानी चाहिए जो कि आवश्यक है क्योंकि एम०एल०ए० के पास अपने हल्के में कोई काम कराने के लिये कुछ भी नहीं है उसको किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। आज एम०एल०ए० गली, मौहल्ले में जाते हुए डरता है कि अगर किसी ने उसको गली बनाने के लिये कह दिया तो वह उसका क्या उत्तर देगा। हमारे सांसदों को तो विकास के लिये दो करोड़ रुपया मिलता है। मेरे हल्के में दो सांसद का एरिया आता है और दोनों सांसदों को 4 करोड़ रुपया मिलता है। उनका मुकाबला करने के लिये राजनीतिक दृष्टि से भी हमारे पास कुछ नहीं है। वे जहां जाते हैं गली या सड़क बना देते हैं कोई राज्यसभा कोष से तो कोई एम०पी० कोष से बना देते हैं। लेकिन हम उनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आये हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिये मैं इस बारे में भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे जरूर इस पर विचार करें और कुछ न कुछ राशि विकास के लिये एम०एल०ए० ग्रान्ट के रूप में अवश्य दें। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपका और सदन के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि सबने मुझे सुना।

श्री अध्यक्ष : सदस्यगण, बजट पर तकरीबन सभी सदस्य बोल चुके हैं। जो मैम्बर्ज अभी तक बोल नहीं पाये हैं, वे बजट की जो डिमांडज आएंगी उन पर बोल सकते हैं। अब वित्त मंत्री जी अपना उत्तर देंगे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रूलिंग देने से पहले एक बार पुनर्विचार कर लें। हमारी आपसे विनती है कि हमारे जो मैम्बर्ज बजट पर बोल नहीं पाये हैं उन्हें 5-5 मिनट बोलने के लिए समय दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपने 5 मैम्बरों का नाम दिया था जबकि आपकी पार्टी के 7 मैम्बर बोल चुके हैं। एक तरह से आपकी पार्टी के एक तिहाई सदस्य बजट पर बोल चुके हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें 5-5 मिनट बोलने के लिए दे दें। आप हाउस की कार्यवाही का समय चाहे 2 घंटे बढ़ा लें, हमें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हाउस का समय आधे घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री भजन लाल : आप सिर्फ हमारे मैम्बर्ज को 5-5 मिनट बोलने के लिए समय दे दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हाउस की कार्यवाही का सिर्फ आधा घंटा बढ़ाया जा रहा है न कि इनके मैम्बर्ज को बोलने के लिए आध घंटा बढ़ाया गया है।

श्री धर्मबीर (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर ट्रेजरी साईड के मैम्बरों ने बोलते हुए कहा कि यह बहुत ही बढ़िया बजट है और कर रहित बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में मेरा कहना यह है कि यह बजट कर रहित न होकर काम रहित बजट है। इस बजट में कहीं यह नहीं दर्शाया गया कि कहां से पैसा आयेगा और उस आये हुए पैसे से कैसे कैसे काम होंगे। सरकार ने अपना जो बजट पेश किया है वह घाटे का बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर बजट को कर रहित दिखा दिया जाता है और बाद में जनता पर टैक्स लाद दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो टैक्स लगाने हों वे बजट के दौरान ही लगाने चाहिएं न कि बाद में। आज हमारे पास काम करने के लिए पैसा कहां से आयेगा उसके कोई साधन इस बजट में नहीं दर्शाये गए। सरकार जो काम करना चाहती है वह सारा कर्ज लेकर करना चाहेगी। यदि सरकार कर्ज के माध्यम से काम करेगी तो फिर ऐसा कब तक चलेगा। यदि किसी घर का मालिक काम न करे और अपनी आय के साधन न जुटाये और कर्ज लेकर ही काम करता रहे तो फिर वह कितने दिनों तक कर्ज लेकर अपने घर को चला पायेगा। बजट को देखने से पता चलता है कि हमारी मौजूदा सरकार की भी यही दशा लगती है। सरकार के अपनी आय के कोई साधन नहीं हैं बल्कि कर्ज लेकर काम चला रही है। सारे काम कर्ज लेकर ही सरकार करती रही तो यह हरियाणा के हित में नहीं होगा। बजट को पढ़ने से मालूम हुआ कि सरकार को अपनी आय से सिर्फ 1600 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इस राशि से हरियाणा का विकास कर पायेगी ? यदि सरकार ने अपनी आय के साधन नहीं बढ़ाये तो आने वाले 5-7 सालों में हमारे राज्य का बिहार से भी बुरा हाल हो जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी आय के साधन जुटाने के लिए कुछ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिएं ताकि सरकार के पास आय के साधन हो सकें। (शोर एवं विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, धमबीर जी से मेरा निवेदन है कि वे हमें सुझाव दें कि कौन से सख्त कदम उठायें जिनसे सरकार के पास आय के साधन अधिक हो सकें। (शोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, हम तो इनसे सुझाव मांग रहे हैं कि ये हमें बताएं कि हम कौन से कदम उठायें। (शोर एवं विघ्न)

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, कल जो बजट पेश किया गया था उसको मैंने पढ़ा है। इस साल जब चुनाव हुए तो नैशनल लोक दल के उम्मीदवार कहते थे कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बेरोजगार युवकों को नौकरियां देंगे लेकिन बजट पढ़ने से मालूम हुआ कि नौकरियों देने की बात इस बजट

[श्री धर्मबीर]

में कहीं पर भी नहीं कही गई है। अगर किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सकते तो इस बजट का क्या फायदा। अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वे मजबूर हो कर गलत रास्ते पर चलने लगेंगे। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए कोई स्कीम जरूर लाएं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि प्रदेश में जितनी भी इण्डस्ट्रीज लगें सरकार उनको आदेश दे कि आई०टी०आई० या पोलिटैक्निक संस्थानों से जो युवक टैक्नीकल ट्रेडों में एजुकेशन ले कर आते हैं केवल उन्हीं लोगों को वहां पर नौकरियां दी जाएं। इन फैक्टरियों में बाहर के लोगों को नौकरियां नहीं दी जानी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक और प्रार्थना करना चाहूंगा। विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्गों के लिए पैंशन राशि 100/- रुपये से बढ़ा कर 200/- रुपये की गई है। ये खुद भुक्तभोगी हैं इसलिए विकलांगों की जो परसैंटेज है उसको कुछ कम करें। विकलांग पैंशन के लिए केवल वही लोग पात्र हैं जो कि 70% विकलांग हैं अगर इस विकलांगता की परसैंटेज को कम करके 30% कर दिया जाए तो कुछ और ऐसे विकलांग लोगों को भी यह पैंशन मिल सकती है जो कि काम करने के योग्य नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनकी बाबत मैं कहना चाहूंगा। खासकर सड़कों, नहरों और पब्लिक हैल्थ के ऐसे काम जिन पर 90% काम हो चुका है और केवल 10% काम शेष बचा है इस 10% काम को पैसे की कमी को पूरा करके इस साल में जरूर पूरा करवाने का प्रावधान बजट में करें ताकि जो पुराना खर्च हो चुका है वह पैसा वेस्ट न जाए और वे स्कीमें लोगों के काम भी आ सकें। मैंने पहले भी ज़िक्र किया था खासकर जूई नहर तथा सिवानी नहर के दोनों तरफ सीपेज है इसलिए एम0आई०टी०सी० के माध्यम से वहां पर ट्यूबवैल्ज़ लगवाए जाएं और उस पानी को नहर में डाला जाए ताकि टेल पर भी पूरा पानी जाए और वहां पर जो सेम का इलाका है वह सेम वहां से खत्म हो सके। दूसरी तरफ जहां पर मोघे नहीं हैं वहां पर नए मोघे दिए जाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, जहां पर ऊंचे-ऊंचे टिब्बे हैं उन टिब्बों पर सिंचाई करने के लिए करीब दस साल पहले 100 स्प्रिंकलर सैट्स खरीदे थे। ये स्प्रिंकलर सैट्स जब से खरीदे हैं बेकार पड़े हैं और इनका यूज़ नहीं किया जा रहा है इस कारण जो पैसा इन सैट्स को खरीदने पर लगाया गया था वह वेस्ट गया और कोई काम इनसे नहीं लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि उन स्प्रिंकलर सैट्स को दोबारा से यूज़ किया जाए ताकि जो पैसा बेकार खर्च किया हुआ पड़ा है उसका कुछ फायदा प्रदेशवासियों को हो सके। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप ये सारी बातें पहले भी कह चुके हैं इसलिए इनको रिपीट न करें। (विघ्न) उन्हीं बातों को दोहराने का कोई लाभ नहीं है।

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, भिवानी शहर के साथ हमारी जो जूई कैनाल जाती है गवर्नमैंट कॉलेज के पास से जो गन्दा नाला गुजरता है उस नाले का पानी इस नहर में डाल दिया जाता है जिसकी वजह से सारे ऐरिया में सांस की बीमारी फैल गई है। इसलिए उस गन्दे पानी को नहर में डालने से रोका जाए (विघ्न) मुख्य मन्त्री जी ने भी एक बात कही है और इस बजट भाषण में भी यह बात है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए नये प्रकार के फूलों और फलों तथा सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं लेकिन उन चीजों के लिए जब बिजली कनैकशन्ज लेने जाते हैं तो उनसे कमर्शियल बिल लिया जाता है। इस सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से बिजली के कमर्शियल बिल्ज़ की जगह नॉर्मल बिल्ज़ ही चार्ज किए जाएं।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में पूरी डिटेल लिख कर सरकार को दे दें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री धर्मवीर : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं को-आप्रेटिव सिस्टम के बारे में भी कहना चाहूंगा। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात की तरह को-आप्रेटिव सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र, गुजरात और बीकानेर में यह सिस्टम है वैसा ही को-आपरेटिव सिस्टम यहां पर भी लागू किया जाना चाहिए और उस सिस्टम का प्रबन्ध लोगों के हाथों में देना चाहिए। इस बारे में हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री हुड्डा जी ने भी कहा है कि इसको एग्जामिन करवा कर इसी प्रकार का को-आप्रेटिव सिस्टम लागू किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी उसमें हो सके। आज बीकानेर में डेयरी सिस्टम को जा कर देखें। बीकानेर डेयरी वाले अपने आप फीड भी देते हैं, पशु खरीदने के लिए पैसा भी देते हैं जिसकी वजह से गरीब आदमी का गुजारा बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि को-आप्रेटिव सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि गरीब आदमियों का पालन पोषण ठीक ढंग से हो सके। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट की शामलात भूमि पर कुछ लोगों ने धीरे-धीरे कब्जा कर लिया है। पहले जब भी कोई गांव बसता था तो उसके आस पास कुछ एरिया खाली छोड़ा जाता था ताकि वहां पर लैंड लैस लोगों की भेड़-बकरियां चारा चर सकें। लेकिन अब उन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। आप इस समस्या के समाधान के बारे में कुछ करें। स्पीकर सर, एजुकेशन प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। यह सरकार एजुकेशन में किस प्रकार से बढ़ावा दे रही है उस पर हमें एतराज है। एजुकेशन बोर्ड में जनरल सैक्रेटरी और सैक्रेटरी कमिशनर रैंक के होने चाहिएं और आप वहां पर अनपढ़ लोगों को लगा रहे हैं। इस बारे में सरकार विचार करे। धन्यवाद।

शोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आज घटित एक अप्रिय घटना की तरफ दिलाना चाहूंगा। श्री जे०एस० राजू, पूर्व राज्य सभा के सदस्य थे उनका आज सुबह हृदय गति रुक जाने की वजह से देहांत हो गया है। वे 64 वर्ष के थे। आज सुबह उन्होंने छाती में दर्द होने की शिकायत की तो उनको हास्पीटल ले जाया गया। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चे छोड़ गए हैं। वे 1989 से 95 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे 1967 से 1980 तक तामिलनाडू असैम्बली के सदस्य चुने गए थे। आज वे इस संसार में नहीं रहे हैं मैं अपनी हार्दिक सांत्वना उनके परिवार के प्रति प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दिवंगत आत्मा के प्रति सदन के नेता ने अपने जो विचार प्रकट किए हैं मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूं। इस दिवंगत आत्मा के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मैं शोक संतप्त परिवार को सदन द्वारा प्रकट की गई संवेदना पहुंचा दूंगा। अब मैं दिवंगत आत्मा के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए सभी माननीय सदस्यों से खड़े होने का अनुरोध करता हूं।

(इस समय दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया।)

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राम किशन (बवानी खेड़ा, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यह जो बजट है इसमें सबसे ज्यादा बातें गन्ने के बारे में कही गई हैं। मेरे हल्के में न तो गन्ने की बिजाई होती है और न ही कोई गन्ने की पिराई की मिल है। हमारे यहां पर गन्ना बवानी खेड़ा में लग सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहीं पर गन्ने की पिराई के लिए मिल लगाई जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। उनको कोई काम धन्धा मिल सके। मेरे हल्के के लोगों को तो यह भी नहीं पता कि गन्ना पैदा कैसे होता है। (विघ्न) जो सरकार हमारे हक देगी वही हमारी सरकार है। इसी तरह से चावल की बात रही। चावल का भाव देने से मेरे हल्के को क्या फायदा हुआ क्योंकि चावल तो हमारे यहां होता ही नहीं है। (विघ्न) अगर चावल सिरसा में हो सकता है तो बवानीखेड़ा हल्के में भी हो सकता है। अगर हमारे यहां पर सरकार चावल पैदा नहीं कर सकती तो फिर वह हमारे यहां पर फैक्ट्री ही लगवा दे ताकि हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार मिल जाए और उनकी बेरोजगारी दूर हो जाए। इसके आलावा मैं नहरी पानी की मांग पहले भी करता रहा हूं और आज भी यह मांग उठा रहा हूं कि हमें दो हफ्ते नहरी पानी मिलना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि यह सरकार हमें पूरा पानी देगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शिक्षा की बात है। आजकल जो सरकारी स्कूल हैं उनमें टीचर्ज जाते ही नहीं हैं अगर जाते भी हैं तो एक हफ्ते में एक बार जाते हैं और हुक्का पीकर वापस आ जाते हैं उनकी कोई चैकिंग नहीं होती। मेरी सरकार से मांग है कि जिले लेवल पर कोई चैकिंग टीम भेजी जानी चाहिए जो सरकारी कर्मचारी सही काम नहीं करते उन्हें सस्पैन्ड किया जाए और उन्हें घर बैठा दिया जाए। हमारी सरकार कहती है कि हमने स्कूलों के लिए इतना पैसा दे दिया। लेकिन केवल पैसे से क्या होता है जब सामान ही नहीं होगा तो फिर स्कूलों में डोगर ही जाएंगे। इसी तरह से गांवों में ही हमारी बहन बेटियों के लिए कालेज होने चाहिएं क्योंकि एक गरीब मजदूर अपनी बेटी को गांव से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता। उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह शहर में उसको भेज सके। इसलिए उसकी लड़की शहर में पढ़ने से कतराएगी। वह दूसरी अमीर लड़कियों को देखकर शर्माएगी कि हम तो इतने गरीब घर के हैं और वे इतनी अमीर घर की हैं। इसलिए गांव में कालेज होने चाहिएं। अगर ऐसा होगा तो हमारे बच्चे पढ़ने के काबिल हो जाएंगे और बाद में उनको नौकरी भी मिल सकेगी। स्पीकर साहब, आज प्राईवेट स्कूल चलाने वाले फीस के रूप में बच्चों से बहुत पैसा मांगते हैं। अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो गरीबों के बच्चे तो बिना पढ़े ही रह जाएंगे। इसलिए जब तक उनको सही शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वे नहीं पढ़ सकेंगे। इसी तरह से अस्पतालों की बात है उनमें तो डाक्टर्ज केवल अपनी तनख्वाह ही पक्की करने जाते हैं। दवाई सरकार तो देती है लेकिन वे सारी दवाई प्राईवेट दुकानों में बेच देते हैं उनकी कोई चैकिंग ही नहीं होती। जिसके कारण गरीब जनता को कोई दवाई नहीं मिलती इसलिए इस बारे में जिला लेवल पर चैकिंग होनी चाहिए। हफ्ते में तीन दिन इनको जाकर चैक करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी पब्लिक को दवाई मिल सकेगी और उनका सही इलाज हो सकेगा। स्पीकर साहब, गरीब कन्याओं के लिए सरकार द्वारा जो 5100 रुपये दिए जा रहे हैं उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि उनको एक चीनी की बोरी और चालीस किलो वेसन भी दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो अब कोई आदमी हमारे घर आएगा तो उससे हमारी इज्जत बढ़ेगी। स्पीकर सर, अगर 36 बिरादरियों को एक करना है तो ऐसा होना ही चाहिए। पैसा पैसे की जगह काम करेगा और राशन राशन की जगह काम करेगा।

श्री अध्यक्ष : अब श्री रघुबीर सिंह कादयान जी बोलेंगे। आपको पांच मिनट का समय दिया जाता है।

श्री रघुबीर सिंह कादयान (बेरी) : धन्यवाद स्पीकर सर, मैं बजट के पक्ष में या विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं वित्त मंत्री जी खुद इस बात का फैसला करें। क्योंकि जिस दिन बजट हाउस की टेबल पर रखा गया। बजट पेश होने के बाद जब हम गए तो बड़ी-बड़ी किताबों का एक गटठा दिया गया और उसके बाद किताबों का एक और गठ्ठा दिया गया। कई माननीय सदस्यों से वह किताबें उठी नहीं। किसी के पेट में दर्द हो गया।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, टू दि प्वाइंट बोलिये।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, ये सारी बातें और ऐस्टीमेट्स बनाने में काफी दिन का समय लगा होगा। मेरे हिसाब से किसी सदस्य में इतनी महारत नहीं है कि वह इस सारे के सारे गटठे को पढ़ सकें और उसको समझ सकें, पढ़ तो सकता है लेकिन जैसा खुद वित्त मंत्री जी ने बताया कि पढ़ने लगूं तो हफ्ता लग जाएगा और आपने हमें इस पर चर्चा के लिए एक दिन का समय दिया है मेरा सुझाव है कि सभी सदस्यों के लिए बजट के ऊपर समझने का और जो उसकी टर्मिनोलौजी है, उसकी इकोनोमिक्स है उस पर कोई ट्रेनिंग या वर्कशॉप कंडक्ट की जानी चाहिए। कम से कम जैसे यह बजट एक हफ्ते में पढ़ा जा सकता है तो एक हफ्ते के बाद अगर सैशन हो तो इस पर रचनात्मक सुझाव आ सकते हैं। दूसरे, जहां तक मैं कहूं कि बजट पढ़ा या नजर दौड़ाई तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो सबसे पतली बुक बजट ऐट ए ग्लैंस है, दूसरा जो संपत सिंह जी ने बजट भाषण पढ़ा इस सारे मामले को जब हम मोटा-मोटा देखते हैं तो पाते हैं कि स्टेट के जितने रिसोर्सेज हैं वह सारे के सारे तनख्वाहों में यानी कि नॉन प्लॉन ऐक्सपैंडीचर में और लोन की अवायगी में बंट जाते हैं। नये असैट्स के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। लगभग पूरे-पूरे प्लान कर्जों से पूरे करने की नीयत साफ झलकती है। मैं आपके सामने एक सुझाव रखूं कि जैसे बजट ऐट ए ग्लांस में वित्तमंत्री जी ने 1999-2000 में रेवैन्यू रिसीटस में बजट ऐस्टीमेट दिया है 6901 करोड़ और रिवाइज ऐस्टीमेट 5979 करोड़ रुपये दिया है इसमें सीधा सीधा एक हजार करोड़ रुपये का डाउन फाल है। यह आपका रिकार्ड बता रहा है। इसमें जिस तरह से बजट ऐस्टीमेट दिया है 6755 करोड़ रुपये का, उसमें कितना ऐग्जेररेशन है क्या ये रिकरिंग रिसीट्स और रेवन्यू रिसीट उसकी पूरी कलैक्शन है। क्योंकि इसमें जो बताया गया है कि टैक्स रेवेन्यू 1999-2000 के बजट एस्टिमेट्स में 4406 करोड़ रुपये थे और इसके रिवाइज्ड एस्टिमेट में ये 4186 करोड़ रुपये है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री अपने भाषण में यह कहते हैं कि हमने टैक्स रिकवरी को बीस प्रतिशत बढ़ाया है। परन्तु इस रिवाइज्ड एस्टिमेट में तो 300 करोड़ रुपये टैक्स रेवैन्यू का डाउन किया गया है। इसके बारे में वित्त मंत्री जी बतायें। अध्यक्ष महोदय, तीसरा मैं रेवैन्यू एक्सपैंडीचर के बारे में कहना चाहता हूं। रेवेन्यू एक्सपैंडीचर का सारा का सारा नॉन प्रोडैक्शन 8097 करोड़ रुपया है जोकि टोटल एक्सपैंडीचर का 85 प्रतिशत है। आपके बजट और बजट एट ए ग्लेंस में फिगर बदले हुए हैं। वित्त मंत्री जी बतायें कि आपका बजट ठीक है या बजट एट ए ग्लेंस ठीक है ? हैल्थ, ऐजुकेशन, रूरल डवैल्पमेंट, एग्रीकल्चर आदि पर 11.2 प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें से 2.02 प्रतिशत कृषि पर खर्च किया जाना है जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हितैषी बनते हैं। मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि बजट के हिसाब से टोटल पैसे का 100 में से 2 प्रतिशत कृषि पर खर्च किया जाना है। रूरल रिसोर्सिज पर 16 प्रतिशत खर्च करना आपने इस बजट में दिखाया

[श्री रघुबीर सिंह कादयान]

है। 16 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत तो सैलरी एस्टिबिलिसमेंट पर खर्च हो जाता है, उसके बाद हैल्थ विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है और रूरल डिवैल्पमैंट विभाग भी है। इसके साथ साथ बजट के पेज नम्बर 6 पर दिखाया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आपका एक मिनट और बाकी है।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, बजट के पेज नम्बर 6 पर दिखाया गया है कि 64.5 फीसदी बजट बिजली पर, इरीगेशन पर, ट्रांसपोर्ट पर, रोड्ज पर खर्च होगा। जिसमें से बिजली पर 9.44 प्रतिशत, इरीगेशन पर 7.79 प्रतिशत, ट्रांसपोर्ट पर 4.14 प्रतिशत, रोड्ज पर 5.82 प्रतिशत और टोटल 27.19 प्रतिशत रूपीज गोज में दिखाया गया है। वित्तमंत्री जी इसमें से कहां पर कटौती कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 64.5 फीसदी बजट खर्च करने को कहा है और रूपीज गोज में 27.19 है।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप दस मिनट बोल चुके हैं अब आप बैठ जाइये।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि हमारा 34.37 प्रतिशत बजट ब्याज के भुगतान और ऋण की अदायगी पर खर्च हो रहा है। आज प्रदेश किस दिशा में जा रहा है और प्रदेश के लोगों के हितों को किस दिशा में यह सरकार ले जा रही है। क्योंकि उन पर तो ऋण का भार डाला जा रहा है। इसलिए मैं इस सरकार को आने वाले भविष्य के बारे में चेतावनी के रूप में बताना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कुछ आवश्यक कदम उठाये।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप दस मिनट बोल चुके हैं इसलिए आप अब बैठ जाइये।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कंक्लूड कर दूंगा। आज के दैनिक ट्रिब्यून में यह दिया हुआ है regarding the abolition of vacant posts, ban on fresh recruitment * * * *

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, कादयान जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, डा० साहब जो कुछ कह रहे हैं वह तस्वीर का दूसरा रूप है। लोन रिपेमैंट 17.03 प्रतिशत है और इन्ट्रस्ट पेमैंट 13.5 परसैन्ट है। who is responsible for re-payment. ये रिपेमैंट और सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी हम लोग नहीं उठाएंगे तो कैसे सरकार चलेगी। शिक्षा के लिए कुल बजट का 11.92 परसैंट रखा गया है और इतनी राशि पहली बार बजट में एजुकेशन के लिए रखी गई है जबकि सैन्टर गवर्नमैंट में 6 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षा के लिए बजट में नहीं रखा गया है। शिक्षा के लिए इस बार हरियाणा का बजट सबसे ज्यादा है। इस बात के लिए सबको सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। (शोर) जो मैं कह रहा हूं वह बजट एट ग्लांस में दिया हुआ है। (शोर)

श्री अजय सिंह (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सम्पत सिंह जी ने 14 मार्च को जो बजट पेश किया है, मेरे हिसाब से यह बजट दिशाहीन है और किसी प्रकार से भी विकासोन्मुख नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि इसमें जो 2530 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना के आकार का जिक्र किया गया है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें तकरीबन 295 करोड़ रुपये का घाटा है जो कि पिछले साल का था। इसी प्रकार सरकार ने अपने संसाधन जुटाने के लिए आटोमोबाइल, लग्जरी आइटम पर सेल्ज टैक्स बढ़ाए हैं और यूनिफार्म टैक्स भी बढ़ाए गए हैं। मैं

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

समझता हूं कि ये टैक्स लगाने से सरकार को 150 करोड़ रुपये की राहत होगी। लेकिन सरकार ने अपने संसाधन जुटाने के बारे में किसी भी कार्यवाही का जिक्र नहीं किया है। इसके साथ-साथ मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि हुडको, मार्किटिंग बोर्ड, हैफेड और जितने भी बड़े-बड़े बोर्ड और कारपोरेशन्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को सरकार अपनी प्लान आउट ले में शामिल करें। उसी प्रकार से सरकार एक रिसोर्स मोब्लाइजेशन इकनोमिक कमेटी गठित करे इस कमेटी के मैम्बर सरकारी अफसर और खास तौर से पब्लिक के रिप्रैजेन्टेटिव हों जो इस बारे में अपने सुझाव दे सकें। इस सरकार ने कुछ टैक्सों को अबोलिश करने का भी काम किया है खासतौर से रूरलस डिवैल्पमैंट सैस 2 परसैंट अबोलिश किया गया है, मुझे इस बात को लेकर आपत्ति है क्योंकि उसका सीधा असर किसानों के ऊपर पड़ता है। एच०आर०डी०एफ० जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें वगैरा बनती हैं, को भी बहुत भारी घाटा पहुंचा है। उसी प्रकार समय-समय पर सरकार कुछ सेल्ज टैक्सों को कम करती है, कुछ को ज्यादा करती है। उसके बारे में सरकार एक व्हाइट पेपर इशू करे। जिसके द्वारा यह बताया जाए कि जब से हरियाणा बना है तब से किस चीज पर कितना टैक्स कम किया गया है और कितना बढ़ाया गया है और ये क्यों कम या ज्यादा किए गए हैं। क्योंकि ऐसे काम कई बार विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि हरियाणा में कई ऐसी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं जिनके हैड आफिस दिल्ली में बने हुए हैं, रसीदें भी उनकी दिल्ली में कटती हैं और जो टैक्स हरियाणा में दिया जाना चाहिए वह दिल्ली में दिया जाता है। इसलिए इसके बारे में बाकायदा एक कानून बनाया जाए कि अगर कोई फैक्ट्री हरियाणा में चल रही है तो उसकी जितनी भी कन्साइनमैंट हैं वह हरियाणा में ही होनी 16.00 बजे चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए ताज्जुब होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर इनटेक की कपेसिटी 1998-99 में 15792 थी। जो अब कम होकर 14997 हो गई है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा सरकार टैक्नीकल एजूकेशन के बारे में सीरियस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश द्वारा 1996 में डैबिट के तौर पर 6212 करोड़ रुपया लिया गया था। जो कि 2001 में 15216 करोड़ रुपये हो जायेगा। यानि सरकार का ले-आउट 2530 करोड़ रुपये है और 2001 में सरकार के ऊपर 15216 करोड़ रुपये लोन के डैबिट के रूप में हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में रि-पैमैंट 1932 करोड़ रुपये की होगी, जो इकनोमिक सर्वे आफ इण्डिया में दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषतौर से पावर सैक्टर के बारे में कहना चाहूंगा जिसके लिए सरकार ने 626.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बारे में मुझे यह आपत्ति है कि सरकार यह बताये कि इस पैसे की इंवैस्टमैंट के आपके क्या प्रोग्राम हैं ? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रैथन करने के लिए एस्टीमेटिड कोस्ट 7 हजार करोड़ रुपये होगी। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट में जो ऐड वर्ल्ड बैंक से मिली थी उसके बारे में जिक्र नहीं किया कि कितने पैसे लोन के रूप में वहां से मिले थे और कितने पैसे और मिलने वाले हैं तथा वर्ल्ड बैंक की इस बारे क्या-क्या शर्तें हैं ? अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक ने सरकार को इस बारे धमकी दी है कि उनके लीगल एग्रीमैंट की शर्तों को 3-4 कारपोरेशंज पूरी करने में असफल रही हैं। इस ओर सरकार अपना ध्यान दे क्योंकि प्रदेश की जनता इस बात के लिए बहुत चिंतित है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जो पावर रिफोर्मज चौधरी बंसी लाल जी के समय में चालू किये गये थे उनके बारे में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि सरकार टोटल कंवर्शन आफ लो वोलटेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में वैल्यू बेस सर्विसिज के बारे में, टैरिफ के रैशनलाईज करने के बारे में भी सरकार क्या कदम उठा रही है ? अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार पावर प्रोडैक्शन की क्वांटिटी चाहे कितनी भी बढ़ा ले लेकिन जब तक 11 के०वी० की लाईनों को ठीक नहीं किया जायेगा तब तक बात नहीं बनेगी।

[श्री अजय सिंह]

अध्यक्ष महोदय, पावर के बारे में इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें ट्रांसपियरैंसी होनी चाहिए। चाहे टैरिफ का मामला हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से लोन का मामला हो, पावर क्षेत्र में पूरी तरह से ट्रांसपियरैंसी होनी चाहिए। मैंने बजट पढ़ा है, इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि पावर के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप 2 मिनट में वाईंड अप करें।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में वाईंड अप कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और इस क्षेत्र के लिए बजट में 111 करोड़ रुपये दर्शाए हैं। शुगर केन का प्रोडैक्शन 1996-97 में 9.2 लाख टन था जो घटकर 1997-98 में 6.8 लाख टन हो गया। मेरे कहने का मकसद यह है कि शुगर केन के अंदर भी डिकलाईन हो रहा है और इसी तरह से फूडग्रेंज के अंदर भी डिकलाईन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 1998-99 में फूडग्रेंज का प्रोडैक्शन 121.23 लाख टन था जो 1999-2000 में घटकर 116.15 लाख टन हो गया। अध्यक्ष महोदय, केवल आयल सीड में थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, वह भी इसलिए कि हमारे यहां पर सूरजमुखी की खेती अच्छी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, इरीगेशन के बारे में आर०आई०डी०एफ० और नाबार्ड के तहत रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों में जो फल्ड प्रौटेक्शन की 36 स्कीमें हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि उनको रिस्टोरिंग कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करने के लिये और लिफ्ट सिस्टम द्वारा न्यू माइनर्स बनाने के लिये, नई एक्सटैंशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए जो टोटल स्कीम थी वह 508 थीं जिसमें से केवल 58 कम्पलीट की गई हैं। तकरीबन 90 स्कीमें ऐसी हैं जिनको टच भी नहीं किया है। पिछली सरकारों ने जान-बूझ कर उन स्कीमों को टच नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, अब आप बैठ जाइए। आपका समय पूरा हो चुका है। जो सदस्य बोलने के लिए रह गये हैं अब ये डिमाण्ड्स पर बोल सकते हैं। काफी समय हो चुका है। साढ़े सात घण्टे का समय दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप बैठिए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पांच मैम्बरों ने बोलना था और चार मैम्बर बोल चुके हैं। एक मैम्बर बाकी है उसको भी पांच मिनट का समय दे दें। उसमें क्या फर्क पड़ता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। तीन बजे तक का समय था और दो बार उसके बाद समय बढ़ाया जा चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, अभी आप बैठिए। आप किसी दूसरे सब्जैक्ट पर बाद में बोल लेना। (शोर)

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी तो सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आपकी भी अभी तक तसल्ली नहीं हुई। आपने 5 मिनट बोलना था और 10 मिनट से ज्यादा आप बोल चुके हैं। आप बैठिए। (शोर)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता के कहने पर आपने आधा घण्टा समय बढ़ाया और वह सारा समय इनको ही मिला। सरकारी पक्ष की तरफ से इस समय में कोई भी सदस्य नहीं बोला है।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कसान साहब, आप बैठिए। आप लोग भाषण बाजी बाद में कर लेना। यहां पर बजट पर बहस हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। आप लोगों को डिमाण्ड औन ग्रान्ट्स पर भी बोलने का मौका मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर को बोलने दें। पांच मिनट में क्या फर्क पड़ता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपके कहने पर ही हाउस का समय आधा घण्टा बढ़ाया गया था और इस समय सवा चार बजने जा रहे हैं जबकि 3.00 बजे तक का समय था। (शोर) आगे एप्रोप्रिएशन बिल आयेंगे, डिमाण्ड्ज आएंगी उन पर बोल लेना। उन पर आप किस को बुलवायेंगे। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। आपके बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। (शोर) आपने आधे घण्टे का समय बढ़ाने के लिये कहा था और आपके कहने से ही आधा घण्टा बढ़ा दिया था।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर को पांच मिन्ट बोलने दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप तो बड़े सुलझे हुए और अच्छे पार्लियामैन्टेरियन हैं। आपको इस तरह से बार-बार खड़े नहीं होना चाहिए। आप बैठिए। (शोर)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने विपक्ष के नेता के कहने पर आधा घण्टा समय बढ़ाया। हमारी तरफ से इस आधे घण्टे में कोई भी नहीं बोला। सारा का सारा समय आपने इनको दिया। (शोर)

श्री अध्यक्ष : इन-प्रोपोशिट सबसे ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी को दिया गया है और ज्यादातर मैम्बर दो-दो बार बोल चुके हैं। (शोर)

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : स्पीकर साहब, * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, जो बोल रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य को बोलने दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपके 9-10 सदस्य बोल चुके हैं। आप बैठिए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से लीडर आफ दि हाउस से निवेदन है कि हमारे जो एक-दो मैम्बर बोलने से रह गए हैं उन्हें आप 5-5 मिनट बोलने का समय दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : चौधरी साहब, अब से पहले जितनी बार भी आपने समय बढ़ाने के लिए स्पीकर साहब को कहा, स्पीकर साहब ने समय बढ़ाया। (शोर एवं विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, हमारे मैम्बर 7-8 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर लेंगे। आप हाउस का समय और बढ़ा लें।

श्री सम्पत सिंह : चौधरी साहब, जितना टाईम आप लोगों को दिया है आप हरियाणा विधान सभा का रिकार्ड उठा कर देख लें, इतना समय कभी भी विपक्ष को नहीं दिया गया। (शोर एवं विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे दो सदस्य रह गए हैं उनको आप बोलने के लिए समय दे दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप लोगों को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। जो मैंबर्ज रह गए हैं वे बाद में बोल सकते हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैम्बर का हाउस में बोलने का अधिकार है। आप इन्हें बोलने की इजाजत दे दें। (शोर एवं विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) ; चौधरी भजन लाल जी, पहले हम भी और आप भी हाउस के सदस्य रह चुके हैं। आज आप अधिकार की बात करते हैं। आपके समय में जब हम कहते थे कि हमें समय दे दिया जाये तो उस वक्त मैम्बर के अधिकार कहां पर चले गए थे ? जब मैं विपक्ष में था तो उस वक्त विपक्ष का नेता होने के नाते मुझे 30 मिनट से ज्यादा बोलने का समय कभी नहीं दिया गया। आप अपने शासनकाल का टाईम याद करो। अब बजट पर आपके 21 सदस्यों में से 10 सदस्य बोल चुके हैं। गवर्नर एड्रैस पर भी आपके तकरीबन सभी सदस्य बोले हैं। स्पीकर साहब ने बड़ी उदारता के साथ आप सभी को बोलने का समय दिया। आपने उनका धन्यवाद करने की बजाये कह दिया कि स्पीकर साहब बोलने के लिए समय नहीं दे रहे, यह गलत बात है। आप वाक आऊट करना चाहते हैं तो बेशक करें। अब और समय नहीं बढ़ेगा क्योंकि स्पीकर साहब ने वित्त मंत्री जी को बोलने के लिए समय दे दिया है। अब आप लोग ध्यान से इनका उत्तर सुनें।

श्री भजन लाल : हमने तो अपने समय में आपको बोलने से कभी रोका नहीं। आप ही हमारी बात सुनने की बजाये वाक आऊट करके चले जाते थे। (शोर एवं विघ्न) यह कहीं होता है कि एक ही दिन में बजट पर बहस होकर उसे पास कर दिया जाये। आपसे निवेदन यही है कि जो हमारे मैम्बर रह गए हैं उन्हें आप डिमांड पर बोलने का आश्वासन दे दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिये।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 5-5 मिनट अगर सभी को बोलने के लिए समय दे दिया जाये तो उससे क्या फर्क पड़ता है। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोगों को सदन से भागने का बहाना चाहिए। ये इस तरह का माहौल पैदा करके सदन से भागना चाहते हैं। आज बजट पर बहस हुई है और आज ही बजट पास किया जाना है। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात नहीं है, कुछ लोग बोलना चाहते हैं उनको बोलने का समय दिया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य चुनाव जीतकर सदन में आये हैं कोई किसी के रहमोकरम से सदस्य बनकर नहीं आया है। इसलिए जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने का समय मिलना चाहिए। (विघ्न) अगर आप चाहें तो आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन आपको हमें बोलने के लिए समय तो देना ही चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, अगर आप चाहें तो खुद सदन से बाहर जा सकते हैं। मैं आपको हाउस से बाहर नहीं निकालूंगा। यदि मैं आपको हाउस से बाहर निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। (शोर एवं विघ्न)

वाक-आउट्स

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमारे साथियों को बोलने का समय देना नहीं चाहते तो हम वाक-आउट करके जाते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अभी डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है इसलिए चौधरी भजन लाल जी आप वाक आऊट करके न जायें।

श्री भजन लाल : जब बोलने के लिए समय नहीं दे रहे तो हम वाक आऊट करके जा रहे हैं।

(इस समय इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाकआउट करके चले गए।)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए। ये मेरी परमिशन के बगैर जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। दलाल साहब, आपको बोलने के लिए 35 मिनट का समय दिया गया था। आप तो केवल अपनी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। पार्टियों के हिसाब से आपको केवल सात मिनट का समय बनता था लेकिन फिर भी आपको बोलने के लिए 35 मिनट का समय दिया गया है। आपके अलावा और भी बहुत से सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। अब वित्त मंत्री जी बजट पर हुई बहस का जवाब देंगे। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो मैं भी वाक आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल भी सदन से बाहर चले गये।)

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मन्त्री (श्री सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, फाईनेंस मिनिस्टर के तौर पर बोलने से पहले मैं एज़ पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर बोलना चाहता हूं। हम लोग विपक्ष के सदस्यों द्वारा जो बातें कहीं गई थे सभी सुनते रहे हैं। आज ही नहीं जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उस दिन से ले कर अब तक हमने ओपोजीशन की हर बात को सुना। उनको बोलने के लिए आपने मैक्सीमम टाईम दिया है। आज तक कभी भी ओपोज़ीशन पार्टी के लोगों को बोलने के लिए इतना टाईम नहीं मिला विशेष कर सारे ही हाउस के मैम्बर्ज़ ने कंट्रीब्यूट किया। इतनी बड़ी संख्या में इन्डिविजुअल मैम्बर्ज आज तक कभी नहीं बोले। जो सारी बातें उन्होंने कहनी थी वे तो उन्होंने कह ली अब वे केवलमात्र इस बात से यहां से उठ कर चले

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री सम्पत सिंह]

गए हैं कि वे हाउस को फेस नहीं करना चाहते। चुनाव में वे पब्लिक को फेस नहीं कर पाए और अब हाउस के अन्दर भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने खुद जो जगलरी ढंग से आंकड़े पेश करने की बात की थी उन बातों का अब जवाब दिया जाना था। उन लोगों में हिम्मत होनी चाहिए थी कि उन बातों का जवाब सुनते। उनके द्वारा अनपार्लियामैंटरी तरीके से वाक-आउट करना ठीक नहीं है अगर वाक-आउट का कोई समय होता तो कुछ और बात थी। विपक्ष के नेता ने जितना टाईम मांगा आप ने बार-बार दिया लेकिन उसके बावजूद भी केवल मात्र एक तमाशा करने के लिए उन्होंने वाक-आउट किया है। जब बोलने को कुछ रह नहीं गया और कुछ सुनने की हिम्मत उनमें थी नहीं केवलमात्र अखबारी खबर बनाने के लिए उन्होंने यह वाक-आउट किया है। उनका यह वाक-आउट वास्तव में वाजिब नहीं है। स्पीकर सर, आपकी इजाजत से अब मैं रिप्लाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय सदन में कल बजट एस्टीमेट 2000-2001 रखा गया था। आज सुबह से उस पर बहस चल रही थी बहुत से सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए और कुछ आलोचनाएं भी की हैं। सुझाव और आलोचनाओं को मैं बड़े सब्र से सुन रहा था और उनको नोट कर रहा था। जो-जो भी हाउस में हैल्दी डिस्कशन हुई हैं मैंने उनको नोट किया है। सर, समूचे विपक्ष को चाहिए तो यह था कि इस बजट का वैल्कम करते। इस शताब्दी का यह पहला बजट पेश हुआ है। इतने वित्तीय बोझ के बावजूद इस सरकार ने अच्छा काम किया है यह सब आप जानते हैं। एक तरफ चुंगी माफ हुई, उससे कितना बोझ पड़ा है। यह सबको पता है। वृद्धावस्था पैंशन, हैंडिकैप्ड पैंशन, शहीदों के आश्रितों की पैंशन वगैरह से स्टेट एक्सचैकर पर 3 गुणा बर्डन पड़ा है जिसको बढ़ाकर 320 करोड़ रुपए करना पड़ा है। इसी तरह से जो शूगरकेन के दाम बढ़ाये हैं वह रिकार्ड तोड़ दाम हैं। आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतने दाम नहीं बढ़ाये जो कि हरियाणा सरकार ने बढ़ाये हैं। आज ही हरियाणा में शूगरकेन के दाम 110 रुपए प्रति क्विंटल हैं। बहुत से आईटमों पर मार्किट फीस दो से एक प्रतिशत की है। कन्यादान की स्कीम शुरू की है। टैक्सों पर भी कई स्कीमें बनी हैं जिससे लोगों को राहत मिली है। इन बातों को ये सुनते तो कुछ बात बनती। लेकिन ये गलत तरीके से अपनी ड्यूटी करके यहां से बाहर चले गए। बहुत से सदस्यों ने यहां पर बहुत सी बातें कहीं। मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। यहां पर सदस्यों ने जो प्रीवैंसिज रखी अपनी मांगें रखी मैंने वह सब नोट कर ली हैं। मैं उस बारे में कहना चाहूंगा कि हम उनको विभिन्न विभागों को भेज देंगे। आप सब को मालूम है कि उन पर एस्टीमेट्स बनते हैं उन पर सरकार सीरियसली सोच-समझ कर काम करवाएगी। जैसा पहले की सरकारों के वक्त में भेदभाव किया जाता था हम वैसा नहीं करेंगे। हमारे लिए 90 के 90 विधान सभा के हल्के बराबर हैं। जैसा कि भागी राम जी ने बताया कि कुछ हल्कों को जानबूझ कर इग्नौर किया गया था उनको हम प्राथमिकता देंगे और वहां के काम करवाएंगे लेकिन बाकी हल्कों में भी हम काम करवाएंगे किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। विपक्ष के सदस्यों ने अपने भाषण में बोलते हुए बताया कि हमने घाटे का बजट पेश किया है। सर, मांगे राम जी और हुड्डा जी यहां से उठकर चले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह रिवायत रही है कि अगर सदन में किसी ने गलत फिगर दी है, तो उसके खिलाफ प्रिवलेज मोशन आता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ लीडर ऑफ दि अपोजिशन होते हुए और मेरे खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन आया था। अगर हम चाहते तो जो मांगे राम गुप्ता जी यहां पर बोल रहे थे और इसी तरीके से कल रघुबीर सिंह जी भी बोलकर चले गए थे। सर, अगर इन लोगों की बात की जाए तो जो फिगर्ज उन्होंने दी थी उसके आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। मैं इन बातों पर बाद में आऊंगा। पहले मैं बजट घाटे के बारे में बताना चाहता हूं। सर, हमें तो विरासत में यह घाटा मिला था। 24 जुलाई, 1999 को जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला

जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी थी उस वक्त घाटा 150 करोड़ रुपये का था लेकिन उसके बाद यह घाटा 31 मार्च तक बढ़कर 196.77 करोड हो गया। स्पीकर सर, मैक्सिमम घाटा तो उनके वक्त का ही है। हमने तो रिकवरी बढ़ायी ही है। बहुत मुस्तैदी के साथ इस सरकार ने काम किया है, इनफोर्समैन्ट बड़ी ईमानदारी से की है। स्पीकर सर, जब हमने सत्ता संभाली थी उस वक्त एक्साईज तो माईनस में आ गया था और सेल्ज टैक्स की इंक्रीज एक प्वायंट कुछ की थी जो अब बढ़कर 13.5 हो गयी हैं। स्पीकर सर, इस तरह के एफर्टस आपकी सरकार ने किए हैं और तभी जाकर के यह रिकवरी बढ़ी है। जब इन चीजों की रिकवरी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि घाटे की पूर्ति भी होगी। भांगे राम गुप्ता जी कह रहे थे कि उन्होंने अपने समय में प्लस में बजट पेश किया था। अब वे यहां पर हैं नहीं वरना उनके खिलाफ प्रिवलेज का मोशन बनता है। स्पीकर सर, उनके बजट के बारे में भी मैं यहां पर बताना चाहूंगा। 1991-92 के साल में 31 मार्च को जो ओपनिंग बैलेंस था वह माईनस 62.13 करोड़ रुपये था जबकि वे कह रहे थे कि हमने प्लस का बजट पेश किया था। स्पीकर सर, इसी तरह से 1993 में 31 मार्च को जो ओपनिंग बैलेंस था वह भी माईनस .14 करोड़ रुपये का था। इसी प्रकार से 1994 में 31 मार्च को जो ओपेनिंग बैलेंस था वह माईनस 57.59 लाख का था और 1995 में 31 मार्च तक ओपनिंग बैलेंस माईनस 91.88 करोड़ रुपये का था जबकि गुप्ता जी कह रहे थे कि उन्होंने प्लस में बजट पेश किया था। वे अब चले गए वरना मैं उनको बताता स्पीकर सर, 500 प्लस 91.88 यानी 592 करोड़ रुपये कहां चले गए क्या वे अपनी जेब में लेकर चले गए ? क्या वे अपने साथ लेकर चले गए ? स्पीकर सर, इस तरह की गलत बयानबजी उन्होंने की थी लेकिन अब वे इन बातों को छोड़कर चले गए क्योंकि सही सुनना उनको बर्दाश्त नहीं था। स्पीकर सर, हमने घाटा पूर्ति के लिए बजट में प्रोविजन रखा है कि कैसे हम इसे पूरा करेंगे। इसी तरह से यूनिफार्म सेल्ज टैक्स की बात आयी। सर, यह अब हरियाणा प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है हालांकि दूसरे प्रदेशों ने चुनावों से पहले ही यह लागू कर दिया था। स्पीकर सर, भारत सरकार के वित्तम मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलायी थी उसमें बड़ी सद्भावना के साथ यह ऐग्रीमैन्ट हुआ था कि सभी राज्य यूनिफार्म सेल्ज टैक्स लागू करेंगे। सर, यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले हम कहते थे कि हमारा बिजनैस माइग्रेट होकर दिल्ली चला गया, पंजाब वाले कहते थे कि उनका बिजनैस राजस्थान या हरियाणा चला गया और यू०पी० वाले कहते थे कि उनका बिजनैस दिल्ली चला गया यानी सभी सटेट्स अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बात कहते थे उनकी अलग अलग आब्जेक्शंज थीं। लेकिन बाद में बड़े अच्छे तरीके से यूनिफार्म सेल्ज टैक्स की पोलिसी बनी। उस समय हम इसको लागू नहीं कर सकते थे क्योंकि चुनाव आ गये थे और अगर हम ऐसा करते तो चुनाव आचार संहिता आड़े आ जाती। लेकिन चुनावों के बाद हमने यूनिफार्म सेल्ज टैक्स लागू किया है। अब इससे 75 करोड़ रुपये की आमदनी होगी और इस तरह से भी घाटा पूरा होगा। इसी प्रकार से जो दसवां सैंट्रल फाईनैंशियल कमीशन था उसने शेयर ऑफ सैंट्रल टेक्सिज की 26 परसैंट के बजाए 29 परसैंट फालतू इंक्रीज मान ली थी। उन्होंने सैंट्रल टैक्सिज में स्टेट शेयर 26 परसैंट के बजाए 29 परसैंट मान लिया था लेकिन यह एरियर भी अभी तक आए नहीं हैं। स्पीकर सर, हमारा अनुमान है कि यह एरियर करीब 155 करोड़ रुपये के आएंगे। अगर गुप्ता जी होते तो ये तर्क हम उनको भी बताते क्योंकि वे कह रहे थे कि घाटे को कैसे मीट आउट करेंगे। परन्तु वे चले गए। स्पीकर सर, हमें तो विरासत में ही 150 करोड़ रुपये का घाटा मिला था। उल्टे हमने तो रिकवरी करके रवैन्यू बढ़ाने की कोशिश ही की है। स्पीकर सर, आप तो बहुत इंटेलैक्चुअल हैं, इंटेलीजैंट हैं। सारे देश की इकोनोमी में रिसैशन आ रहा था जैसे मैं पहले कह रहा था कि पाकिस्तान ने कैसे युद्ध किया, उन दिनों कैसे हालात थे। यह तो हिंदुस्तान की अर्थ-व्यवस्था थी जो एग्रीकल्चर बेस्ड है। जापान या कोरिया जैसे लोगों की इकोनोमी तो ऐसे हालात

[श्री सम्पत सिंह]

में फेल हो जाती, वे भिखमंगे हो जाते और उनको कोई भीख भी न देता। ये तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है जिस पर हमें फख्र है कि एक तरफ तो बोर्डर्स पर हमारे देश के जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपनी जान की बाजी लगा दी जिसमें हरियाणा प्रदेश का सबसे ज्यादा योगदान है। हमारे यहां कृषि के भंडार हैं और अनाज का जो उत्पादन है उसमें हरियाणा प्रदेश ने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया है। मेरे कहने का मतलब है कि इन विपरीत हालातों में हमने इतना अच्छा उत्पादन किया है जिससे हमारी इकोनोमी रिसैशन से बाहर आ रही है। जब इकोनोमी रिसैशन से बाहर आयेगी तब ग्रोथ बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ेगा, इण्डस्ट्रीयल उत्पादन बढ़ेगा। नयी इण्डस्ट्रीयल पौलिसी आई है। इस बारे में मैं लम्बी चौड़ी बात न करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने जो पौलिसी लागू की है इससे काफी निवेश आ रहे हैं। इस बारे में मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा कि इससे हमें कितनी इनकरेजमैंट मिली है और जो निवेश किया है वह कितना कैटेलाइज हो चुका है जिससे अपने आप पता लग जाएगा कि हरियाणा प्रदेश की इकोनोमी किधर जाएगी और किस तरह से घाटे को पूरा करेगी। जो नयी औद्योगिक नीति आई है और केटेलाइज हुई है उससे फरवरी 2000 तक जो निवेश आए हैं वह 2641 करोड़ के आए हैं और पाइप लाइन उद्योग लगाने के लिए 252 करोड़ रुपये आए हैं टोटल 2900 करोड़ की इन्वैस्टमैंट कैटेलाइज हो चुकी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनोमी को कितना चढ़ाव मिलेगा और इससे 64600 लोगों को रोजगार मिलेगा। सुबह कह रहे थे कि जीवूस के लिए प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं। विकास से इंप्लोयमैंट मिलता है सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती। जब तक प्रदेश का चहुंमुखी विकास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। सड़क, स्कूल, अस्पताल, कालेज और नहरें बनेंगी तो अपने आप लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो कैसे विकास होगा ? अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रदेश के क्या हालात थे जब वर्तमान सरकार ने पदभार संभाला था सारा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया था चाहे सड़कों की बात हो, या नहरों की बात हो या स्कूलों की बात हो या चाहे अस्पतालों की बात हो सारा का सारा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया था। ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की हिम्मत है कि उन्होंने सारा का सारा स्ट्रक्चर रिवाइज करने का फैसला किया और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर-घर गए और जिन लोगों की बात कोई सुनता नहीं था उनकी बात सुनी। जो लोग चंडीगढ़ आकर घूम घूम कर चले जाते थे उनकी बात को सुनकर हरियाणा प्रदेश के विकास को शुरु किया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जब प्रदेश में विकास के काम होंगे तो घाटे का बजट होगा। भांगे राम गुप्ता जी भी कोई विकास कार्य कर नहीं पाए थे सिर्फ गलत आंकड़े देकर चले गए थे। अध्यक्ष महोदय, यह बजट रोजगारोन्मुखी बजट है इससे रोजगार मिलेगा। अब मैं अग्रोहा मैडीकल कॉलेज के कर्ज की बात कहना चाहूंगा। कर्ज के बारे में उन्होंने बड़े ही जगलरी और ड्रामाटिक तरीके से गलत फिग्गर पेश करने की कोशिश की और जहां तक कर्ज का सवाल है, यह कर्ज कोई नयी बात नहीं है। स्वाभाविक है कि ग्रोइंग स्टेट है जिसको ग्रो करना है उसको कर्ज लेना पड़ेगा। बाकी जो नहर के सिस्टम को सुधारना है उसके लिए डब्ल्यू०आर०सी०पी० है उसका काम आज से नहीं है 5-6 साल से चल रहा है। हमारी कोशिश यह होगी कि इसको एक्जिस्ट करायें। नाबार्ड से लोन लेते हैं इरीगेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ताकि हमारे एग्रीकल्चर सैक्टर में मजबूती आये। पावर सैक्टर के लिए भी लोन लेना पड़ता है इससे हमारा पावर सैक्टर मजबूत होगा। अगर पावर सैक्टर मजबूत होता है तो स्वाभाविक है कि कृषि क्षेत्र मजबूत होगा (इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री रामपाल माजरा जी चेयर पर पदासीन हुए) सभापति महोदय, आप भी पैडी एरिया से संबंध रखते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पावरसैक्टर मजबूत नहीं होगा तो किसानों की पैडी के सीजन में

क्या हालत होगी। चेयरमैन सर, आपको याद होगा कि 1987-88 में चौधरी देवी लाल जी ने किसानों को बिजली देकर रिकार्ड तोड़ पैडी की पैदावार करवायी थी और इस बार चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने किसानों को पूरी बिजली देकर पैडी की रिकार्ड तोड़ पैदावार करवायी है। चेयरमैन सर, आज तक हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है कि सत्ता पक्ष की सरकार को चुनाव के समय हमेशा नेगेटिव वोट जनता ने दिया है। पूरे देश में या तो आन्ध्र प्रदेश की सरकार है या पश्चिमी बंगाल की सरकार है जिनकी जनता ने चुनावों के समय पोजीटिव वोट दिया है। आज हरियाणा प्रदेश देश का तीसरा राज्य है जिसकी सरकार को चुनाव के समय जनता ने पोजीटिव वोट दिया है और पोजीटिव मेन्डेट दिया है। आज चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार को वर्क्स के आधार पर दोबारा चुनकर 36 बिरादरी के लोगों ने यह सरकार बनाई है। दूसरी बात कही गई कि कर्जा कैसे मिलेगा। विपक्ष के साथियों ने तो यह बात ऐसे कह दी जैसे यह सारा का सारा 15217 करोड़ रुपये का कर्जा वर्तमान सरकार ने ही लिया है। जब वर्तमान सरकार ने पदभार संभाला उस समय कर्जे की राशि 12750 करोड़ रुपये थी। और कहते ऐसे हैं जैसे यह सारा कर्जा हमने ही लिया हो। अगर वर्तमान कर्जे की राशि को हम देने में सक्षम हो जायेंगे तो एक दिन हरियाणा प्रदेश टैक्स फ्री स्टेट और कर्जा फ्री स्टेट बन जायेगा और ऐसा तभी संभव है जब कि सरकार स्थिर हो। इस बार जिस प्रकार चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार को लोगों ने मेनडेट देकर भेजा है। उसी हिसाब से हरियाणा प्रदेश का बहुमुखी विकास यह सरकार करेगी। चेयरमैन सर, जैसा कि श्री मांगेराम गुप्ता जी ने अग्रोहा मेडीकल कालेज के बारे में बात की और आनन-फानन में भी ओमप्रकाश जिन्दल ने भी इस बारे में अपनी बात की। चेयरमैन सर, जैसा एग्रीमैंट चौधरी देवी लाल जी ने किया था वैसा एग्रीमैंट आज तक कभी नहीं हुआ क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मैडीकल कालेज की 99 प्रतिशत रिकरींग ग्रान्ट सरकार दे और वह कालेज प्राइवेटली एरेन्जड कालेज हो। चौधरी देवी लाल जी को एक तरफ महाराजा अग्रसेन जी के नाम से लगाव था और दूसरी ओर अग्रवाल कम्यूनिटी के साथ लगाव था तथा तीसरा हरियाणा स्टेट से लगाव था। हरियाणा प्रदेश को चार मेडीकल कालेजिज की जरूरत थी। उस समय केवल एक ही मेडीकल कालेज रोहतक में था। चौधरी देवी लाल जी ने हिम्मत करके 99 प्रतिशत ग्रान्ट अग्रोहा मेडिकल कालेज को दी थी। स्पीकर सर, मैचिंग ग्रान्ट स्कीम में 50 प्रतिशत ग्रान्ट पब्लिक की तरफ से आती है और 50 प्रतिशत ग्रान्ट सरकार देती है। इस ग्रांट से उस कालेज के लिए इक्विपमेंट आदि खरीदे जाते थे। लेकिन चौधरी भजन लाल जी इक्विपमेंट खरीदने वाली उस 50 प्रतिशत ग्रान्ट को बन्द कर गये। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए जो ग्रान्ट दी जाती थी उसको चौधरी बंसी लाल जी ने खत्म कर दिया। अब चौधरी भजन लाल जी को व श्री मांगे राम गुप्ता जी को तो इसके लिए एप्रीशिएट करना चाहिये था क्योंकि श्री मांगे राम गुप्ता जी तो अग्रवाल कम्यूनिटी से हैं। श्री ओमप्रकाश जिन्दल जी भी अग्रवाल कम्यूनिटी से हैं। इसलिए इनको भी एप्रीशिएट करना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी की सरकार में श्री मांगे राम गुप्ता जी शामिल थे और दूसरी सरकार में श्री ओमप्रकाश जिन्दल पार्टी के सदस्य थे। अब दोनों ही माननीय सदस्य वाक आऊट कर गये। इसके बाद श्री मांगे राम गुप्ता जी ने सात करोड़ रुपये देने की बात रखी। चेयरमैन सर, जब डिमाण्ड आती है तभी एल०ओ०सी० रिलीज किया जाता है जब हमारे पास 50 लाख रुपये की डिमाण्ड आई तो हमने तत्काल एल०ओ०सी० रिलीज कर दी। इसके बाद उनकी डिमाण्ड आई 50 लाख रुपये निर्माण कार्यों के लिए चाहिएं क्योंकि उन्होंने इस काम के लिए टैण्डर इंवाइट किए हुए हैं। वे 50 लाख रुपये भी रिलीज कर दिए।मैंने पहले भी कहा था कि यह सरकार इस बारे में बिल्कुल कटिबद्ध है। पिछली बार बजट में अग्रोहा मेडीकल कालेज के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान था और इस साल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैडिकल कालेज को रिकोग्नाइज करने के लिए जितना पैसा

[श्री सम्पत सिंह]

चाहिए था उसके लिए चौधरी देवी लाल जी ने जो एग्रीमैंट किया था उस एग्रीमैंट की कंडीशंज के आधार पर उस एग्रीमैंट की एक-एक लाइन को, एक-एक शब्द को पूरा करने के लिए यह सरकार तैयार है, कटिबद्ध हैं और यह सरकार उसको पूरा करेगी। इसी तरीके से सेल्ज टैक्स के बारे में ओम प्रकाश जिन्दल जी और मांगे राम जी ने कहा कि उन्होंने 2-3 आइटमों पर सेल्ज टैक्स कम कर दिए थे। सभापति महोदय इसके बारे में सुबह स्पीकर साहब ने वर्णन किया था कि वे आइटम जिन पर इन्होंने सेल्ज टैक्स कम किए थे, बहुत ही छोटी आइटम्स थीं। 1987 से 1991 में जब देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे और बाद में श्री ओमप्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय 65 आइटमों पर सेल्ज टैक्स या तो खत्म कर दिए गए थे या फिर कम कर दिए गए थे। उस समय यह कितना सराहनीय काम किया गया था। अब भी व्यापारियों के हित सरकार के हाथों में सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने जो हाई पावर कमेटी बनाई उसमें कांग्रेस पार्टी का जो नोमिनी था उसको व्यापारी वर्ग के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। जबकि इस कमेटी में जो व्यापारियों का प्रतिनिधि होता है वह इरिस्पैक्टिव आफ एनी पार्टी एफीलिएशन होता है। पिछली सरकारों के समय में अपने विचारों के लोगों को, अपने चहेतों को जो पिछलग्गू टाइप के होते हैं उनको इस कमेटी में शामिल कर लिया जाता था। ऐसा कार्य करके मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने कितनी उदारदिली दिखाई है, इनको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके तहत 50 लाख तक के सैल्फ असैसीज, 80 प्रतिशत सेल्ज टैक्स असैसीज, 80 प्रतिशत व्यापारी कवर हो जाते हैं। अब उनको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी वजह से ही व्यापारियों ने भी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को मेन्डेट दिया है। सभापति महोदय, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने कई आइटम्ज पर मार्किट फीस 2 प्रतिशत से घटाकर एक परसैंट की है। इन सब बातों के लिए इन लोगों को एप्रीशिएट करना चाहिए। कर विवाद स्कीम के बारे में भी हम सोच रहे हैं तथा और भी कई स्कीमें हम लागू करने जा रहे हैं। पिछली सरकार के समय डी०ई०टी०सी० के दफ्तरों में टैक्स पेयी व्यापारियों के लिए बैठने के लिए प्रबन्ध नहीं होता था। हमारी सरकार ने अब उन व्यापारियों के लिए बैठने के लिए सैपरेट अरैन्जमैंट करवा दिया है, पीने के लिए पानी का भी इंतजाम करवा दिया है। पुरानी सरकारों में उनको चोर के रूप में आंका जाता था और आज की सरकार उनको टैक्स पेयी के रूप में आंक रही है, उनको एक कंट्रीब्यूटर के रूप में आंक रही है। यही कारण है कि लोगों ने श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर इज्जत दी है। सभापति महोदय, किसानों की बात करते हुए यहां कहा गया है कि बजट में इतने परसैंट एग्रीकल्चर के मामले में जगलरी की गई है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि क्या पावर एग्रीकल्चर से सम्बन्धित नहीं है, इरीगेशन एग्रीकल्चर से सम्बन्धित नहीं है और दूसरी चीजें पैस्टीसाइड, इन्सैक्टीसाइट, फर्टीलाइजर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई नहीं हैं ? हर चीज एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इन सब चीजों के बजट के बारे में हमने जो प्रावधान किया है उस बारे में तो ये लोग बात नहीं करते हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने यूनीफोरम सेल्ज टैक्स लागू करते समय भी किसानों के हितों पर निगाह रखी है। यूनीफोरम सेल्ज टैक्स पोलिसी लागू होने के बावजूद भी हमने फर्टीलाइजर, पैस्टीसाइड, इन्सैक्टीसाइड इन तीनों चीजों को उसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि इन तीनों चीजों का किसान से डायरैक्ट सम्बन्ध है। इससे सरकार को 75 करोड़ रुपये का नुकसान होगा परन्तु हमारी सरकार को किसानों के हित प्यारे हैं न कि 75 करोड़ रुपये । इसी तरह से मांगे राम जी जाते-जाते कह गए कि रूरल डिवैल्पमैंट फण्ड के लिए बजट में 35.10 करोड़ रुपये रखे गए हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि पिछली बार 31 मार्च तक रूरल डिवैल्पमैंट फण्ड के लिए 120 करोड़ रुपये का एस्टीमेट रखा गया था परन्तु इस साल कई चीजों पर मार्किट फीस कम करने के कारण यह एस्टीमेट

110 करोड़ रुपये का आ रहा है। यह रूरल डिवैल्पमैंट फण्ड विकास के कार्यों पर ही खर्च होगा। आज यह सरकार हरियाणा प्रदेश के हर गांव की सड़कों को ठीक करवा रही है। सड़कों के गड्ढे भरवाने का काम यह सरकार पूरा करवा चुकी है। 30 मई तक सारे हरियाणा प्रदेश की टोटल सड़कों की मुरम्मत करवा दी जाएगी। इससे बढ़िया काम हमारी सरकार और क्या करेगी। सभापति महोदय, मांगे राम जी कह गये कि हमने पशु-पालन और मछली पालने के लिए बजट में पैसा नहीं रखा। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वे बजट ठीक तरह से पढ़ते तो हैं नहीं और ऐसे ही कुछ ही कह देते हैं। सभापति महोदय, बजट के पेज-17 पर कृषि, पशुपालन, बागबानी, मछली पालन, डेरी विकास तथा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हेतू वर्ष 2000-2001 के लिए 308.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और मांगे राम जी ने कहा कि इसके लिए हमने कोई पैसा नहीं रखा। इसी तरह से चेयरमैन सर, मांगे राम जी ने कहा कि हमने पुलिस के वैलफेयर के लिए बजट में कोई भी पैसा नहीं रखा। मुझे तो यह कहते हुए शर्म आती है कि वे पांच साल तक वित्त मंत्री कैसे रहे। वे बिना पढ़े ही कुछ भी कह गये। चेयरमैन सर, पुलिस का जो मेजर हैड है उसमें 2055 करोड़ रुपये है। नोन-प्लान में पहले 363.94 करोड़ रुपये रखा गया था और वर्ष 2000-2001 के लिए 396.73 करोड़ रुपये रखा है चेयरमैन सर, इसी तरह से प्लान के लिए पिछले साल जो 6 करोड़ रुपये रखा गया था उसकी जगह 8 करोड़ रुपये इस साल के प्लान बजट में रखे हैं। जबकि मांगे राम जी ने कहा कि हमने पुलिस के लिए पैसा रखा नहीं है। हमने तो 400 करोड़ ज्यादा रखे हैं। चेयरमैन सर, इसी तरह से मांगे राम जी ने कहा कि हार्टिकल्चर के लिए जो 12.50 करोड़ रुपये रखा है वह कहां से आयेगा। इस बारे में भी बजट में चर्चा नहीं की गई। इस बारे में बताना चाहूंगा कि यह एक ऑन-गोइंग प्रोसैस है और फरवरी, 2000 तक इसमें 6 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और 5.91 करोड़ रुपये हार्टिकल्चर के लिए और प्रोवाईड किये जायेंगे। इस तरह से ये 12.50 करोड़ रुपये के करीब बनते हैं और जो प्लान बजट है वह 5.91 करोड़ रुपये है, इस तरह से यह पैसा अपने आप मीट-आऊट हो जायेगा। चेयरमैन सर, चौधरी बंसी लाल जी ने एक सुझाव भी दिया था और शंका भी जाहिर की थी कि जो हिसार-घग्गर ड्रेन का प्रोजैक्ट है, क्योंकि वह और स्टेटस से संबंधित है इसलिए उसके बारे में साथ लगती स्टेट्स आब्जैक्शन उठायेंगी। इस बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार तो हो सकता है कि आब्जैक्शन करे लेकिन पंजाब और हिमाचल आब्जैक्शन नहीं करेंगे। चेयरमैन सर, मैं बंसी लाल जी को बताना चाहूंगा कि इस प्रोजैक्ट के लिए एक कमेटी बनी हुई है और सी०डब्ल्यू०सी० (फ्लड) का मैंबर उस कमेटी का चेयरमैन है। उन्होंने इस ड्रेन के लिए बाकायदा क्लियरैंस दे दी है। क्लियरैंस के बाद ही यह प्रोजैक्ट शुरू किया गया है। स्पीकर सर, डा० कादियान जी ने भी कहा था कि इरीगेशन के ऊपर, पॉवर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 64.5% रुपये रखे हैं, उसके बारे में यह नहीं बताया गया कि यह पैसा कहां से आयेगा और कैसे इसको यूज किया जायेगा। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह 64.5% पैसा आउट आफ प्लान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जायेगा। यह बजट में भी लिखा हुआ है। ये लोग बजट के बारे में किताब तो पढ़ते नहीं हैं और कुछ भी कह देते हैं। सभापति महोदय, यह 64.5% पैसा प्लान हैड में 2530 करोड़ रुपये रखा है उस पैसे में से ही इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। इसी तरह से जिंदल साहब को अपनी इंडस्ट्री की तकलीफ थी। उन्होंने कहा कि सेल टैक्स ट्रिब्यूनल के मैम्बर जूडिशियल हो, फलाना हो, परमानैन्ट हो, रैगुलर हो, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। इस तरह की बातों का इन्होंने यहां जिक्र किया है जबकि कोर्ट में विचाराधीन केस के बारे में जिक्र सदन में नहीं किया जा सकता। हिसार में मै० जिंदल स्ट्रिप्स लि० के नाम से इनकी कम्पनी है। इस कम्पनी द्वारा ओनरेबल पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। Now, the matter is pendiding with the Hon'ble High Court

[श्री सम्पत सिंह]

जबकि यहां ये सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इस तरह की बातों का इनको इस सदन में जिक्र नहीं करना चाहिए था। क्या ये अपनी कम्पनी का इन्ट्रस्ट वॉच करने के लिये विधान सभा में आये हैं या लोगों का इन्ट्रस्ट वॉच करने के लिये आये हैं। थोड़ा बहुत इस बात का ध्यान तो इनको रखना चाहिए। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिन्दल साहब ने गजट नोटिफिकेशन के बारे में कहा कि इनको गजट नोटिफिकेशन होने का कोई पता नहीं चलता है। मांगे राम गुप्ता जी ने भी इस तरह की बात की थी। किसी ने जिन्दल साहब को कुछ टाइप करके दे दिया जिसको वे यहां पढ़ रहे थे। इनको पता कुछ है नहीं, बोलना कुछ आता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक गजट नोटिफिकेशन का सवाल है, इससे जो रिलेवेंट इन्फोरमेशन है वह बिल्कुल प्रोम्पटली बकायदा प्रैस के द्यू दी जाती है और अब तो आप इस बात को भी एप्रीशिएट करेंगे कि इसको भी डिपार्टमैन्ट ने इन्टरनैट वैब साइट में फीड कर दी है। अब जिन्दल साहब जब मर्जी जो इन्फोरमेशन लेना चाहें वह इन्टरनैट वैब साइट पर ले सकते हैं। आज कल तो बड़े-बड़े व्यापारियों ने बाकायदा इन्टरनैट लगा रखे हैं। इससे फालतू और क्या सुविधा सरकार दे सकती है। आज अगर कोई गजट नोटिफिकेशन आती है तो उसी टाइम इन्टरनैट वैब साइट में फीड कर दी जाती है। जब मर्जी कम्प्यूटर को खोलकर पता कर लें। इससे बड़ी सुविधा हरियाणा सरकार और क्या दे सकती है। इन्होंने तो आलोचना के लिये भी आलोचना करनी है। अध्यक्ष महोदय, राई की मण्डी के बारे में माननीय सदस्य चौ० सूरजमल ने जिक्र किया था। पहले भी कई सदस्यों ने गवर्नर एड्रैस के टाइम इस मण्डी के बारे में जिक्र किया था। यह परियोजना भी हम बाकायदा सिरे चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार ने भी एक प्लान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 1 पर खानपुर कलां में इसी तरह की मण्डी बनाने की एक परियोजना बनाई है। अगर वे भी इस योजना को बना लेते हैं तो हमारी इस योजना पर चाहे कितना भी पैसा क्यों न खर्च कर लें वह कामयाब नहीं हो सकती। इसलिये हमने दिल्ली सरकार के साथ मैटर-टेक अप किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के साथ बात की है कि हमारे यहां आलरेडी यह परियोजना है और आप अपनी इस परियोजना को रहने दें और हमें अपनी परियोजना को कान्टीन्यू करने दें। ताकि इस प्रोजैक्ट पर हमारी जो ग्रोथ बाकी है उसको हम पूरा करें। हमने इस मैटर को सीरियसली टेक-अप किया है जबकि आज तक किसी भी सरकार ने इस मामले को टेक-अप नहीं किया। केवल उस पर ये लोग झाड़ झंकार करते रहे। इन लोगों को तो इस बात के लिये सरकार की सराहना करनी चाहिए और इस काम में मदद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष के सदस्य कहते हैं कि फ्लड कन्ट्रोल में केवल 20 करोड़ रुपया रखा है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 20 करोड़ रुपया कैसे रखा है। डब्ल्यू०आर०सी०पी० में फ्लड कन्ट्रोल का पैसा है, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट फण्ड में फ्लड का पैसा है और नाबार्ड में भी फ्लड कन्ट्रोल का पैसा है। यह 20 करोड़ रुपया तो प्लान आउट ले में स्टेट की तरफ से खर्च होना है इसके अलावा फ्लड कन्ट्रोल का काम दूसरी ड्रेनों वगैरा को बनाकर किया जाएगा। जिन ड्रेनों के प्रोजैक्ट चल रहे हैं उन प्रोजैक्टों को भी पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब बिलो-पौवरटी लाइन की बात आती है। अध्यक्ष महोदय, आप भी चुनावों के दौरान गांवों में गये, हम भी गये। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले सभी गांवों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ओपन-दरबार लगाये थे और उस समय मुख्यमंत्री जी को लोगों की शिकायतें मिलती थीं कि फलाना बिलो पोवरटी लाइन में है, मेरा कार्ड नहीं मिला है। हालांकि 1998 में बी०पी०एल० का सर्वे हो चुका था जिसकी सूची में पांच लाख 64 हजार नाम बढ़े थे फिर भी सी०एम० साहब ने 29-11-99 को आदेश जारी किए कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति रह गये हैं जिनका नाम सर्वे के दौरान उस सूची में नहीं जोड़ा गया

है उनके नाम जोड़ने के लिये भी कार्यवाही की जाए। सी०एम० साहब के आदेशों के मुताबिक सरकुलर जारी हो चुका है और जो आवेदन आये हैं उन पर कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा नये आवेदन भी विभाग को दिये जा सकते हैं उन पर बाकायदा कार्यवाही की जाएगी और सर्वे पूरा किया जाएगा। इससे बड़ा सराहनीय काम और क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल तीन चार बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और विपक्ष में तो इनको बैठने का थोड़ा ही समय मिला है। इन्होंने कहा कि पावर सैक्टर में 800 करोड़ रुपये की एग्रीकल्चर के लिये सबसिडी रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि वह अमाउन्ट 800 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 846.40 करोड़ था जिसमें से 1998-99 की कैश सबसिडी केवल 364 करोड़ रुपये थी और 482.40 करोड़ रुपये तो लोन की एडजस्टमैन्ट थी। वह सारी कैश सबसिडी नहीं थी। हमने पावर सैक्टर में एग्रीकल्चर कन्जयूमर के लिये कैश सबसिडी 412 करोड़ रुपये रखी है। लोन की एडजस्टमैन्ट तो साल के बाद में होती है। लोन की जो एडजटमैन्ट होती है वह कैश सबसिडी में नहीं मानी जाती। इस तरह इनकी फिगर्ज मिक्स हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, जैसा गलत ब्यानी मांगे राम जी कर रहे थे उसी तरह से हुड्डा साहब भी गलत ब्यानी कर रहे थे जो कि अब यहां बैठे नहीं हैं। वे अपने आपको राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का अध्यक्ष मानते हैं। वे पार्लियामैन्ट के मैम्बर भी रह चुके हैं और अपने आपको सीनियर आदमी कहते हैं। हुड्डा साहब ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र में गन्ने के दाम 150/- रुपये प्रति क्विंटल दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में गन्ने के दाम 76/- रुपये प्रति क्विंटल दिये हैं जबकि हरियाणा सरकार ने 110/- रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के दाम दिये हैं। जहां तक रिकवरी का सवाल है तो हमारी सरकार की रिकवरी ओन एन एवरेज 9% है। कभी-कभी किसी एक आधी मिल की रिकवरी 10% आ जाती है जबकि महाराष्ट्र की रिकवरी 12% से 14% रहती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर गन्ने की फसल तकरीबन 10 महीने में तैयार हो जाती है जबकि महाराष्ट्र में एक साल में या 13, 14 महीने में तैयार होती है। वहां पर गन्ने की फसल पर इन्वैस्टमेंट भी हमारे यहां की अपेक्षा बहुत अधिक आती है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में तो गन्ने के दाम 76 रुपये प्रति क्विंटल हैं जबकि हमारे यहां पर 110/- रुपये प्रति क्विंटल हैं। गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए हुड्डा साहब ने गन्ने की प्राइस के बारे में बहुत गलत ब्यानी की है। अध्यक्ष महोदय, जैसे उन्होंने यहां पर गलत ब्यानी की है उस हिसाब से तो उनके खिलाफ प्रिवलिज मोशन आ जाना चाहिए था। सदन के दूसरे सदस्यों ने जो-जो सुझाव दिए हैं वे नोट कर लिए गए हैं। विपक्ष के सदस्यों ने रचनात्मक तरीके से बजट पर विचार प्रकट न करके आलोचनात्मक तरीके से अपने विचार प्रकट किए हैं। अन्त में स्पीकर साहब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो बजट हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रस्तुत किया है उसे यूनानीमसली पास किया जाये। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष का चुनाव

Mr. Speaker : Now, election of Deputy Speaker will be conducted. I call upon the Hon'ble Chief Minister to propose the name for the election of the Deputy Speaker.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, पुरानी ट्रेडीशन को बरकरार रखते हुए स्पीकर सत्ता पक्ष से चुना गया है। विपक्ष की तरफ से यह मांग उठती रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष की तरफ से चुना जाना चाहिए। चूंकि स्पीकर सत्ता पक्ष का होता है, उस पद पर आप चुने जा चुके हैं और आपने अपनी पार्टी से व उसकी प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इस बात के लिए मैं

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का है यह मांग हमारे विपक्ष की तरफ से उठी है। अब हाउस में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वह तो इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। इस समय विपक्ष के रूप में सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार सदन में उपस्थित हैं। जो आजाद उम्मीदवार चुन कर आए हैं उनकी संख्या विपक्ष के नाते दूसरे नम्बर पर आती है। आजाद उम्मीदवारों की गिनती को मध्यनजर रखते हुए मेरे विचार से उनमें से एक सदस्य को डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनना चाहिए। श्री गोपी चन्द गहलोत जी जो गुड़गांव से जीत कर हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए हैं वे काबिल उम्मीदवार हैं। स्पीकर महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

> कि हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री गोपी चन्द गहलोत जो कि सदन में उपस्थित हैं, को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाये।

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने श्री गोपी चन्द गहलोत जी के नाम को उपाध्यक्ष के पद के लिए प्रस्तावित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Shri Gopi Chand Gahlot, a member of the Haryana Legislative Assembly, who is present in the House, be elected as Deputy Speaker of the Assembly.

Is there any other proposal please ?

Voices : No.

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि सदन के नेता ने श्री गोपी चन्द गहलोत जी को जो आजाद उम्मीदवार चुन कर सदन में आये हैं, सदन के उपाध्यक्ष के लिए उनके नाम का प्रस्तावित किया है। चौधरी गहलोत जी बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता हैं। मैं इनके नाम का उपाध्यक्ष पद के लिए समर्थन करता हूं। हमें उम्मीद है कि ये हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। इसलिए मैं पुनः सदन के नेता का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने गोपी चन्द जी के नाम का जो उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया है उसका मैं भी समर्थन करता हूं और गोपी चन्द जी को इस पद पर चुने जाने के लिए बधाई देता हूं।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने उपाध्यक्ष पद के लिए श्री गोपी चन्द जी के नाम का जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और इनके नाम का अनुमोदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे। अतः मैं इनके उपाध्यक्ष चुने जाने पर इन्हें बधाई देते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री राम भगत : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने आजाद उम्मीदवारों का जो मान-सम्मान बढ़ाया है उसके लिए मैं सदन के नेता का धन्यवाद करता हूं और श्री गोपी चन्द जी के उपाध्यक्ष चुने जाने के नाम का अनुमोदन करते हुए और इन्हें धन्यवाद देते हुए अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Speaker : Since there is only one proposal before the House that Shri Gopi Chand Gahlot be elected as Deputy Speaker, I declare him duly elected as Deputy Speaker of the Assembly Unanimously, (Thumping) I request him to take the seat of the Deputy Speaker.

(As this stage, Shri Gopi Chand Gahlot Escorted by the Chief Minister and Shri Krishan Pal, a member of the Bharatiya Janata Party and many other Independent Members, occupied the seat of the Deputy Speaker) (Thumping)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गोपी चन्द गहलोत जी को सर्वसम्मति से 17.00 बजे उपाध्यक्ष के पद पर चयन करने के लिए इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अब तक की उन सारी परम्पराओं और रिवायतों को बरकरार रखा। श्री गोपी चन्द गहलोत जी एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और एक वकील के रूप में बहुत लम्बे समय तक उन्होंने लोगों की सेवा की है। कानून का ज्ञाता होने की वजह से छोटे-मोटे विवादों और वखेड़ों को सुलझाने में भी उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी ग्रासरूट्स से आया हुआ व्यक्ति आम नागरिक की समस्याओं और दिक्कतों को सुलझाने में बहुत ही चतुर होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आपकी तरह ही श्री गोपी चन्द गहलोत जी भी इस पद की गरिमा को बरकरार रखेंगे तथा सारे हाउस को विश्वास में लेकर सदन के हर सदस्य को अपनी तरफ से पूरा मान तथा सम्मान प्रदान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता के तौर पर और सभी सदन के सम्मानित सदस्यों की तरफ से मैं उपाध्यक्ष महोदय को यह विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी तरफ से आपको भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गोपी चन्द गहलोत जी, आज आप यूनानिमसली हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्विवाद चुने गए हैं उसके लिए इस महान सदन को बड़ी खुशी महसूस हुई है तथा सारे हरियाणा प्रदेश को भी इससे बड़ी खुशी महसूस होगी क्योंकि एक सुयोग्य, पढ़ा-लिखा, कानून का ज्ञाता और बड़े नर्म तबीयत के इन्सान को हरियाणा विधान सभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर निर्विवाद चुना गया है। आपके चयन पर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है और सभी सदस्यों को भी बहुत खुशी हुई है। हम मिल-जुल कर इस सैक्रेटेरियेट में बड़े अच्छे तरीके से मैम्बर साहेबान के अधिकारों की रक्षा करेंगे तथा इस सदन को सही ढंग से और सुचारू रूप से चलाने में मुझे आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। श्री गोपी चन्द गहलोत जी के चयन के लिए मैं सभी मैम्बर साहेबान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सुयोग्य व्यक्ति को इस पद के लिए चुना है। भगवान श्री गोपी चन्द गहलोत जी को ऐसी ताकत दे कि वे अपने इस गरिमामई पद को ग्रहण कर इसे गरिमामयी ढंग से चलायें तथा राज्य तथा अपने लोगों को विकास और भलाई के रास्ते पर चलाएं। भगवान हर मामले में उनकी मदद करे ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : इस महान सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी और दूसरे सदन के सभी साथियों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। मैं अपनी ओर से आप सबको विश्वास तथा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस पद की गरिमा को मैं पूर्ण रूप से कायम रखूंगा तथा अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही को आप सब के सहयोग से रूल्ज़ और पार्लियामैंटरी कन्वैंशन्ज़ के मुताबिक चलाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मैं आप सबसे खासकर लीडर ऑफ दि ओपोज़ीशन जो कि मेरे साथ बैठते हैं से भी सहयोग की आशा करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मुझे अपना पूरा सहयोग देंगे ऐसी उम्मीद और अपेक्षा आप सब से करता हूं। एक बार पुनः आप सब को धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करता हूं विशेष तौर पर हाउस के नेता का आभार प्रकट करता हूं। मैं हर कीमत पर सदन की गरिमा को कायम रखूंगा। विशेषकर नव-आगंतुक साथियों के हितों की रक्षा करने की कोशिश करूंगा।

वर्ष 2000-2001 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the Demands for Grants on Budget for the year 2000-2001 will take place. As per the past practice and to save the time of the House, the demands on order paper (Nos. 1 to 25) will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding *Rs. 6,97,50,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 1—Vidhan Sabha.*

That a sum not exceeding *Rs. 1,08,73,97,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 2—General Administration.*

That a sum not exceeding *Rs. 4,56,24,42,000* for revenue expenditure and *Rs. 8,00,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 3—Home.*

That a sum not exceeding *Rs. 75,57,66,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 4—Revenue.*

That a sum not exceeding *Rs. 39,95,00,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 5—Excise and Taxation.*

That a sum not exceeding *Rs. 7,97,75,25,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 6—Finance.*

That a sum not exceeding *Rs. 2,88,01,69,000* for revenue expenditure and *Rs. 3,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 7—Other Administrative Services.*

That a sum not exceeding *Rs. 3,89,91,13,000* for revenue expenditure and *Rs. 3,02,25,30,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 8—Building and Roads.*

That a sum not exceeding *Rs. 13,06,97,33,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 9—Education.*

That a sum not exceeding *Rs. 5,98,34,54,000* for revenue expenditure and *Rs. 1,55,60,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 10—Medical and Public Health.*

That a sum not exceeding *Rs. 32,81,44,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 11—Urban Development.*

That a sum not exceeding *Rs. 57,54,68,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 12—Labour and Employment.*

That a sum not exceeding *Rs. 4,63,31,44,000* for revenue expenditure and *Rs. 1,50,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under Demand No. *13—Social Welfare and Rehabilitation.*

That a sum not exceeding Rs. 21,80,74,000 for revenue expenditure and Rs. 7,10,03,93,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under Demand No. 14—Food and Supplies.

That a sum not exceeding *Rs. 9,14,35,00,000* for revenue expenditure and *Rs. 7,12,42,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No.15—Irrigation.*

That a sum not exceeding *Rs. 33,63,43,000* for revenue expenditure and *Rs.10,31,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 16—Industries.*

That a sum not exceeding *Rs. 2,31,48,54,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 17—Agriculture.*

[Speaker]

That a sum not exceeding *Rs. 1,03,77,93,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No.18—Animal Husbandry.*

That a sum not exceeding *Rs. 9,83,92,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 19—Fisheries.*

That a sum not exceeding *Rs. 67,07,65,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 20—Forest.*

That a sum not exceeding *Rs. 93,02,21,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 21—Community Development.*

That a sum not exceeding *Rs. 24,38,15,000* for revenue expenditure and *Rs. 5,09,14,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 22—Co-operation.*

That a sum not exceeding *Rs. 4,70,40,37,000* for revenue expenditure and *Rs. 40,58,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 23—Transport.*

That a sum not exceeding *Rs. 1,60,21,000* for revenue expenditure and *Rs. 3,50,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 24—Tourism.*

That a sum not exceeding *Rs. 3,79,26,10,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.*

वित्तमंत्री (श्री सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही से बजट पर बहस चल रही है। बजट से ही ये डिमान्डज राईज होती हैं। आलरेडी इन पर सब बोल चुके हैं। अगर हाउस सहमत हो तो इन सबको इक्ट्ठा ही पास कर लिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding *Rs. 6,97,50,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 1—Vidhan Sabha.*

That a sum not exceeding *Rs. 1,08,73,97,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 2—General Administration.*

That a sum not exceeding *Rs. 4,56,24,42,000* for revenue expenditure and *Rs. 8,00,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 3—Home.*

That a sum not exceeding *Rs. 75,57,66,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 4—Revenue.*

That a sum not exceeding *Rs. 39,95,00,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 5—Excise and Taxation.*

That a sum not exceeding *Rs.7,97,75,25,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 6—Finance.*

That a sum not exceeding *Rs. 2,88,01,69,000* for revenue expenditure and *Rs. 3,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 7—Other Administrative Services.*

That a sum not exceeding *Rs. 3,89,91,13,000* for revenue expenditure and *Rs. 3,02,25,30,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 8—Building and Roads.*

That a sum not exceeding *Rs. 13,06,97,33,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 9—Education.*

That a sum not exceeding *Rs. 5,98,34,54,000* for revenue expenditure and *Rs.1,55,60,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 10—Medical and Public Health.*

[Speaker]

That a sum not exceeding *Rs. 32,81,44,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 11—Urban Development.*

That a sum not exceeding *Rs. 57,54,68,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 12—Labour and Employment.*

That a sum not exceeding *Rs. 4,63,31,44,000* for revenue expenditure and *Rs. 1,50,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 13—Social Welfare and Rehablitation.*

That a sum not exceeding *Rs. 21,80,74,000* for revenue expenditure and *Rs. 7,10,03,93,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 14—Food and Supplies.*

That a sum not exceeding *Rs. 9,14,35,00,000* for revenue expenditure and *Rs. 7,12,42,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 15—Irrigation.*

That a sum not exceeding *Rs. 33,63,43,000* for revenue expenditure and *Rs.10,31,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 16—Industries.*

That a sum not exceeding *Rs. 2,31,48,54,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No.17—Agriculture.*

That a sum not exceeding *Rs. 1,03,77,93,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No.18—Animal Husbandry.*

That a sum not exceeding *Rs. 9,83,92,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No.19—Fisheries.*

That a sum not exceeding *Rs. 67,07,65,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 20—Forest.*

That a sum not exceeding *Rs. 93,02,21,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 21—Community Development.*

That a sum not exceeding *Rs. 24,38,15,000* for revenue expenditure and *Rs. 5,09,14,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 22—Co-operation.*

That a sum not exceeding *Rs. 4,70,40,37,000* for revenue expenditure and *Rs. 40,58,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 23—Transport.*

That a sum not exceeding *Rs. 1,60,21,000* for revenue expenditure and *Rs. 3,50,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 24—Tourism.*

That a sum not exceeding *Rs. 3,79,26,10,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 25—Loans and Advances by State government.*

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stand adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 16th March, 2000.

*17.07 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 16th March, 2000).

31841—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY